ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी
# संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

## बिहार में प्रचार शबाब पर

**बिहार** चुनावों के पहले चरण के मतदान में अब दो दिन का ही समय शेष रह गया है और अगले 24 घंटे बाद चुनाव प्रचार भी थम जायेगा अतः सत्तारूढ़ एनडीए व विपक्षी महागठबन्धन ने जमीन पर अपने-अपने स्टार प्रचारकों को उतार रखा है। कहा जा सकता है कि राज्य में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। भाजपा वाले एनडीए के प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संभाल रखी है और गृहमन्त्री अमित शाह भी स्टार प्रचारक हैं, जबकि कांग्रेस वाले महागठबन्धन की तरफ से श्री राहुल गांधी व उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी के अलावा श्री लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार की कमान सौंप रखी है। इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनावी जमीन पर लोगों के मुद्दे तैर रहे हैं जिनका आंकलन करना सामान्यतः असंभव नहीं होता है। ये मुद्दे महंगाई से लेकर बेरोजगारी के हैं जिन्हें विपक्षी महागठबन्धन केन्द्र में रखना चाहता है। इसके साथ ही महागठबन्धन की कोशिश है कि राज्य के विकास का मुद्दा भी केन्द्र में लाया जाये जबकि भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस विकास के मुद्दे के साथ 20 साल पहले के उस लालू राज के मुद्दे को भी जोड़ दिया जाये जिसे वह जंगल राज बता रहा है। चुनावों का यह नियम होता है कि चुनाव वही पार्टी या गठबन्धन जीतता है जिसका विमर्श जमीन पर चलने लगता है।

दोनों ही गठबन्धन एक–दूसरे पर जमकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और दोनों को ही अपने-अपने जातिगत गठबन्धनों पर भरोसा है। मगर चुनावों में यह देखना होता है कि आम जनता कौन सा गठबन्धन बना रही है ? बिहार की जनता या मतदाता राजनैतिक रूप से बहुत सजग माना जाता है क्योंकि मौका पड़ने पर यह जातिगत आग्रहों को उठा कर ताक पर भी रख देता है। महागठबन्धन के नेता कह रहे हैं कि 20 साल से (केवल 17 महीने छोड़कर) बिहार में राज कर रही नीतीश कुमार की सरकार को अब 'अलविदा' कहने का समय आ गया है। मगर सबसे ज्यादा आश्चर्य यह है कि विपक्ष के निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री व जद(यू) नेता श्री नीतीश कुमार नहीं हैं जबकि भाजपा कह रही है कि एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। बेशक नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर महागठबन्धन के नेता कटाक्ष कसने से बाज नहीं आ रहे हैं मगर नीतीश बाबू भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के साथ मिलकर ही नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं अतः इस सरकार के पिछले कार्यकलापों के बारे में हिसाब मांगना लोकतन्त्र में विपक्ष का दायित्व माना जाता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जिसके चलते हर वर्ष लाखों बिहारी देश के अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। हालांकि एनडीए ने अपने घोषणापत्र में आगामी वर्ष में एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है लेकिन विपक्ष इसे सवालों के घेरे में ले रहा है और पूछ रहा है कि पिछले बीस सालों में राज्य में सबसे ज्यादा पांच लाख नौकरियां उन्हीं 17 महीनों की सरकार के दौरान दी गईं जब तेजस्वी बाबू नीतीश सरकार में ही उप मुख्यमन्त्री थे।

> बिहार की जनता या मतदाता राजनैतिक रूप से बहुत सजग माना जाता है क्योंकि मौका पड़ने पर यह जातिगत आग्रहों को उठा कर ताक पर भी रख देता है। महागठबन्धन के नेता कह रहे हैं कि 20 साल से (केवल 17 महीने छोड़कर) बिहार में राज कर रही नीतीश कुमार की सरकार को अब 'अलविदा'' कहने का समय आ गया है। मगर सबसे ज्यादा आश्चर्य यह है कि विपक्ष के निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री व जद(यू) नेता श्री नीतीश कुमार नहीं हैं जबकि भाजपा कह रही है कि एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है।

इस दौरान नीतीश बाबू ने भाजपा का दामन छोड़ दिया था और उन्होंने लालू जी की पार्टी राजद के साथ मिल कर सरकार चलाई थी। वैसे इन दोनों पार्टियों ने 2015 का मिलकर चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तब भाजपा ने अपने दम पर ही 243 सदस्यीय विधानसभा में 52 सीटें प्राप्त की थीं और यह विपक्ष में बैठी थी। खैर अब यह इतिहास की बात हो चुकी है, वर्तमान सन्दर्भों में मुद्दे की बात यह है कि क्या नीतीश बाबू चुनावों में अपने गठबन्धन का बहुमत ले आयेंगे? बिहार की मिट्टी को सूंघ कर हवा का रुख बताने वाले विश्लेषक यह मानते हैं कि इस बार बिहार की जनता निर्णायक फैसला देने जा रही है अर्थात 2020 की तरह यह उहापोह की स्थिति में नहीं रहेगी और एनडीए व महागठबन्धन में से किसी एक को भारी बहुमत देगी। 2020 के चुनावों में एनडीए व महागठबन्धन के कुल वोटों में केवल 12 हजार (0.3 प्रतिशत) का ही अन्तर था। इसके बावजूद नीतीश बाबू के एनडीए को एक दर्जन सीटों की बढ़त मिल गई थी। विश्लेषकों की राय है कि इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसे देखते हुए जमीन पर चुनावी प्रचार का लेखा-जोखा किया जा सकता है। प्रधानमन्त्री समेत एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यदि महागठबन्धन सत्ता में आया तो 20 साल पहले का जंगल राज फिर लौट आयेगा, जबकि विपक्षी महागठबन्धन की दलील है कि यदि एनडीए की सत्ता में वापसी हुई तो नीतीश बाबू को भाजपा मुख्यमन्त्री नहीं बनने देगी और इस पद पर अपने ही किसी दूसरे नेता को बैठायेगी। जाहिर है यह सवाल नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है जिसकी वजह से भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि एनडीए के शासन में यह पद खाली नहीं रहेगा क्योंकि नीतीश बाबू वर्तमान में भी मुख्यमन्त्री हैं और आगे भी रहेंगे। अभी तक विश्लेषक बिहार के जातिगत गणित पर ही चुनावी विजय के आंकड़ों की समीक्षा करते रहे हैं। असलियत यह है कि इस प्रकार के आंकड़े बिहार की प्रबुद्ध जनता के अपमान की तरह होते हैं क्योंकि यह वह जनता है जिसने 1974 में स्व. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विभिन्न राजनैतिक बुराइयों के खिलाफ जन आन्दोलन किया था और जेपी को 'लोकनायक' का दर्जा दिया था। दरअसल चुनावी विश्लेषक भी सरल रास्ता अपनाते हैं और राजनैतिक दलों द्वारा व्याख्यायित विजय आंकड़ें के फेरे में जाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि राजद के पक्ष में मुस्लिम व यादव के कुल 32 प्रतिशत वोट गारंटी शुदा बताये जा रहे हैं और नीतीश बाबू के पक्ष में महादलितों की कुल संख्या। ऐसी गणनाएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। क्योंकि बिहार कबायली राजनीति के दौर से बाहर आने को कुलबुला रहा है। बिहार में युवा बेरोजगारी की दर 10.8 प्रतिशत है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि राज्यभर में केवल एक लाख 35 हजार 464 लोग ही बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं जिनमें से केवल 34 हजार 470 लोग ही स्थायी कर्मचारी हैं। बाकी सब ठेके पर काम करते हैं। बिहार की कुल आबादी साढ़े 13 करोड़ के लगभग है जो कि दो करोड़ 76 लाख परिवारों में बटी हुई है। इन परिवारों में 64 प्रतिशत एसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी दस हजार रु. से भी कम है। केवल चार प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50 हजार रु. मासिक से ऊपर है। इसी से बिहार में गरीबी का आलम मापा जा सकता है। अतःचुनाव प्रचार के तेवर इसी धरातल पर बैठ कर मापे जाने चाहिए। ऐसे में जो भी पार्टी अपना विमर्श जनता के बीच तैरा देगी वही बाजी मार ले जायेगी।

### गौरव का क्षण...

"तुम्हें कौन सा बाहर जाकर कमाना है,
चूल्हा–चौका करके केवल घर ही तो चलाना है,,
लड़कों के खेलों में भला क्यों रुचि दिखाना है,
कौन सा तुम्हें पुरुष खिलाड़ियों के बराबर मिलेगा मेहनताना है,,
इन तानों ने ही तो उन्हें तराश कर हीरा बनाया है,
और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वजह से
आज हर भारतीय के जीवन में यह गौरव का क्षण आया है...!"

गीता पाढा

# शांति का राग और परमाणु परीक्षण !

विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

**एक** पुरानी कहावत है कि आप अपने असली चेहरे को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी यही हुआ है, अभी तक वे शांति का राग कुछ इस तरह अलाप रहे थे जैसे कि उनसे बढ़कर शांति का मसीहा कोई और अब तक पैदा ही नहीं हुआ है लेकिन रूस ने परमाणु संचालित मिसाइल का परीक्षण क्या कर लिया, ट्रम्प ने तो सीधे परमाणु परीक्षण के ही आदेश दे दिए। शांति का राग महज दिखावा साबित हुआ।

ट्रम्प लगातार कहते रहे हैं कि वे दुनिया से अशांति खत्म करना चाहते हैं। वे दावे भी करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्ध खत्म कराए हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। भारत-पाकिस्तान के बीच जंग खत्म कराने का उनका दावा झूठा साबित हुआ। कांगो और रवांडा के बीच भी जंग खत्म नहीं हुई है। मिस्र और इथोपिया के बीच कोई जंग थी ही नहीं, केवल पानी को लेकर कुछ विवाद था। सर्बिया और कोसोवो में तनातनी बनी हुई है।

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद में शांति है लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ लेकिन इजराइल ने फिर भी कई हमले किए हैं। पिछले सप्ताह ही गाजा में सौ से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रम्प इजराइल की तरफदारी कर रहे हैं और हमास ने बात नहीं मानी तो उस पर हमले की चेतावनी भी दे रहे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि ट्रम्प शांति का यह कैसा राग अलाप रहे हैं? इस राग में तो अशांति छिपी नजर आती है।

मगर रूस की एक चाल ने ट्रम्प के राग शांति की पोल खोल कर रख दी। हुआ यह कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित खास तरह की मिसाइल का परीक्षण किया जो करीब 15 घंटे हवा में थी और इस दौरान कई बार उसकी दिशा बदली गई। इस मिसाइल पर परमाणु वार हेड लगाया जा सकता है और यह मिसाइल इतनी चालाक है कि वह हर तरह के रडार को चकमा दे सकती है। यानी ये मिसाइल अचूक है, वैसे तो रूस ने इस तरह की मिसाइल की घोषणा 2018 में ही कर दी थी और 2023 में पुतिन ने इसके परीक्षण की सफलता का दावा भी कर दिया था लेकिन पश्चिम के देशों ने इसे रूस का केवल दावा करार दिया था, अब रूस ने फिर से परीक्षण कर दिया तो अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों, खासकर नाटो की तो जान ही सूख गई। अमेरिका यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हथियारों की होड़ में रूस उससे आगे निकल जाए?

डोनाल्ड ट्रम्प तत्काल मैदान में आ गए और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वार को उन्होंने फिर से परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। लगे हाथ उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार हैं! यह उपलब्धि भी उनके पहले कार्यकाल में हासिल हुई थी। तो सवाल उठता है कि यदि पहले से ही आपके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो फिर नए सिरे से परीक्षण की जरूरत क्या है?

दरअसल सबसे ज्यादा परमाणु हथियार होने का उनका दावा सच के करीब नहीं है। 2022 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया था कि रूस के पास 5977, अमेरिका के पास 5428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 तथा ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 तथा उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। ट्रम्प को यह बात खटक रही होगी कि परमाणु हथियारों के नंबर गेम में वे पुतिन से पीछे क्यों हैं? इसीलिए उन्होंने फिर से परमाणु परीक्षण के आदेश दिए हैं ताकि पहले से भी ज्यादा विनाशक हथियार अमेरिका तैयार कर सके। ट्रम्प यह जानते हैं कि अश्वमेध का जो घोड़ा लेकर वे निकले हैं, उसकी लगाम पुतिन ने पकड़ ली है और ट्रम्प कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वे चाह कर भी यूक्रेन को घातक अमेरिकी मिसाइलें नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पुतिन ने बड़ी साफ धमकी दे रखी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में यदि अमेरिका कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति भी बदल दी है।

> अमेरिका चाहता है कि सबसे ज्यादा परमाणु बम बस उसके पास रहे, बाकी दुनिया के पास न हो ताकि उसकी दादागीरी को चुनौती न मिले।

इस नीति की व्याख्या कुछ इस तरह की जा सकती है कि अमेरिका यदि घातक मिसाइलें यूक्रेन को देता है और उससे रूस पर हमला होता है तो रूस यह मानेगा कि हमले में अमेरिका भी शामिल है।

रूस की नई परमाणु नीति यह भी कहती है कि रूस पर मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले यदि हो रहे हैं तो रूस परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। नीतियों में इस बदलाव के बाद पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। यही कारण है कि ट्रम्प कितनी भी बहादुरी दिखाने की कोशिश करें लेकिन पुतिन के इस फैसले ने उन्हें बगलें झांकने के लिए मजबूर कर दिया है, वैसे यह मान कर चलिए कि मौजूदा हालात में कोई भी देश कभी भी परमाणु हमले की बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। यह केवल डराने और धमकाने का तरीका है, लेकिन इस तरीके ने ट्रम्प के राग शांति की असलियत की पोल खोल कर रख दी है। हथियारों के सौदागर वाला अमेरिकी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने है।

**और अंत में...**

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली तो नहीं है लेकिन चिंतित करने वाली जरूर है। हम सभी यह जानते हैं कि भारतभर की नदियां प्रदूषण का दंश झेल रही हैं लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ज्यादा 54 नदियां महाराष्ट्र की हैं।

राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान संसद की पर्यावरण कमेटी के सदस्य के रूप में हमने नदियों का हाल जानने के लिए व्यापक दौरा किया था और एक रिपोर्ट भी सरकार को दी थी कि नदियां बेहाल हैं तथा शहरों के नाले भी खतरे में हैं, तब से लेकर हालात बहुत नहीं बदले हैं।

महाराष्ट्र की नदियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खासतौर पर ध्यान देना होगा। कहते हैं कि जब एक नदी मरती है तो उस पूरे इलाके के जनजीवन पर गहरा और घातक असर होता है, जो नदियां बची हैं, क्या उन्हें बचाने के लिए हम अपने स्तर पर कुछ कर रहे हैं? सवाल गंभीर है, विचार जरूर कीजिएगा।

# क्रिकेट के आकाश पर छा गई भारत की बेटियां

रोहित माहेश्वरी

**नवी** मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला खेला गया। जिसमें टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने ये करिश्मा करके दिखाया है। जिसका जश्न आज पूरा भारत मना रहा रहा है।

भारत की बेटियों की जय हो। वाह! क्या खेल दिखाया है? क्या जुझारू पारी और एकाग्रता की मिसाल कायम की है? विश्व कप में भारत की बेटियों ने जो खेल खेला है, वह वाकई अद्भुत, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अतुलनीय है! यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। यह आधी आबादी को संबल देने वाली जीत है जो नजीर बन गई उनके लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक फाइनल मुकाबले पर हर किसी की नजरें बनी हुई थीं। 25 साल के विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बार फिर से महिला क्रिकेट टीम के सामने एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इसमें बाजी मारते हुए विश्व विजेता बनकर देश का मान और गौरव बढ़ा दिया है। विमेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 299 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पूरी मेहमान टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई और 52 रनों से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया।

भारत और हम भारतीयों को अपेक्षाएं ही नहीं थीं। हमने महिला क्रिकेट तो क्या, महिला खिलाड़ियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने जो करिश्मा कर दिखाया उसकी बात करना जरूरी जान पड़ता है। असल में वो मैच निर्णायक मैच तो था ही। वहीं उस मैच में मिली जीत ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया था। महिला टीम इंडिया ने 7 बार की विश्व चैम्पियन और लगातार 15 मैचों की अजेय ऑस्ट्रेलिया टीम को पराजित कर विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, वो पल खेल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ग्रुप स्तर पर टीम इंडिया के 330 रनों का सफल चेज कर जीत हासिल की थी। लिहाजा सेमीफाइनल मुकाबले में किसी अतिरिक्त करिश्मे की उम्मीद नहीं थी लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स के रूप में मानो कोई फरिश्ता उतर आया और उसने अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया। जेमिमा को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 'ड्रॉप' किया गया था। जेमिमा की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने नाबाद 127 रन ठोके थे।

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का पहाड़-जैसा लक्ष्य दिया था। जवाब में जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना अपेक्षाकृत कम स्कोर पर आउट हो गए तो भारत की पारी डूबती-सी लगी। उन स्थितियों में जेमिमा ने नाबाद 127 रन (134 गेंद, 14 चौके) बनाकर न केवल विश्व कप का अपना पहला शतक लगाया, बल्कि कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 गेंद पर 89 रन) के साथ तीसरे विकेट की साझेदारी में 167 रन (156 गेंद) बना कर 'पहाड़' की ऊंचाई को एक हद तक कम कर दिया। जेमिमा ने दीप्ति शर्मा के साथ 38 रन (34 गेंद), ऋचा घोष के साथ 46 रन (31 गेंद) और अमनजोत कौर के साथ नाबाद 31 रन (15 गेंद) जोड़े और एक अविश्वसनीय-सी लग रही जीत पर मुहर लगा दी। विश्व कप का यह सबसे बड़ा और सफल चेस रहा।

भारत ने 1978 में पहली बार महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था। 2005 व 2017 में मिताली राज की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, पर दोनों बार ट्रॉफी हाथ से फिसल गई। आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम विश्व विजेता बन गई। महिला टीम की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है। 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पुरुष टीम ने वनडे विश्व कप जीता था। अब हरमनप्रीत कौर की अगुआई में बेटियों ने भी विश्व चैंपियन का तमगा पा लिया। यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 297 रन का स्कोर खड़ा किया जो महिला वनडे विश्व कप फाइनल का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है, जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ट (101) ने शतकीय पारी खेली, पर टीम को जीत नहीं दिला पाईं। महिला टीम की जीत ने 2024 टी-20 विश्व कप की यादें भी ताजा कर दीं, जब रोहित की कप्तानी ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरा टी-20 खिताब जीता था।

दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची। टीम इंडिया ने उनके खेल और हुनर को किसी भी तरह कमतर आंकने के गलती नहीं की। महिला टीम इंडिया 2005 और 2017 में भी फाइनल में पहुंच चुकी है। हमें उस स्तर के तनाव और दबाव का अनुभव हो चुका था। टीम इंडिया ने 2017 विश्व कप में भी, सेमीफाइनल मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया टीम को पराजित किया था। हम यह कई बार साबित कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम 'अजेय' नहीं है। उसे किसी भी दिन, बेहतर खेल के जरिए, पराजित किया जा सकता है। अब भारत की बेटियों ने विश्व कप को जीत कर अपनी प्रतिभा, लगन और मजबूत इरादों का प्रदर्शन कर दिया है। यह प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इसे भारतीय महिला क्रिकेट का उभार भी कहा जा सकता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत है। अब तक पुरुष टीम के मुकाबले महिला क्रिकेट को कम आंका जाता था लेकिन इस जीत ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब बीसीसीआई और राज्य संघ महिला क्रिकेट में अधिक निवेश करेंगे, घरेलू टूर्नामेंट्स को विस्तार मिलेगा और नए प्रायोजक सामने आएंगे। यह ट्रॉफी सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समान अवसर और नए भारत की नारी शक्ति का उदाहरण बन जाएगी।

### हरियाणा कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

# शहीदों के परिवारों को नौकरी, डेली वेजेस और पार्ट टाइम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौत्तरी

**चंडीगढ़,** राजेश जैन (पंजाब केसरी) :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में महत्वपूर्ण छूट प्रदान करने को स्वीकृति दी। इस निर्णय से दो मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी, पहले मामले में जिनमें श्री समीर, युद्ध शहीद सिपाही सतीश कुमार (सेना) के पुत्र, जिनकी 28 दिसंबर, 2001 को 'ऑपरेशन पराक्रम' में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा दूसरे मामले में श्री जंगवीर तक्षक, युद्ध शहीद सिपाही जगदीश (सेना) के पुत्र, जिनकी 26 जुलाई, 2000 को 'ऑपरेशन रक्षक' (जम्मू-कश्मीर) में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार वालों को नौकरी देने के नियम में सरकार ने ढील दी है। पहले नियम था कि शहीद सैनिक के परिवार को तीन साल के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई करना होता था, लेकिन अब अगर किसी वजह से वे तीन साल में अप्लाई नहीं कर पाए, तो भी उन्हें नौकरी मिल सकेगी। इस फैसले से आज दो परिवारों को नौकरी देने की मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही अब डेली वेजेस के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। जिसमें कैटेगरी-1 में काम करने वाले लेवल-1 कर्मचारियों को हर महीने 19,900 रुपए, हर दिन 765 रुपए, या हर घंटे 96 रुपए मिलेंगे। लेवल-2 वालों को महीने के 23,400 रुपए, दिन के 900 रुपए, या घंटे के 113 रुपए मिलेंगे। लेवल-3 वालों को महीने के 24,100 रुपए, दिन के 927 रुपए, या घंटे के 116 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी-2 में लेवल-1 वालों को महीने के 17,550 रुपए, दिन के 675 रुपए, या घंटे के 84 रुपए मिलेंगे।

लेवल-2 वालों को महीने के 21,000 रुपए, दिन के 808 रुपए, या घंटे के 101 रुपए मिलेंगे। लेवल-3 वालों को महीने के 21,700 रुपए, दिन के 835 रुपए, या घंटे के 104 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी-3 में लेवल-1 वालों को महीने के 16,250 रुपए, दिन के 625 रुपए, या घंटे के 78 रुपए मिलेंगे।

# बीरेन सिंह पर आरोप वाली ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई

> न्यायालय में एनएफएसएल का बयान

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गुजरात स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एनएफएसएल) ने इस बात के संकेत दिये हैं कि लीक हुई उस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिनमें राज्य में 2023 की जातीय हिंसा में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित भूमिका की ओर इशारा किया गया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि एनएफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार, ऑडियो क्लिप में संपादन और छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं और ये (क्लिप) आवाजों की फॉरेंसिक जांच के लिए वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त नहीं हैं।

पीठ ने एनएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ''इसलिए, क्लिप में विवादित वक्ताओं की आवाज की समानता अथवा असमानता तथा क्लिप में छेड़छाड़ को लेकर कोई राय नहीं दी जा सकती।'' शीर्ष अदालत 'कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट' (कोहूर) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें इस मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। ट्रस्ट की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एनएफएसएल की रिपोर्ट की एक प्रति पक्षकारों के साथ साझा की जाए, ताकि वे उस पर प्रतिक्रिया दे सकें। पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति पक्षकारों के वकील को सौंपने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई आठ दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।

# बंधक मामले में रोहित आर्य की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू

**मुंबई,** (पंजाब केसरी): मुंबई में 30 अक्टूबर को एक स्टूडियो में 17 बच्चों और दो वयस्कों को बंधक बनाए जाने की घटना के दौरान पुलिस अभियान में गोली लगने से मारे गए सामाजिक उद्यमी रोहित आर्य की मौत के संबंध में अब स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। मजिस्ट्रेट जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा शुरू की गई जांच के साथ जारी रहेगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों को बुलाया जाएगा, बयान दर्ज किए जाएंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

पवई इलाके में महावीर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आर. ए. स्टूडियो में बृहस्पतिवार अपराह्न डेढ़ बजे से शाम सवा पांच बजे के बीच यह घटनाक्रम जारी रहा और अभियान के दौरान आखिरकार बंधकों को बचाया गया तथा आर्य (50) की मौत हो गई।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

# आतंक से मुकाबला

## विजय और सतर्कता

जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने घोषणा की कि भारत में आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है, तो उनके बयान में एक निर्विवाद सत्य और एक सतर्क चुनौती दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, "तथ्य तो तथ्य ही हैं," उन्होंने कहा कि 2013 के बाद से भारत के भीतरी इलाकों में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। दरअसल, एक समय सिलसिलेवार विस्फोटों, सीमा पार से घुसपैठ और विद्रोही हिंसा से आहत देश ने पिछले एक दशक में आंतरिक सुरक्षा का उल्लेखनीय स्तर हासिल कर लिया है। फिर भी, जैसा कि भारत इस उपलब्धि पर उचित गर्व महसूस करता है, यह दावा इस बात पर भी विचार करता है कि उस दुनिया में उन्मूलन का वास्तव में क्या मतलब है जहां आतंकवाद लगातार विकसित हो रहा है - अपने रूपों, उद्देश्यों और तरीकों को बदल रहा है।

भारत की आतंकवाद विरोधी यात्रा लंबी, महंगी और जटिल रही है। 1990 से 2010 के बीच मुंबई से दिल्ली, जयपुर से हैदराबाद तक घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। राज्य की प्रतिक्रिया - मजबूत खुफिया नेटवर्क, विधायी उपकरण और राजनयिक दबाव के संयोजन - ने धीरे-धीरे एक निवारक वास्तुकला का निर्माण किया जो तब से लचीला साबित हुआ है। 2008 में 26/11 के हमलों ने एक क्रूर चेतावनी के रूप में काम किया, जिससे भारत में सुरक्षा की संकल्पना में मौलिक सुधार हुआ।

आज, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राज्य एटीएस इकाइयों और बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक समन्वित संरचना उस सीखने की अवस्था के एक शांत प्रमाण के रूप में खड़ी है। डोभाल का यह दावा कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरा देश सुरक्षित है, एक और वास्तविकता को उजागर करता है - भारत में आतंकवाद तेजी से स्थानीयकृत हो गया है, जो बड़े पैमाने पर कश्मीर की अनूठी राजनीतिक और ऐतिहासिक जटिलताओं के भीतर समाहित है। वहां, उग्रवाद अखिल भारतीय उग्रवाद की अभिव्यक्ति के बजाय सीमा पार छद्म युद्ध का एक साधन बना हुआ है।

जैसा कि डोभाल ने कहा, वामपंथी उग्रवाद का अपने पिछले भौगोलिक प्रसार के 11 प्रतिशत से भी कम तक कम होना एक व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है: सशस्त्र विद्रोह, चाहे वह वैचारिक हो या अलगाववादी, अब उस तरह का क्षेत्रीय या भावनात्मक प्रभाव नहीं रखता है जो पहले हुआ करता था। फिर भी, सुरक्षा विशेषज्ञ अनुपस्थिति को उन्मूलन के साथ जोड़ने के प्रति आगाह करेंगे। बड़े हमलों की कमी का मतलब इरादे या क्षमता का खत्म होना नहीं है। आतंकी नेटवर्क ने साइबर भर्ती, लोन-वुल्फ कट्टरपंथ और वित्तीय घुसपैठ को अपना लिया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश के साथ, आतंकवाद-निरोध में अगला मोर्चा बंदूकों और हथगोले से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम और डिजिटल फायरवॉल से लड़ा जा सकता है। इसलिए, खतरा कम दिखाई देता है लेकिन वास्तविक भी कम नहीं है। इसके अलावा, सुरक्षा केवल हिंसा को रोकना नहीं है, यह नागरिकों के बीच विश्वास, समावेशन और लचीलेपन की खेती भी है।

डोभाल का यह कहना कि प्रत्येक भारतीय को ₹सुरक्षित महसूस करना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मनोवैज्ञानिक आयाम की ओर इशारा करता है। ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक अविश्वास, या ऑनलाइन घृणा अभियान उस ताने-बाने को नष्ट कर सकते हैं जिसकी रक्षा भौतिक सुरक्षा करना चाहती है। आगे की चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि राष्ट्रीय एकता और व्यक्तिगत सुरक्षा एक-दूसरे को मजबूत करें, विरोधाभासी नहीं।

# उत्तर कोरिया का सामरिक पुनराविष्कार

**किम जोंग उन की रणनीतिक दृष्टि की जड़ों को समझने के लिए, उस क्रूसिबल की ओर लौटना होगा जहां से उत्तर कोरिया का जन्म हुआ था। राष्ट्र के संस्थापक, किम इल-सुंग, औपनिवेशिक उत्पीड़न और क्रांतिकारी उथल-पुथल की दोहरी ताकतों से उभरे। वह प्रोटेस्टेंट शिक्षाओं से प्रभावित थे, एक प्रदर्शन जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता की पश्चिमी धारणाओं से परिचित कराया।**

**नीलांत इलांगमुआ**
लेखक, स्तम्भकार हैं।

10 अक्टूबर, 2025 को, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ मनाई - एक संस्था जो एक वैचारिक मोनोलिथ और एक भूराजनीतिक उपकरण दोनों के रूप में विकसित हुई है। उत्सव वफादारी दिखाने से कहीं अधिक थे, वे ताकत, अनुशासन और सहनशक्ति का एक जानबूझकर किया गया दावा थे - एक अनुस्मारक कि उत्तर कोरिया ने आठ दशकों तक बाहरी प्रभुत्व का विरोध किया है, ऐतिहासिक आघात को सहन किया है, और एक ऐसी भू-राजनीतिक पहचान बनाई है जो टकरावपूर्ण और विरोधाभासी रूप से समाधानकारी दोनों है। प्रदर्शन की अध्यक्षता किम जोंग उन कर रहे थे, जो उस वंशवादी वंश में सबसे कम उम्र के थे, जिन्होंने साम्राज्यों को पीछे छोड़ दिया और निरंकुशता को फिर से परिभाषित किया।

उनके बगल में उनकी बहन किम यो जोंग खड़ी थीं, जो अब राज्य मामलों के आयोग में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनकी बढ़ती दृश्यता और तीखी बयानबाजी ने उन्हें प्योंगयांग के कोरियाई प्रायद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य के पुनर्मूल्यांकन में सह-रणनीतिकार के रूप में चिह्नित किया है।

किम जोंग उन की रणनीतिक दृष्टि की जड़ों को समझने के लिए, उस क्रूसिबल की ओर लौटना होगा जहां से उत्तर कोरिया का जन्म हुआ था। राष्ट्र के संस्थापक, किम इल-सुंग, औपनिवेशिक उत्पीड़न और क्रांतिकारी उथल-पुथल की दोहरी ताकतों से उभरे। कोरिया पर जापान के कब्जे के दौरान 1912 में जन्मे, वह प्रोटेस्टेंट शिक्षाओं से प्रभावित थे, एक प्रदर्शन जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता की पश्चिमी धारणाओं से परिचित कराया, बीज जो बाद में जुचे के सिद्धांत में विकसित हुए।

जापानी विरोधी संयुक्त सेना में गुरिल्ला सेनानी के रूप में और बाद में सोवियत समर्थित क्रांतिकारी के रूप में उनके वर्षों ने कठोर विचारधारा के बजाय अनुकूलनशीलता के आसपास उनके विश्वदृष्टिकोण को आकार दिया। पवित्रता नहीं, बल्कि जीवित रहना उनका धर्म बन गया, एक ऐसा गुण जो पीढ़ियों तक उत्तर कोरियाई शासन कला को परिभाषित करेगा। किम इल-सुंग से किम जोंग-इल और फिर 2011 में किम जोंग उन में संक्रमण वंशानुगत निरंतरता से कहीं अधिक दशार्ता है, यह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिष्कार में विकास का प्रतिनिधित्व करता है। स्विट्जरलैंड में शिक्षित, किम जोंग उन पश्चिम की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियों से विशिष्ट रूप से परिचित थे।

इस वैश्विक जागरूकता ने, प्योंगयांग के सत्ता के गलियारों में उनकी कठोर तैयारी के साथ मिलकर, एक ऐसे नेता को तैयार किया जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और घरेलू नाटकीयता दोनों में पारंगत था।

उनके नेतृत्व में, उत्तर कोरिया ने दोहरी रणनीति अपनाई है: परमाणु निवारण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और सतर्क आर्थिक व्यावहारिकता। जो बाहरी लोगों के प्रति आक्रामकता के रूप में प्रकट होता है, वह संक्षेप में, असममित शक्ति का एक परिकलित दावा है। परमाणु शस्त्रागार एक लापरवाह जुआ के रूप में नहीं बल्कि एक तुल्यकारक के रूप में कार्य करता है - एक अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में अस्तित्व संबंधी सुरक्षा। इसे लागू करने वाली उन्नत साइबर क्षमताएं और विशिष्ट विशेष बल हैं जिन्होंने प्योंगयांग को एक बहुआयामी निवारक प्रदान किया है जो इसके आकार या अलग-थलग देशों में शायद ही कभी देखा जाता है। उत्तर कोरिया का भूराजनीतिक पदचिह्न आज इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। चीन और रूस के साथ उसके संबंध गहरे हुए हैं, शीत युद्ध की यादों के कारण नहीं बल्कि साझा रणनीतिक आवश्यकता के कारण।

बीजिंग आर्थिक जीवन रेखाएं और राजनयिक कवर प्रदान करता है, जबकि मॉस्को के हालिया आउटरीच ने व्यापार, ऊर्जा सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को पुनर्जीवित किया है। इस बीच, प्योंगयांग ने वियतनाम और लाओस के साथ चुपचाप संबंध बनाए हैं - ये राष्ट्र समान साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास से बंधे हैं।

प्रतिरोध की साझा स्मृति - संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ वियतनाम का युद्ध, ₹गुप्त युद्ध₹ के दौरान लाओस की तबाही और विदेशी हस्तक्षेप के व्यापक आघात ने वैचारिक सहानुभूति पैदा की है। उत्तर कोरिया ने इस साझी विरासत को कुशलतापूर्वक हथियार बनाकर खुद को लचीलेपन और उत्तर-औपनिवेशिक आत्मनिर्णय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यहां तक कि म्यांमार और कंबोडिया भी ऐतिहासिक एकजुटता और व्यावहारिक जुड़ाव के मिश्रण से आकर्षित होकर इस कक्षा की ओर बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। अपनी सीमाओं के भीतर, किम यो जोंग के उत्थान से किम जोंग उन की सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई है। उनकी भूमिका नेतृत्व में एक विकास को दशार्ती है - जहां वंशवादी वैधता नौकरशाही कौशल के साथ मिलती है। वाशिंगटन और सियोल के प्रति उनके सावधानी से तैयार किए गए बयान, खतरे और कूटनीति के बीच बारी-बारी से संकेत देने में उनकी महारत का पता चलता है जो घरेलू और विदेश दोनों में प्रतिध्वनित होता है।

जैसा कि मेरे अगस्त 2025 के कॉलम द राइज ऑफ किम यो जोंग इन नॉर्थ कोरिया (डेली पायनियर, इंडिया) में बताया गया है, वह शासन की दोहरी प्रकृति-निरंतरता और अनुकूलन का प्रतीक है। उनकी बढ़ती प्रमुखता सत्ता की आधुनिक छवि पेश करते हुए किम राजवंश का भविष्य सुनिश्चित करती है।

फिर भी भव्य परेडों और संगठित एकता के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक आख्यान छिपा है - जो युद्ध, अभाव और अवज्ञा में रचा गया है। कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी बमबारी का आघात राष्ट्रीय मानस में बना हुआ है, जिसने घेराबंदी और अस्तित्व की सामूहिक कहानी को आकार दिया है। जब उत्तर कोरियाई राजनयिक ₹साम्राज्यवादी आक्रामकता₹ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वे वास्तविक ऐतिहासिक स्मृति का आह्वान कर रहे होते हैं, न कि केवल प्रचार में संलग्न होते हैं। यह उपनिवेशवाद-विरोधी ढांचा पूरे वैश्विक दक्षिण में प्रतिध्वनित होता है, जहां राष्ट्र अभी भी बाहरी प्रभुत्व के अवशेषों से जूझ रहे हैं - चुपचाप प्योंगयांग की नरम शक्ति को अप्रत्याशित तरीकों से बढ़ा रहे हैं। आर्थिक रूप से, उत्तर कोरिया अलगाव और अनुकूलन के बीच छाया में काम करता है। प्रतिबंधों के बावजूद, चीन और रूस के साथ व्यापार महत्वपूर्ण जीविका प्रदान करता है, जबकि शासन ने भूमिगत व्यापार नेटवर्क और सीमित भागीदारी विकसित की है जो आवश्यक उद्योगों को बनाए रखती है।

राज्य मीडिया इन मामूली लाभों को ज्यूचे की जीत के रूप में प्रस्तुत करता है, जो घेराबंदी के तहत पनप रहे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की पौराणिक कथा को पुष्ट करता है। वार्षिक सैन्य परेड, मिसाइलों और मशीनरी के सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किए गए प्रदर्शनों के साथ, न केवल मार्शल प्रदर्शन के रूप में बल्कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति की दृश्य पुष्टि के रूप में भी काम करती हैं - अस्तित्व और सरलता का प्रदर्शन।

अस्सी साल की उम्र में, उत्तर कोरिया शीत युद्ध के अवशेष के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्निर्माण में एक केस स्टडी के रूप में खड़ा है। किम राजवंश ने निरंकुशता को एक स्थायी प्रणाली में परिष्कृत किया है, सामरिक लचीलेपन के साथ वैचारिक कठोरता का मिश्रण। किम जोंग उन अपने दादा की क्रांतिकारी प्रवृत्ति और अपने पिता की नाटकीय प्रतिभा को वैश्विक प्रकाशिकी के बारे में आधुनिक जागरूकता के साथ जोड़ते हैं, शक्ति के रूप में धारणा में हेरफेर करते हैं।

किम यो जोंग में, शासन को निरंतरता और नवीनीकरण दोनों मिलते हैं - यह प्रमाण है कि अस्पष्टता में भी, अनुकूलन अस्तित्व सुनिश्चित करता है। आठ दशकों के बाद, उत्तर कोरिया एक अवशेष के रूप में नहीं बल्कि अपने भाग्य के वास्तुकार के रूप में खड़ा है, जो स्मृति, विचारधारा और सटीकता के साथ शक्ति का उपयोग करता है। गुरिल्ला जड़ों से भूराजनीतिक रणनीतिकार तक इसका विकास पुनर्निर्माण की विरासत को रेखांकित करता है जो एशिया के शक्ति संतुलन को आकार देना जारी रखता है।

# नीतीश का बिहार, बिहार के नीतीश

**इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव किए हैं। आज से 20 साल पहले का बिहार नरसंहार , अपहरण और अपराध का पर्याय बन चुका था।**

**सुप्रिया द्विवेदी**
लेखिका, इलाहाबाद विवि में शोधकर्ता हैं।

पिछले बीस साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार का औरा क्या जा चुका है ? या वे फिर से सत्ता के दावेदार बनकर उभरेंगे। कई जगह नीतीश कुमार थके थके नजर आने लगे हैं पर यह थकान सिर्फ उम्र की है या उनके विचार भी थके हुए हैं। विरोधियों का कहना है कि जिस नीतीश के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है उनका चेहरा ही बुझा बुझा है। बाराती नाच रहे हैं दूल्हा चिंता में है। अब यह प्रश्न खुल कर उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी ढो रही है। या नीतीश कुमार बीजेपी को ढो रहे हैं। या बिहार की जनता विकल्पहीनता के कारण थक चुके नेताओं को ढो रही है।

वैसे जितना विरोधी कह रहे हैं नीतीश कुमार उतने थके नहीं है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खराब मौसम का हवाला देकर तेजस्वी यादव पटना से बाहर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इन्हीं दो दिनों में सड़क मार्ग से नीतीश कुमार ने तीन जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करके थकान के मिथक को चुनौती दे दी। नीतीश कुमार सीधे लोगों से मिल रहे हैं। खुद सभा को संबोधित कर रहें हैं। उनकी सभा में महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। ये सारे संकेत नीतीश कुमार के लिए काफी सकारात्मक हैं।

इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव किए हैं। आज से 20 साल पहले का बिहार नरसंहार , अपहरण और अपराध का पर्याय बन चुका था पर नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपराधियों पर लगाम लगाई । उनके दौर में एक भी नरसंहार नहीं हुआ।

नीतीश कुमार ने बिहार से अपराध का पूरी तरह खात्मा कर दिया। नीतीश से पहले बिहार में अपराध संगठित रूप में होते थे। अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था। अब अपराध का वैसा संगठित रूप बिहार में देखने को नहीं मिलता है। अपराध पर लगाम लगाते ही नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण

का दूरगामी प्रयास आरंभ किया। उनसे पहले के दौर में लड़कियों की शिक्षा दर काफी कम थी। नीतीश कुमार ने बालिकाओं के लिए साइकिल योजना का आरंभ किया। जिसके कारण लाखों लड़कियां साइकिल लेकर स्कूल जाने लगी। यह बिहार के सामंती और पितृसत्तात्मक समाज में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव था। आज बिहार के हर सड़क पर साइकिल चलाती लड़कियों को देखा जा सकता है।

बिहार में एक सवाल यह भी तौर रहा है कि क्या बीजेपी को फिर इग्नोर करके चुनाव बाद नीतीश कुमार दूसरी ओर चले जायेंगे। दूसरी ओर चले जाने में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। वो इधर से उधर जाने में बेजोड़ हैं। इधर वाला उन्हें जब तक अपना समझता है तब तक वे उधर वालों के घर में ढूंक जाते हैं। यह कम मजेदार नहीं है कि बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार बीजेपी को काउंटर करते रहते हैं। राजद के साथ रहते हुए राजद को काउंटर करते रहते हैं पर कोई नीतीश कुमार को काउंटर नहीं कर पाता। अपनी कुर्मी जाति के सिर्फ 3 प्रतिशत वोट बैंक के सहारे वे पिछले बीस सालों से बिहार के केंद्र में बने हुए हैं। राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए यह शोध का विषय होना चाहिए।

पिछले चुनाव की तरफ इस बार का चुनाव मुझे एकतरफा नहीं लग रहा है। एक तथ्य यह भी है कि लालू यादव के स्थापित यादव मुस्लिम वोट बैंक में तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए दो लाख नौकरियां देकर युवाओं का अतिरिक्त वोट बैंक जोड़ लिया। जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी पहले से चले आ रहे अपने वोट बैंक में कोई अतिरिक्त वोट नहीं जोड़ पाए। बीजेपी के पास राज्य में एक भी मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है। ये जरूर है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक करोड़ जीविका दीदी के खाते में दस दस हजार रुपए डालकर महिला वोटरों को अपनी तरफ कर लिया है।

फिलहाल इतना तय है कि इस बार का बिहार चुनाव सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि थकान बनाम उम्मीद का चुनाव बन गया है। कुर्सी के इस टैग ऑफ वॉर में एक नए योद्धा प्रशांत किशोर भी जोर लगा रहे हैं । इस चुनाव से उनका राजनीति भविष्य भी तय होगा। चुनाव के आरंभिक दौर से पहले ही प्रशांत किशोर ने बिहार में एक डिस्कोर्स को जन्म दिया। उन्होंने रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाकर सारे दलों को इस बात के लिए विवश किया कि इस बार के चुनाव में मुद्दों की प्रधानता होगी , जाति की नहीं। प्रशांत किशोर जाति के प्रश्न के बजाय विकास के प्रश्न को चुनाव के केंद्र बिंदु में ले आए हैं। यह उनकी राजनीति का एक सकारात्मक पक्ष है। प्रशांत के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए जबकि शराब माफिया पर कोई अंकुश नहीं लग पाया। प्रशांत बिहार में शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं।

नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर ही शराब पर रोक लगाई थी अब प्रशांत किशोर उसे हटाने का वादा कर रहे हैं। ऐसा करके कहीं वो नीतीश कुमार के स्थापित महिला वोट बैंक की मदद तो नहीं कर रहे हैं। अब पूरे देश को बिहार चुनाव के परिणाम का इंतजार है। देखते हैं इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

## आप की बात

### महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत

2 नवंबर 2025 का दिन भारतीय खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वूमेन इन ब्लू ने 47 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म किया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों की ऐतिहासिक परिणति है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने पूरे टूनार्मेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग झ्र तीनों विभागों में खिलाड़ियों ने अनुशासन और जोश का अद्भुत संगम दिखाया। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ियों की जुझारू भावना और आत्मविश्वास ने दशार्या कि अब महिला क्रिकेट किसी भी दृष्टि से पुरुष क्रिकेट से कम नहीं है। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे वैश्विक हस्तियों ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायी क्षण बताया। सुंदर पिचाई ने अपने संदेश में लिखा कि यह मैच 1983 के पुरुष विश्व कप और 2001 की ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला की याद दिलाने वाला रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी महिला टीम की इस सफलता का भरपूर सम्मान किया।

– **विभुक्ति बुपक्या**, दिल्ली, विश्वविद्यालय

### बार-बार एक्सीडेंट या रोड किलिंग

वाहनों की संख्या बढ़ना और सड़कों का संकुचित/खराब होना अथवा अप्रत्यक्ष परवाही /लापरवाही/भूल/चूक दुर्घटना का कारण बन सकता है. किन्तु अब तो बारम्बार कभी जयपुर तो कभी इंदौर और कभी कहीं ओर कभी कार तो कभी डम्पर और कभी ट्रक तो कभी कंटेनर्स लोगों को ऐसे घसीटते ले जाते हैं जैसे ड्राइवर को कुछ दिख ही नहीं रहा हो या वो होश में ही न हो अथवा उसे लगता है जैसे सड़क सपाट है और कोई आसपास लोग या वाहन नहीं है. देखिये न जयपुर में दिनदहाड़े एक ट्रक/डम्पर ने राहगीरों की इतनी गाड़ियों को टक्करें मारी कि ११ लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए. ये कैसी ड्राइविंग है ? इंदौर में रात के समय प्रतिबंधित क्षेत्र में आकर ट्रक ने वाहन चालकों को ऐसा घसीटा कि वे ऑन स्पॉट ही मारे गए. ये हो क्या रहा है? किसकी लापरवाही है ? सड़कें खराब हैं या ड्राइविंग अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी जिम्मेदार विभाग ? एक शहर हो तो बात करें। आजकल तो हर शहर और महानगर की रोज-रोज सड़क दुर्घटनाओं की खबरों से अखबार के पन्ने काले हो रहे हैं और टीवी चैनलों में ये समाचार सुर्खियां बन रहे हैं. लेकिन शासन/प्रशासन के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही है. जनहित में सरकार कुछ तो उपाय करो जिससे सड़क पर बेवजहअकस्मात अकाल मौतें होना रुके।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

### मन चंगा तो कठौती में गंगा

आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई है। मई में गोवा के श्री लायराई देवी मेले में हुई भगदड़, जुलाई में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग नामक एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ और बिहार के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हुई भगदड़ जैसे कितने उदाहरण हम दे सकते हैं? प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में भी भगदड़ मची थी। यह समझ से परे है कि हमारा समाज, जो आमतौर पर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के प्रति उदासीन रहता है, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में इतनी भारी भीड़ कैसे और क्यों जुटा लेता है? सभी सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव और तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण जीवन के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, सभी को अपनी आस्था पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। भक्तों को संत शिरोमणि गुरु रविदास के शब्दों, मन चंगा तो कठौती में गंगा का मूल्य समझना चाहिए। धार्मिक स्थलों के आसपास की संकरी सड़कें, जिनमें रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानों की भीड़, मंदिर प्रबंधन द्वारा गलत अनुमान और योजना का अभाव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का व्यापक उल्लंघन, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं में समन्वय की कमी आदि ऐसी दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हैं। तीर्थस्थल पर किस अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए, यह पंढरपुर की आषाढ़ी यात्रा में भाग लेने वाले वारकरों से सीखने लायक है।

– **संदीप कुमार**, मधुपुर, झारखंड

### धर्मस्थलों पर सावधानी जरूरी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के दिन मची भगदड़ से करीब दस श्रद्धालुओं की मौत होना हमें यही बताता है कि बिना सोचे विचारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की हमारी आदत कभी जाती नहीं है एवं इस तरह की घटनाओं से हम कोई सबक भी नहीं सिखाते हैं,यहां फिर दुख इस बात का भी है कि ये इस वर्ष में लगातार हो रही घटनाओं में से एक है। धार्मिक स्थलों पर बिना जाने समझे हमारी आदत जाती नहीं है एवं इसमें अज्ञानता एवं अंध भक्ति सबसे प्रमुख कारण रहता है। आंध्र प्रदेश में इस वर्ष हुई भगदड़ की लगातार यह दूसरी घटना है, अतः कहा जा सकता है कि न तो मंदिर प्रबंधक हौशियार हो रहे हैं न हीं हमारे धार्मिक श्रद्धालु जन। हमें तो सबसे अधिक दुख तब हुआ था जब प्रयागराज महाकुम्भ में मची भगदड़ में एक साथ काफी श्रद्धालु जनों की दबने से मौत हो गई थी,जो इस वर्ष की सबसे बड़ी दुखद घटना थी, चुंकि भगदड़ की घटनाएं देश की काफी बदनामी भी कराती हैं इसलिए उन्हें रोकने के नए उपाय करना आज बेहद जरूरी हो गये है,ये इसलिए भी जरूरी है कि हाल की इन भगदड़ की घटनाओं से यह साफ है कि अपने देश में भीड़ प्रबंधन के जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं वे निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

**प्रेरणा**

जीवन की असली चमक वहीं है, जहां उम्मीद कभी खत्म न हो। - **हेनरी डेविड थोरो**

**संपादकीय**

## बेटियों की यह जीत नए युग के आगाज का संकेत

**एक** पुरुष-प्रधान देश में जब बेटियां खेल के मैदान में अपना झंडा बुलंद करती हैं तो समाज की बदलती सोच का पता चलता है। महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में साउथ अफ्रीका की अंतिम खिलाड़ी का भारतीय कप्तान द्वारा कैच पकड़ना इस बात का ऐलान था कि आधी आबादी को अबला कहना अब बंद करें। न भूलें कि इन खिलाड़ियों में अधिकांश छोटे शहरों, आदिवासी समुदाय और सामान्य घरों की हैं। यह सच है कि आज भी दर्शकों की रुचि पुरुष क्रिकेट में ज्यादा रहती है। यही कारण है कि महिला क्रिकेट स्पर्धाओं के प्रायोजक भी कम होते हैं, लिहाजा मैचों का सजीव प्रसारण भी पहले नहीं होता था। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के मैदानों पर रणजी ट्राफी चलने से महिला विश्व कप का फाइनल मैच भी वानखेड़े से दूर निजी-स्वामित्व वाले डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ। आने-जाने में कठिनाई के बावजूद दर्शकों की असाधारण भीड़ इस बात का संकेत था कि फैंस ने अब लैंगिक-विभेद बंद कर दिया है। आईसीसी और बीसीसीआई ने भी भारत की बेटियों पर भारी धन-वर्षा करके नए युग के आगाज का संकेत दिया। दूसरे खेलों की पीटी उषा, मल्लेश्वरी, चानू, साक्षी, विनेश, दीपा, दीपिका, सानिया, सिन्धु, नेहवाल, मनु जैसी दर्जनों बेटियां तो पहले ही अनेक स्पर्धाओं में अपनी शक्ति और क्षमता दिखा कर देश की सोच को बदल चुकी हैं।

**जीने की राह**

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com


## भक्त की ओर परमात्मा अपने आप ही चलता है

**ईश्वर** तक जाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सुविधा दी है कि जिस मार्ग में रुचि हो, उससे आओ। किसी ने कहा भी है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा रास्ता था दिल का। और शिव जी ने गरुड़ से कहा कि आपको राम को जानना हो तो काकभुशुंडि जी के पास चले जाओ। और साथ में टिप्पणी कर दी- मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा, किएं जोग तप ग्यान बिरागा। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य से रघुनाथ जी नहीं मिलते। तुम सत्संग के लिए वहां चले जाओ। तो एक तरफ प्रेम है, और दूसरी तरफ योग, तप, ज्ञान, वैराग्य। प्रेम की अद्‌भुत ताकत है। इसे हम इमोशनल स्ट्रेंग्थ कह सकते हैं। सैनिकों को फिजिकल स्ट्रेंग्थ के साथ इमोशनल डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। क्योंकि प्रेम ऐसा अनुशासन है, जिसमें गहराई के साथ स्वीकृति व अपनेपन के साथ स्वतंत्रता होती है। जो प्रेमिल हो गया, उसे भक्त होना आसान है। और जो भक्त हो गया, परमात्मा उसकी ओर आप चलता है।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

**एडवांटेज इंडिया** • हमारी दृढ़ता उन्हें बेचैन करती है

## आखिर ट्रम्प भारत से क्या हासिल करना चाहते हैं?

**स्वायत्तता**

पलकी शर्मा

मैनेजिंग एडिटर FirstPost

X @palkisu


**लाख** टके का सवाल है कि ट्रम्प भारत से चाहते क्या हैं? व्यापारिक सौदा? नोबेल की सिफारिश? राजकीय यात्रा? या महज अटेंशन? कोई नहीं जानता, शायद ट्रम्प भी नहीं। हाल में उनके दक्षिण कोरिया में दिए भाषण से यह साफ भी हो गया। यह कूटनीति के छलावे में मिले-जुले संकेतों, विरोधाभासों और कोरी कल्पनाओं से भरी अदायगी थी। एक सीईओ समिट में बोलते हुए ट्रम्प हमेशा की तरह पटरी से उतर गए। कारोबार की बात करते-करते भू-राजनीति में भटक गए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को दो ऐसी एटमी ताकतें करार दिया, जो 'एक-दूसरे पर टूट पड़ी' थीं। उन्होंने फिर दावा किया कि निजी तौर पर उन्होंने ही दखल देकर दोनों नेताओं को लड़ाई रोकने के लिए मनाया था, और वो भी मात्र दो दिनों में। आत्ममुग्धता से दमकते हुए ट्रम्प बोल उठे- क्या यह गजब नहीं?

गड़बड़ इतनी ही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था! भारत ने साफ किया कि ट्रम्प और मोदी के बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। उस दौरान एकमात्र आधिकारिक सम्पर्क जेडी वेंस से हुआ, जिन्होंने चेताया था कि पाकिस्तान लड़ाई को तूल दे सकता है। मोदी का जवाब दृढ़ था- भारत इसके लिए तैयार है। यानी, ट्रम्प की कहानी कोरी कल्पना थी। वे स्वयं को हीरो साबित करने के लिए ऐसे झूठ गढ़ते रहते हैं।

असल सवाल यह नहीं है कि ट्रम्प अपने तथ्य लाते कहां से हैं। अब तक हम सब जान चुके हैं कि ट्रम्प की दुनिया में तथ्यों की कोई खास अहमियत नहीं है। इससे बड़ा सवाल यह है कि वे अपनी कहानियों में बार-बार भारत को क्यों घसीट लाते हैं। क्यों वे भारत के फैसलों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं या ऐसे नेताओं से दोस्ती का ढोंग करते हैं, जिन्हें वे समझते तक नहीं? इसका जवाब भी ट्रम्प के नजरिए में छिपा है। यह एक विभाजित, सौदेबाजी पर आधारित और बेहद असुरक्षित विश्व-दृष्टि है। उनके लिए हर रिश्ता एक सौदा, हर नेता एक ग्राहक और हर देश या तो उनका साझेदार या फिर समस्या है। ट्रम्प का फलस्फा बहुत सिम्पल है- या तो मेरी चापलूसी करो, मेरे पिछलग्गू बनो या मेरा सामना करने को तैयार हो जाओ।

कुछ जगहों पर उनकी यह नीति कारगर भी रही। जापान अमेरिकी चावल खरीदने को राजी हो गया। ईयू ने सैकड़ों अरब डॉलर के ऊर्जा आयात का वादा किया। कतर ने 240 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। वियतनाम ने टैरिफ शून्य कर दिया। इन सबने यह ट्रम्प-फॉर्मूला सीख लिया है कि खुशामद करो और डील पाओ। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और यही कारण है कि अभी तक ट्रेड डील नहीं हो सकी है।

ट्रम्प की महत्वाकांक्षाएं अब व्यापार से परे जा चुकी हैं। उन्हें अब शांतिदूत बनने का शौक चर्राया है- एक ऐसा नेता, जिसके एक कॉल पर युद्ध समाप्त हो जाएं। भारत-पाक के बीच तनाव घटाने में उनकी कथित भूमिका के लिए पाकिस्तान ने तो उन्हें नोबेल तक के लिए नामित कर दिया। लेकिन भारत ने इस नौटंकी को नजरअंदाज किया। कारण, भारत शांति को आउटसोर्स नहीं करता। और न ही फरेब में दिलचस्पी लेता है।

और यही बात ट्रम्प को बेचैन करती है। वे समझ नहीं पाते कि भारत उनकी 'हां या ना' वाली दुनिया को क्यों नहीं स्वीकारता। ट्रम्प को आज्ञाकारी साझेदार चाहिए, बराबरी से बातें करने वाले नहीं। लेकिन भारत की विदेश नीति स्वायत्तता पर आधारित है। भारत इसे 'मल्टी-अलाइनमेंट' कहता है- बिना किसी के जाल में फंसे, सभी से अच्छे संबध रखना। इस नीति की जड़ें गहरी हैं। तकनीक और रक्षा में भारत अमेरिका से रिश्ते रखता है। रूस से तेल खरीदता है। यूरोप से व्यापारिक

**ट्रम्प के लिए हर रिश्ता एक सौदा, हर नेता एक ग्राहक और हर देश या तो उनका साझेदार या विरोधी है। ट्रम्प का फलस्फा है- या तो मेरी चापलूसी करो या मेरा सामना करने को तैयार हो जाओ। और भारत इससे दृढ़ता से इनकार करता है।**

चर्चा और जापान से साझेदारी रखते हुए भी चीन और इराक से संवाद करता है। यह तटस्थता नहीं, संतुलन है। इसे अनिर्णय नहीं, रणनीति कहते हैं। वास्तव में, भारत कभी भी खेमों में नहीं रहा है- न शीत युद्ध में और ना अब। उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कोई नारा नहीं है, बल्कि एक सबक है- जो उसने औपनिवेशिकता के अनुभवों, पर-निर्भरता के इतिहास और अपनी किस्मत को दूसरों के हवाले कर देने के खतरों से सीखा है। ट्रम्प को समझना होगा कि भारत धमकियों या नाटकीयता पर नहीं, बल्कि तर्क, सम्मान और निरंतरता पर प्रतिक्रिया देता है। लोकतांत्रिक देश इसी तरह से आपस में संवाद करते हैं।

**(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

**विश्लेषण** • डिजिटल सुविधाएं चुनौतियां भी लाती हैं

## साइबर हमलों के मोर्चे पर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है

**डिजिटल**

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर


**एक** डिजिटल ताकत के रूप में भारत के उदय ने समृद्धि, दक्षता और अंतरराष्ट्रीय ख्याति तो दिलाई है, हमें साइबर हमलों का निशाना भी बनाया है। अब जब साइबर हमले हमारे वित्तीय, सैन्य और प्रशासनिक नेटवर्क में सेंध लगा रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का नया दायरा अब सिर्फ जमीन, समुद्र या हवा तक सीमित नहीं रह गया है- यह साइबरस्पेस में भी उतना ही व्यापक है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हर दिन लगभग 17 करोड़ साइबर हमले होते हैं! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की डिजिटल प्रणालियों पर 24 घंटों में 40 करोड़ से ज्यादा हमले किए गए। इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि भारत एक विशाल, अदृश्य युद्धक्षेत्र के केंद्र में है। आधुनिक युग के युद्ध अब टैंकों की गड़गड़ाहट या विमानों की गर्जना से शुरू नहीं होते; वे केबल्स, क्लाउड्स और कोड के जरिए चुपचाप आगे बढ़ते हैं। ऐसे में साइबर योद्धा आज अग्रिम पंक्ति के सैनिक जितने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।

एक डिजिटल राष्ट्र के साइबरस्पेस में सेंधमारी वित्तीय क्षमताओं को पंगु बना सकती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है और एक भी गोली चलने से पहले जनता का विश्वास खत्म कर सकती है। कई साल पहले जब मैं लंदन में रहता था और मेरे पास नकदी नहीं होने के बावजूद डिजिटल कार्ड हर जगह मेरे काम आते थे- राशन खरीदने से लेकर बिजली के बिल चुकाने और परिवहन तक- तो मैं इस स्थिति पर ताज्जुब करता था। लेकिन आज भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है। हम एक समाज के रूप में जुड़े हुए हैं और इंटरनेट की पहुंच सब जगह है। ये हालात सुविधाजनक हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए खतरे भी पैदा करते हैं।

आज साइबर हमले छोटे-मोटे अपराधों से कहीं आगे निकल गए हैं। अब ये किसी हैकर द्वारा त्वरित मुनाफा कमाने के इरादे से नहीं, बल्कि संगठित समूहों, आपराधिक गिरोहों और तेजी से बढ़ते राज्य-प्रायोजित विरोधियों द्वारा भारत की डिजिटल क्षमता की सीमाओं को परखने के इरादे से किए जा रहे हैं। इनके उद्देश्य अलग-अलग हैं- कुछ पैसों के पीछे भागते हैं, कुछ अराजकता की तलाश करते हैं। लेकिन सभी का मकसद डिजिटल इनोवेशन का वैश्विक प्रतीक बन चुके भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करना है।

दुनिया के सॉफ्टवेयर केंद्र, यूपीआई के अग्रदूत और सबसे उन्नत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों में से एक के निर्माता के रूप में भारत के उदय ने न केवल अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, बल्कि उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया है जो हमें कमजोर होते देखना चाहते हैं। आज भारत के यूपीआई सिस्टम, डिजिटल भुगतान नेटवर्क या फिनटेक गेटवे को बाधित करना उसकी विकास-गाथा की नींव पर प्रहार करना है।

स्किनवेयर हमलों ने इस खतरे को चिंतनीय बना दिया है। ये केवल कोड की पंक्तियां नहीं होतीं, बल्कि ये छद्म पहचान और धोखे के सुनियोजित ऑपरेशन हैं, जिनमें साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के लिए विश्वास और अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। तथाकथित डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ऋण प्रस्ताव और पहचान की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि ऐसे कई ऑपरेशन उन्हीं शहरों से जुड़े हैं, जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति प्रदान करते हैं- बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। आपराधिक नेटवर्क में पैर जमाने के लिए सैकड़ों छोटे ऑनलाइन सिस्टम की लगातार जांच या उनमें घुसपैठ की जाती है। विरोधी देशों और आतंकवादी समूहों के लिए इन सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या डिजिटल बाजार में भारत की विश्वसनीयता को कम करना उसे क्षति पहुंचाने का किफायती तरीका है।

एक ओर बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों और भुगतान

**एआई हमारे लिए अवसर और जोखिम दोनों को बढ़ा रहा है। एआई सिस्टम्स विशाल डेटा प्रवाह का विश्लेषण करते हुए तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन चिंतनीय यह है कि वे हमलावरों को भी इतना ही सक्षम बनाते हैं।**

प्रणालियों पर आर्थिक रूप से प्रेरित हमले हैं, जहां एक भी व्यवधान लेनदेन को रोक सकता है और बाजारों में व्यापक दहशत पैदा कर सकता है। दूसरी ओर, देश को चलाने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे- बिजली ग्रिड, हवाई अड्डे, जल नेटवर्क और रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद सबसे घातक वे ऑपरेशन हैं, जिनका उद्देश्य सूचनाओं में हेरफेर करना, झूठे दावे फैलाना या रक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क से संवेदनशील डेटा को चुपचाप चुराना है। ऐसा हर हमला हमारे विश्वास को कम करता है और साइबरस्पेस में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है।

भारत के सामने मौजूद खतरा उसकी डिजिटल सफलता और उसकी विशाल कनेक्टिविटी के अनुपात में है। 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, एक अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शनों और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण हमारे यहां हमले का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**


दैनिक भास्कर — अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।


# © The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

**इस हफ्ते चर्चा में...**

### चिप की कमी से कारों का प्रोडक्शन कम होगा

**13,300 करोड़ रुपए घाटा** हुआ है यूरोपीय कार कंपनी फॉक्सवैगन को तीसरी तिमाही में। दरअसल चिप सप्लाई में कमी से कंपनी का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है।

**180 अमेरिकी कंपनियों ने** इस साल अब तक आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में प्रवेश किया है। यह संख्या पिछले साल 150 थी।

**2.3 लाख करोड़ रु.** की सहायता दी है, 2023 में अमीर देशों ने गरीब देशों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। 2022 से 7% कम है।

**साज सज्जा**

### ट्रम्प ने वॉशरूम में सोने की लाइट्स लगवाईं


ल्यूक ब्राडवाटर


**अमेरिका** के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने सरकारी आवास और दफ्तर व्हाइट हाउस में बदलाव कर रहे हैं। वे ईस्ट विंग को 2660 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दे रहे हैं। ट्रम्प ने बताया कि उन्होंने लिंकन बेडरूम के बाथरूम को नया आकार दिया है। उसमें नए डिजाइन का काला और सफेद संगमरमर लगाया गया है। बाथरूम फिटिंग्स, फॉसेट और लाइट सोने की हैं। व्हाइट हाउस ने नहीं बताया कि रेनोवेशन का खर्च कौन उठा रहा है। कितनी लागत आएगी। ईस्ट विंग के नए निर्माण पर आलोचकों ने सवाल उठाए हैं। पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1945 में बाथरूम में बदलाव किए थे। ट्रम्प बार-बार उनकी स्टाइल की आलोचना करते थे। ट्रम्प का कहना है कि व्हाइट हाउस के कुछ हिस्से पुराने पड़ चुके हैं या बहुत छोटे हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में कई जगह सोने से सजावट करवाई है।

© The New York Times

**ओपिनियन** सार्वजनिक डेटा, इंसानों के एक जैसे पैटर्न से फैसले ले रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

## एआई को अब निजी डेटा की जरूरत नहीं, उसके बिना ही बता रही- नौकरी, लोन पाने का सही उम्मीदवार कौन


मैक्सिमिलियन कैसी


**एआई** अब हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होने लगी है। उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट पर प्राइवेसी सुरक्षित रखते हैं, पर्सनल जानकारी स्वयं तक सीमित रखते हैं, ऑनलाइन राय जाहिर करने से बचते हैं या एप्स और वेबसाइट को अपनी निगरानी से रोक रखा है। आपके बारे में थोड़ी भी जानकारी होने पर एआई बता सकती है कि आप अच्छे से काम करेंगे या नहीं, कैसा बर्ताव करेंगे। एआई आप जैसे अन्य लोगों की जानकारी के बूते यह सब बता सकती है। इस पैटर्न के आधार पर अब लोगों के संबंध में अहम फैसले होने लगे हैं।

एआई ने काफी कुछ बदल दिया है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम-अल्गोरिदम से बैंक फैसला कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को लोन दिया जाए। पुलिस ने भावी कार्रवाई के लिए अल्गोरिदम में अपराधों का रिकॉर्ड बना रखा है। कल्पना कीजिए आपने किसी जॉब के लिए अर्जी दे रखी है। आप स्वयं को बेहद काबिल मानते हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल तक नहीं आता है। आवेदकों की छानबीन में इस्तेमाल होने वाला एआई प्रोग्राम बता सकता है कि आप कंपनी के कल्चर में फिट नहीं बैठेंगे। वह आपके व्यवहार से बाद में होने वाले विवाद के संकेत देगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे क्लिक के आधार पर निर्णय करते हैं कि हम कौन सी खबर, गलत जानकारी या प्रोपेगंडा पसंद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि डेटा प्राइवेट रखने से हम अवांछित नतीजों से बच सकते हैं। लेकिन, एआई को जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं। उसे सिर्फ इतना जानना है कि आप जैसे लोगों ने पहले क्या किया है। इसलिए प्राइवेसी किसी एक व्यक्ति को अब सुरक्षित नहीं रख सकती है। हमें अपने पूरे डेटा पर सामूहिक नियंत्रण रखने की जरूरत है।

2000 के दशक में डिजिटल प्राइवेसी पर चिंता के बीच कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने डिफरेंशियल प्राइवेसी नामक सुरक्षा ढांचा बनाया था। इसके तहत यूजर्स के पैटर्न को जानने के वास्ते पहचान सुरक्षित रखते हुए डेटा जुटाया जाता है। डिफरेंशिल प्राइवेसी अल्गोरिदम बेतरतीब तरीके से डेटा जुटाते हैं। पता नहीं लगता कि डेटा किसका है। इन अल्गोरिदम पर एपल के आईफोन बने हैं। ये यूजर के व्यवहार और ट्रेंड की जानकारी देते हैं। ये भी नहीं बताते कि डेटा किसके फोन का है। © The New York Times

**नए सिस्टम बहुत कुछ कर सकते हैं**

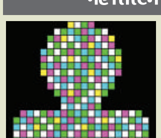

- एआई से यूजर के व्यवहार और ट्रेंड की जानकारी मिलती है।
- व्यक्ति को जाने बिना उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है।
- लोगों की पात्रता और योग्यता तक मशीन से तय होने लगी है।
- निजी प्राइवेसी की बजाय सामूहिक सुरक्षा से बचाव संभव।

### अब एआई अल्गोरिदम बताएंगे किस जगह मिल सकते हैं इमिग्रेंट्स

टेक्नोलॉजी कंपनी पलनटिर कई डेटा स्रोतों के विश्लेषण से लोगों की पहचान करने वाले एआई सिस्टम बना रही है। इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकालने के लिए इसका उपयोग होगा। किसी एक व्यक्ति को जाने बिना ही अल्गोरिदम उन बस्तियों, कार्यस्थलों और स्कूल, कॉलेजों की जानकारी देंगे, जहां अवैध इमिग्रेंट्स मिल सकते हैं। लैवेंडर और व्हेअर इज डैडी जैसे एआई अल्गोरिदम का इस्तेमाल इजराइली सेना ने गाजा में बमबारी के लिए किया है।

### लोगों की प्रसन्नता, नौकरी और जिंदगी तक छीन जाने का खतरा

हर किसी का डेटा शेयर कर एआई से समाज में बदलाव लाना संभव है। लेकिन एआई के लक्ष्यों से सबका सहमत होना जरूरी है। अल्गोरिदम के फैसलों से लोगों की नौकरी, प्रसन्नता, आजादी या जिंदगी का छिनना ठीक नहीं होगा। सामूहिक नुकसान से बचने के लिए एआई नियंत्रण के कानून और संस्थाएं बनाना जरूरी है। एआई का भविष्य स्मार्ट अल्गोरिदम या तेज चिप्स तय नहीं करें। बल्कि यह तो जनता के हाथ में होना चाहिए।

**सोसायटी**

### दो दशकों में अमेरिका में तीन लाख बाल विवाह हुए


निकोलस क्रिस्टोफ


सिएरा लिओन, कोलंबिया जैसे छोटे देशों ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन अमेरिका के 34 राज्यों में यह प्रथा कानूनी है। हर साल औसतन 15 हजार से अधिक बाल विवाह होते हैं। अमेरिका में बाल विवाह पर पाबंदी सबसे पहले डेलावेयर राज्य ने लगाई थी। उसके बाद 15 अन्य राज्यों ने रोक लगा दी। नेवादा, फ्लोरिडा जैसे कुछ राज्यों में बाल विवाह की न्यूनतम आयु 17 साल है। कुछ अन्य में 16 वर्ष है। हवाई और कंसास में 15 है। कैलिफोर्निया, मिसीसिपी, न्यू मैक्सिको और ओकलाहोमा में कोई न्यूनतम आयु नहीं है। वहां एक पैरेंट या एक जज की स्वीकृति काफी है। एक स्वयंसेवी संगठन अनचेंड एट लास्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2021 के बीच अमेरिका में 18 साल से कम आयु के तीन लाख 14 हजार लोगों का बाल विवाह हुआ है। इनमें 86 प्रतिशत लड़कियां थीं। उनका विवाह अपने से औसतन चार साल बड़े पुरुषों से हुआ। अधिकतर नाबालिगों की आयु 16-17 साल थी। कुछ लड़कियों की तो दस साल में शादी कर दी गई। कुछ राज्यों में विरोधाभासी स्थितियां हैं। विवाह की अनुमति है लेकिन यदि कोई नाबालिग है तो पति और पत्नी के बीच यौन संबंध अपराध है। अमेरिका में 2021 में औसतन हर दिन चार या पांच बच्चों का विवाह हो रहा था। © The New York Times

**बिजनेस** अफ्रीका में फसल खराब होने से अमेरिकी कंपनियों पर असर

## कोका के दाम उछलने से चॉकलेट में बढ़ने लगी शुगर


क्लेअर ब्राउन


**अमेरिका** में कई चॉकलेट निर्माताओं को स्वाद बनाए रखने के लिए नए तरीके अपनाना पड़े हैं। लोगों को चॉकलेट का जाना-पहचाना स्वाद नहीं मिल रहा है। कोका की कमी से ऐसा हुआ है। पश्चिम अफ्रीकी देशों में सूखे से कोका की फसल चौपट होने से उसके मूल्य आसमान पर हैं। चॉकलेट कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने के साथ प्रोडक्ट में कोका की मात्रा कम कर दी है। कोका की जगह शुगर कंटेंट में बढ़ोतरी हो रही है।

ऑलमंड जॉय, मिस्टर गुडबार, रोलो जैसी चॉकलेट की पैकेजिंग से मिल्क चॉकलेट जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। मिस्टर गुडबार के रैपर पर मिल्क चॉकलेट्स पीनट्स के बजाय चॉकलेट कैंडी पीनट्स लिखा जाता है। ऑलमंड जॉय की मार्केटिंग कोकोनट एंड ऑलमंड चॉकलेट कैंडी बार के नाम से होती है। रोलो पर मिल्क चॉकलेट की जगह रिच चॉकलेट कैंडी लिखा रहता है।

कुछ कंपनियां कोका बटर की जगह अन्य फैट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके प्रोडक्ट अब अमेरिकी नियमों की परिभाषा में मिल्क चॉकलेट नहीं हैं। लिहाजा, मिल्क चॉकलेट अब चॉकलेट कैंडी बन गई है। पिछले दस साल से पश्चिम अफ्रीका के कोका उत्पादक क्षेत्रों में हर वर्ष भीषण गर्मी छह हफ्ते बढ़ गई है।

कुछ कंपनियों को कच्चा माल बेचने वाली कंपनी कारगिल के वाइस प्रेसिडेंट जॉन सटुम्बा ने बताया कि चॉकलेट के विकल्पों में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। कारगिल कम कोका का उपयोग करने वाली कोटिंग, फिलिंग बनाने के लिए नीदरलैंड्स में एक फैक्ट्री बना रही है। कृषि कंपनी एक्सपाना में कोका एनालिस्ट एंड्रयू मोरिआर्टी का कहना है, कंपनियों ने पिछले दस वर्षों में शुगर में कटौती की थी। लेकिन कोका के स्थान पर शुगर कंटेंट बढ़ रहा है। विश्लेषक कहते हैं, गर्मी बढ़ने से कोका की सप्लाई कम होती जाएगी। © The New York Times

**कोका के मूल्य चार गुना बढ़े**

लुई फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले साल के अंत में कोका के मूल्य 8.87 लाख रु. प्रति टन हो गए थे। यह 2022 के मुकाबले चार गुना अधिक है। विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि पैसा बचाने के लिए कोका की मात्रा में कमी की गई है। कंपनियां रेसिपी में बदलाव पर कुछ नहीं बोलती हैं।

**कार्रवाई** वकीलों, अटॉर्नियों की संख्या घटी

## अपने खिलाफ मुकदमे चलाने वाले वकीलों को बर्खास्त या डिमोट कर रहे हैं ट्रम्प


एलन फ्यूएर


**अमेरिका** के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दाखिल करने वाले वकील और अफसर मुश्किल में हैं। इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी वॉशिंगटन के अटॉर्नी ऑफिस पर पड़ा है। वहां कई वकील इस्तीफा दे चुके हैं। लगभग बीस साल से कार्यरत सीनियर प्रोसीक्यूटर जॉन हुक्स को निकाल दिया गया है। ट्रम्प द्वारा नियुक्त वॉशिंगटन अटॉर्नी ऑफिस की प्रमुख जीनाइन पिरो के सहायक जोनाथन होरनॉक ने निष्कासन का आदेश जारी किया।

हुक्स को निकालने का आदेश उस वक्त जारी हुआ जब उनके कुछ साथियों की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और वर्जीनिया सहित कई राज्यों के फेडरल प्रोसीक्यूटर ऑफिस ट्रम्प के कोप का शिकार बने हैं। ट्रम्प उन लोगों से चुन-चुनकर बदला ले रहे हैं, जिन्होंने उनके व सहयोगियों के खिलाफ मामले पेश किए हैं। वॉशिंगटन अटॉर्नी ऑफिस में कई लोग निकाले गए हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कुछ को डिमोट किया गया है। ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के बाद ऑफिस में वकीलों, अटॉर्नी सहित कर्मचारियों की संख्या एक तिहाई कम हो गई है। पिछले सप्ताह दो प्रोसीक्यूटर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया। इन्होंने 6 जनवरी 2021 के संसद पर उपद्रव करने वाले ट्रम्प समर्थक एक दंगाई को कड़ी सजा देने की सिफारिश की थी। ट्रम्प ने सभी दंगाइयों को माफ कर दिया था। © The New York Times


https://t.me/AllNewsPaperPaid

## महिलाओं की दुनिया

### विश्व कप में जीत मैदान पर लंबे संघर्ष के बाद मिली।

एक जादुई रविवार की आधी रात को, हरमनप्रीत कौर और उनकी अद्भुत महिलाओं ने नियति से मुलाक़ात की। भारत को अंततः महिला क्रिकेट में विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया। यह एक ऐसा सफ़र था जो चिंता और खुशी के लंबे इतिहास से जुड़ा था, जिसे शांता रंगास्वामी, डायना एडुल्जी, मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी अग्रदूतों के पसीने और सपनों ने आकार दिया था। आईसीसी विश्व कप के एक बेहद अहम मुकाबले में, भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया, जो ज़ोरदार ऊर्जा से भरपूर स्टेडियम में बदल गया।

यह क्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1983 में कपिल देव और उनकी टीम के लिए था, जब उन्होंने लॉर्ड्स में विश्व कप जीता था। इसने क्रिकेट की धारणा और संचालन के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला दिया और भारत के लिए एक व्यावसायिक महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। हरमनप्रीत और उनकी टीम, और महिला क्रिकेट, दोनों के लिए भी कुछ ऐसा ही मोड़ आने वाला है। कोच अमोल मजूमदार का भी अपना समय था। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज होने के बावजूद, उन्हें कभी सीनियर पुरुष टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका करियर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ-साथ चला। हरमनप्रीत की जोशीली महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि उनके गुरु को अंततः समझ में आ जाए कि उच्चतम स्तर पर सफलता का क्या मतलब है।

2005 और 2017 के विश्व कप फाइनल में लड़खड़ाने के बाद, भारत को घर पर खेलने के दबाव से भी जूझना पड़ा। जब दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन लीग मैच हार गए, तो सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। फिर भी, टीम डटी रही और हर खेल ने एक नया सितारा दिया - उदाहरण के लिए प्रतीक रावल। फाइनल में, शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन किया, जबकि स्मृति मंधाना हमेशा की तरह ठोस थीं। इससे पहले, गौरव की ओर मोड़ सेमीफाइनल में हुआ जब जे-मिमाह रोड्रिग्स ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आश्चर्यजनक पीछा किया। उनकी नाबाद 127 रन की पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक है। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के रूप में प्रोटियाज के पास एक शानदार बल्लेबाज है और सेमीफाइनल तथा फाइनल में उनके द्वारा लगाए गए दो शतक उच्च स्तरीय तथा जुझारूपन वाले थे।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय महिलाओं ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बना ली है।

## केरल की एक कहानी

### गरीबी उन्मूलन को एक कभी न खत्म होने वाले कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए

कश्मीर एराला, अपने अनुकरणीय रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है सामाजिक और मानव विकास, और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ उन लोगों के बराबर हैं विकसित देशों के इस समूह ने 1 नवंबर को अपने 69वें स्थापना दिवस पर एक और उपलब्धि हासिल की - अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन। यह चार साल के, सावधानीपूर्वक नियोजित कार्यक्रम का परिणाम था, जिसमें व्यापक सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन विभाग की अगुवाई में कई एजेंसियां शामिल थीं। मई 2021 में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली दूसरी एलडीएफ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी) शुरू किया गया था। केरल के जन-केंद्रित विकास और विकेन्द्रीकृत योजना के लिए उत्तरवर्ती राज्य सरकारें श्रेय की पात्र हैं, जिसने यह सुनिश्चित किया कि गरीबी 1973-74 में 59.8% से घटकर 2011-12 में 11.3% हो जाए। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2023) में कहा गया है कि जनसंख्या अनुपात के आधार पर केरल सबसे कम गरीब राज्य था। केरल की मात्र 0.55% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब थी - जो राष्ट्रीय औसत 14.96% से काफी कम है। स्व-नामांकन पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार ने अत्यंत गरीबों की पहचान करने के लिए एक मजबूत स्थानीय निकाय प्रणाली और कुडुम्बश्री कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित लगभग 4 लाख प्रशिक्षित गणनाकारों को तैनात किया। कई स्तरों की जांच के बाद, 64,006 अत्यंत गरीब परिवारों - जिनमें 1,03,099 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से कई के पास बुनियादी दस्तावेज नहीं थे - की पहचान भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका के साधन और आवास तक पहुंच के चार सूत्री मानदंडों के आधार पर की गई। ऐसी विविध आवश्यकताओं के लिए एक समान समाधान अपर्याप्त था, जिससे कल्याणकारी शासन में एक प्रयोग आवश्यक हो गया: प्रत्येक पहचाने गए परिवार के लिए कस्टम-मेड माइक्रो प्लान की तैयारी और आवश्यक समर्थन का प्रावधान जैसे पहचान दस्तावेज, आवास, आजीविका, नियमित दवा, पका हुआ भोजन, उपशामक देखभाल और कुछ मामलों में, अंग प्रत्यारोपण।

गरीबी से लड़ना एक अंतहीन काम है और अत्यधिक गरीबी को मिटाने के दावे की आलोचना, खासकर आदिवासी आबादी की दुर्दशा के संदर्भ में, अपरिहार्य है। राज्य सरकार ने गरीबी की पुनरावृत्ति को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नया परिवार अत्यधिक गरीबी में न गिरे, ईपीईपी 2.0 शुरू किया है। एलडीएफ ने मिशन मोड में गरीबी के सभी रूपों से निपटने का संकल्प लिया है। 'केरल मॉडल' के आलोचकों ने अक्सर स्थिर विकास और बढ़ती बेरोजगारी को इसकी कथित विफलता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। राज्य ने इन क्षेत्रों में कमी को पाटने के लिए प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और उच्च तकनीक वाले हरित उद्योगों को गति दी है। यह बेरोजगारी को कम करने के लिए शिक्षित लोगों को कौशल भी प्रदान कर रहा है। ईपीईपी दर्शाता है कि प्रगतिशील शासन सामाजिक सुरक्षा या स्थिरता से समझौता किए बिना, कल्याणवाद और विकास में एक साथ निहित हो सकता है। बड़े पैमाने पर समुदाय-संचालित मॉडल भले ही अपूर्ण न हो, लेकिन यह स्वतः विकसित होता है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह एक वैकल्पिक विकास योजना प्रस्तुत करता है - एक केरल की कहानी जो प्रचारित करने लायक है।

# भारत का आईटी सपना दोराहे पर है

शशि थरूर
के सदस्य
संसद के लिए
तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में
लोकसभा और
अध्यक्ष महोदय,
संसदीय
स्थायी समिति
बाहरी वायु पर

लगभग तीन दशकों से भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का मुकुट रत्न रहा है—जो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, वैश्विक प्रासंगिकता और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हालाँकि आईटी उद्योग भारतीय कार्यबल का केवल लगभग 1% ही नियुक्त करता है, लेकिन यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान देता है। छोटे शहरों के युवा इंजीनियर कभी इन्फोसिस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में नौकरी को समृद्धि का पासपोर्ट मानते थे। लेकिन आज, वह सपना धूमिल होता जा रहा है। टीसीएस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा—एक ही तिमाही में लगभग 20,000 नौकरियाँ—और अन्य कंपनियों द्वारा चुपचाप उसका अनुसरण करने के साथ, यह सवाल उठता है: क्या आईटी अब महत्वाकांक्षी तकनीकी पेशेवरों के लिए सोने का बछड़ा नहीं रहा?

एक गहरा कायापलट: इसका जवाब जटिल है।
भारत का आईटी क्षेत्र ढह नहीं रहा है, बल्कि एक गहरे कायापलट से गुज़र रहा है — जिसके लिए तत्काल ध्यान, रणनीतिक पुनर्संतुलन और भविष्य के लिए तैयार कौशल के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। 'लायो वेव' उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तन का एक लक्षण है। यह अमेरिका में भी हो रहा है: अमेज़न ने घोषणा की है कि वह एआई के इस्तेमाल के कारण अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या में 14,000 की कमी करेगा।

मेटा 8,000 लोगों की छंटनी कर रही है। भारत में, टीसीएस द्वारा अपने कर्मचारियों की संख्या में 3.2% की कटौती करने का निर्णय, जो मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर की नौकरियों को लक्षित करता है, कोई अलग घटना नहीं है: अन्य आईटी कंपनियाँ भी ऐसा ही कर रही हैं।
उद्योग जगत के अनुमान बताते हैं कि इस साल के अंत तक 50,000 से ज़्यादा आईटी नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि ये पारंपरिक अर्थों में सामूहिक छंटनी नहीं, बल्कि 'साइलेंट लेओस' होंगे - प्रदर्शन से जुड़ी छंटनी, स्वैच्छिक इस्तीफे, और विलंबित पदोन्नति जो बिना सुर्खियाँ बटोरे चुपचाप कर्मचारियों की संख्या कम कर देती हैं।

इसके कई कारण हैं। पहला, एआई-संचालित स्वचालन आईटी कार्य की प्रकृति को ही बदल रहा है। नियमित कार्य - रिपोर्टिंग, समन्वय, बुनियादी कोडिंग - अब एल्गोरिदम द्वारा अधिकाधिक संभाले जा रहे हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के मॉडलों के आगमन के साथ-साथ एजेंटिक एआई - तर्क करने और बहु-चरणीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम स्वायत्त प्रणालियाँ - के उदय ने भारत के आईटी सेवा क्षेत्र में बुनियादी बदलाव ला दिया है। यह नियमित कार्यों को स्वचालित कर रहा है, डेवलपर उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार ला रहा है, और उद्योग का ध्यान उच्च-मूल्य वाले, एआई-संचालित डिजिटल परिवर्तन की ओर स्थानांतरित कर रहा है। हालाँकि एआई कभी भी मनुष्यों की सहानुभूति या भावना की क्षमता की नकल नहीं कर सकता, लेकिन इन कार्यों के लिए ऐसे गुणों की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता है।

दूसरा, अमेरिकी आव्रजन नीतियों में वृद्धि हुई है
एच-1बी वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी और टैरिफ की धमकियों के कारण भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को विदेशों में ही भेजने पर मजबूर हो रही हैं, जिससे प्रतिबंध और बढ़ गए हैं। भारतीय आईटी कंपनियां कम वेतन वाली नौकरी पाने के लिए 1,00,000 डॉलर का भुगतान नहीं कर सकतीं।

भारतीय आईटी की कहानी खत्म नहीं हो रही है - यह विकसित हो रही है। यह बदलाव निस्संदेह कष्टदायक होगा। लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण भी हो सकता है।

मध्य स्तर के पेशेवर को अमेरिका में ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए भेजा गया, जिनसे इतना अधिक लाभ नहीं होगा।
तीसरा, ग्राहकों का बजट कड़ा होता जा रहा है, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, जहाँ आर्थिक अनिश्चितता के कारण आईटी खर्च में सावधानी बरती जा रही है। संक्षेप में, आउटसोर्सिंग मॉडल, जो कभी पैमाने और लागत अंतर पर निर्भर था, अब एक ऐसे मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो विशिष्ट विशेषज्ञता, कमज़ोर टीमों और एआई दक्षता को महत्व देता है।

असेंबली लाइन का अंत: भारत का आईटी क्षेत्र एक साधारण से वादे पर खड़ा किया गया था: हज़ारों इंजीनियरों को नियुक्त करना, उन्हें बुनियादी कोडिंग का प्रशिक्षण देना और उन्हें वैश्विक ग्राहकों की सेवा के लिए तैनात करना। यह एक डिजिटल असेंबली लाइन थी—कुशल, स्केलेबल और पोर्टेबल। लेकिन वह मॉडल अब—सीधे शब्दों में कहें तो—पुराना हो चुका है।

आज के ग्राहक कोडर्स की सेना नहीं चाहते हैं; वे समाधान चाहते हैं। वे क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, और जनरेटिव AI इंटीग्रेशन चाहते हैं। वे कम लोग चाहते हैं जो ज़्यादा काम कर सकें। और वे उन्हें तेज़ चाहते हैं। इस बदलाव ने भारतीय आईटी कार्यबल में कौशल की असमानता को उजागर किया है। कई मध्य-करियर पेशेवर, जिन्हें तकनीकी गहराई के बजाय प्रबंधकीय क्षमता के लिए पदोन्नत किया गया था, अब खुद को नई मांगों के लिए अयोग्य पाते हैं। विरासत कौशल - SAP ECC, मेनफ्रेम, गैर-क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म - कम प्रासंगिक हैं। केवल एक उदाहरण लेते हैं: SAP ECC (SAP ERP सेंट्रल कंपोनेंट) SAP के पारंपरिक एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ़्टवेयर सूट का मूल है, वह डिजिटल रीढ़ जो बड़े संगठनों को विभागों में अपने दैनिक व्यावसायिक संचालन का प्रबंधन करने में मदद करती है। आज AI इसे संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल की नकल कर सकता है।

आईटी प्रोफेशनल के लिए उस घटक में महारत अब उतनी ज़रूरी नहीं रही। सवाल उठता है: हाँ, लेकिन आप और क्या कर सकते हैं?

इसका नतीजा एक दर्दनाक उथल-पुथल है: अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, नए स्नातकों को प्रवेश के अवसर ढूँढ़ने में मुश्किल हो रही है, और कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस तेज़ तकनीकी बदलाव को देखते हुए, सरकार को बड़े पैमाने पर छंटनी करने वाली आईटी कंपनियों को मुआवज़े के पैकेज के रूप में अनिवार्य रूप से 6-9 महीने का वेतन देने पर विचार करना चाहिए, जिससे अचानक अपनी आजीविका खोने वाले और बदलते रोज़गार बाज़ार के लिए नए कौशल हासिल करने की ज़रूरत वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके।

फिर भी, हमारे आईटी क्षेत्र के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भारत की तकनीकी दक्षता अभी भी वैश्विक सम्मान का पात्र है। यह अर्थव्यवस्था में 280 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देता है, लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार देता है और विभिन्न उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन को गति प्रदान करता है। लेकिन सफलता की गारंटी की चमक—यह विचार कि एक तकनीकी डिग्री एक स्थिर करियर के बराबर है—धुंधला रही है। युवा पेशेवरों के लिए, रास्ता अब सीधा नहीं रहा।

कंप्यूटर साइंस की डिग्री ही काफी नहीं है। एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल करनी होगी और सीखते रहना होगा। बुनियादी जावा या .NET (या यहां तक कि SAP ECC) पर निर्भर रहने की परंपरा खत्म हो गई है।

छंटनी से लेकर पुनर्आविष्कार तक तो, हम क्या कर सकते हैं? अगर भारत अपनी आईटी बढ़त बरकरार रखना चाहता है, तो उसे कई मोर्चों पर काम करना होगा। नीति निर्माताओं के लिए, चुनौती कौशल विकास की पुनर्कल्पना करना है। भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव करने होंगे। सरकारी कार्यक्रमों को केवल डिजिटल साक्षरता ही नहीं, बल्कि एआई साक्षरता को भी प्रोत्साहित करना होगा। और उद्योग जगत को केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि पुनर्कौशल विकास में भी निवेश करना होगा।

पहला स्पष्ट कार्य बहुत बड़े पैमाने पर एआई 'अपस्किलिंग' है। टीसीएस पहले ही 5,50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को बुनियादी एआई कौशल और 1,00,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को उन्नत कौशल प्रदान कर चुकी है। इसे अपवाद नहीं, बल्कि एक आदर्श बनना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस प्रयास को गति दे सकती है।

इसके साथ ही, पाठ्यक्रम में तत्काल सुधार की भी आवश्यकता है। इंजीनियरिंग शिक्षा को रटंत कोडिंग से आगे बढ़ना होगा।

मशीन लर्निंग, एआई में नैतिकता और उत्पाद चिंतन जैसे पाठ्यक्रम मुख्यधारा में होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स—संचार, सहयोग, आलोचनात्मक सोच—भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सरकार और वेंचर कैपिटलिस्टों से और अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। भारत का तकनीकी भविष्य केवल सेवाओं में ही नहीं, बल्कि उत्पादों में भी निहित है। एआई स्टार्टअप्स, डीप-टेक वेंचर्स और इनोवेशन हब्स को समर्थन देने से नए रोज़गार सृजित हो सकते हैं और इस क्षेत्र में विविधता आ सकती है। सरकार को वीज़ा पहुँच, डेटा संप्रभुता और व्यापार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ जुड़ना चाहिए। विदेशों में संरक्षणवाद को घरेलू स्तर पर नीतिगत स्पष्टता के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

मौजूदा उथल-पुथल में नौकरी से निकाले गए या विस्थापित हुए लोगों के लिए, सेवानिवृत्ति भत्ता पर्याप्त नहीं है। उन्हें करियर परिवर्तन सहायता, मानसिक स्वास्थ्य संसाधन और पुनर्प्रशिक्षण सब्सिडी की आवश्यकता होगी। भारतीय आईटी उद्योग को पहले कभी सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके लिए समय आ गया है।

भारतीय आईटी की कहानी खत्म नहीं हो रही है — यह विकसित हो रही है। मानवशक्ति से लेकर मानसिक शक्ति तक, आउटसोर्सिंग से लेकर नवाचार तक, मात्रा से लेकर गुणवत्ता तक, यह बदलाव चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन अपरिहार्य भी। यह बदलाव निस्संदेह कष्टदायक होगा। लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण भी हो सकता है।

हमें सफलता का आकलन सिर्फ़ कर्मचारियों की संख्या से नहीं करना चाहिए। अब बात सिर्फ़ आईटी क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाशाली भारतीयों की संख्या की नहीं है। इसके बजाय, आइए हम पूछें: क्या हम ऐसे समाधान बना रहे हैं जो मायने रखते हैं? क्या हम एआई युग में कर्मचारियों को फलने-फूलने के लिए सशक्त बना रहे हैं? क्या हम लचीलेपन, पुनर्आविष्कार और प्रासंगिकता की कहानी कह रहे हैं? मैंने जानकार दोस्तों से पूछा कि क्या भारत के आईटी गुलाब का खिलना सच है। उनके जवाब बताते हैं कि गुलाब ने भले ही कुछ पंखुड़ियाँ खो दी हों, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं, और यह खिलकर वापस आ सकता है - बशर्ते हम इसे दूरदर्शिता, कौशल और साहस से पोषित, सींचें और खाद दें। इसके लिए नीतिगत नेतृत्व की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़ने का कोई कारण नहीं है।

# ऊर्जा दक्षता का मामला

सतीश कुमार
राष्ट्रपति और
कार्यकारी निदेशक,
ऊर्जा के लिए गठबंधन
कुशल अर्थव्यवस्था

अजय माथुर
प्रैक्टिस के प्रोफेसर,
आईआईटी दिल्ली; पूर्व
महानिदेशक,
अंतर्राष्ट्रीय सौर
गठबंधन और ब्यूरो
ऊर्जा दक्षता

मैं भारत ने स्वच्छ ऊर्जा पर दोगुना ज़ोर दिया है, फिर भी आज आप जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वह पाँच साल पहले की तुलना में ज़्यादा प्रदूषित है। यह एक विरोधाभास है जो हमारे ऊर्जा परिवर्तन के मूल में है।

जून 2025 तक, भारत की कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान लगभग 50% होगा। हालाँकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार , भारत का ग्रिड उत्सर्जन कारक (GEF), जो बिजली की कार्बन तीव्रता का एक माप है, 2020-21 में 0.703 $tCO_2/MWh$ से बढ़कर 2023-24 में 0.727 $tCO_2/MWh$ हो गया है।

यह एक आश्चर्यजनक उलटफेर है: ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होगा एक स्वच्छ ग्रिड। इसके बजाय भारत का ग्रिड गंदा क्यों होता जा रहा है?

क्षमता-उत्पादन का बेमेल: इसका उत्तर क्षमता और उत्पादन के बीच के अंतर में निहित है। हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा अब स्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वे कोयले या परमाणु ऊर्जा की तुलना में साल भर में बहुत कम बिजली प्रदान करते हैं। सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र आमतौर पर 15-25% क्षमता उपयोग पर चलते हैं, जबकि कोयला और परमाणु ऊर्जा संयंत्र 65-90% क्षमता उपयोग पर चलते हैं।

2023-24 में, नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत सहित) कुल बिजली का केवल 22% ही प्रदान करेगी; शेष जीवाश्म ईंधन से संचालित होगी। मुख्य क्षमता और वास्तविक वितरित ऊर्जा के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, और भारत की तेज़ी से बढ़ती माँग को इस प्रणाली में सबसे अधिक कार्बन-गहन स्रोत: कोयले से पूरा किया जा रहा है।

भारत में बिजली की माँग भी तब चरम पर होती है जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे कम उपलब्ध होते हैं। सौर ऊर्जा दोपहर में ग्रिड को ऊर्जा देती है, लेकिन शाम तक कम हो जाती है, ठीक उसी समय जब घरों से बिजली का अधिकतम भार बढ़ता है। इसलिए, जीवाश्म ईंधन संयंत्र सिस्टम के शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं—जो रात के समय और अधिकतम माँग को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं—लेकिन वे उत्सर्जन को भी रोकते हैं।

यह अस्थायी बेमेल, की सीमाओं को उजागर करता है
केवल क्षमता विस्तार ही काफी नहीं है। वास्तव में कार्बन मुक्त होने के लिए, भारत को अधिक गीगावाट के साथ-साथ लचीलेपन की भी आवश्यकता है।

यदि भारत वास्तव में अपने ग्रिड को कार्बन मुक्त करना चाहता है, तो दक्षता को पहला ईंधन बनना होगा - और जीवाश्म ईंधन नहीं, बल्कि लचीलापन ही भविष्य को शक्ति प्रदान करेगा।

जबकि चौबीसों घंटे चलने वाली (आरटीसी) नवीकरणीय बिजली, 5 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से भी कम कीमत पर, नए कोयला आधारित बिजलीघरों की तुलना में कम लागत में उपलब्ध है, तथापि इसका विस्तार धीमा है।
हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो अधिक भूमि, ट्रांसमिशन लाइनें और निवेश को संभव बनाएं।

ऊर्जा दक्षता की भूमिका ऊर्जा दक्षता अवसर प्रदान करती है। इसे अक्सर "प्रथम ईंधन" कहा जाता है, यह आपूर्ति उत्पन्न होने से पहले ही मांग को कम कर देता है। शाम और रात के समय के चरम को कम करके, दक्षता, उत्सर्जन के उच्चतम स्तर पर कोयले पर निर्भरता को कम करती है। कुशल उपकरणों - पंखे, एयर कंडीशनर और मोटर - का विस्तार करके और इमारतों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में दक्षता को शामिल करके इस वक्र को नया रूप दिया जा सकता है।

इसके लाभ कोयले की खपत में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के अवसरों में वृद्धि से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। ऊर्जा दक्षता, मांग के चरम पर पहुँचकर और मांग को नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता के अनुरूप बनाकर लचीलेपन को बढ़ाती है। यह पुरानी, अप्रचलित तकनीकों को समय से पहले बदलकर लॉक-इन को भी रोकती है।

ऊर्जा दक्षता डिज़ाइन के अनुसार अदृश्य है - द्वैध, वितरित और संचयी। फिर भी, इसके बिना, ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त नहीं किया जा सकता।

ऊर्जा विज्ञान ब्यूरो के ठोस साक्ष्य से पता चलता है कि भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक लगभग 200 मिलियन टन तेल समतुल्य कुल ऊर्जा की बचत की है, जो लगभग 1.29 गीगाटन $CO_2eq$ के बराबर है, और लगभग 760,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

भारत अकेला नहीं है, लेकिन इसका मार्ग अद्वितीय है।
फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में ग्रिड उत्सर्जन कारक केवल 0.1-0.2 $tCO_2/MWh$ है, जिसका मुख्य कारण जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का बड़ा हिस्सा है।
भारत, जिसका उत्सर्जन कारक 0.727 है, कोयले पर आधारित एक प्रमुख आधार से शुरू होता है और लगातार बढ़ती माँग का सामना कर रहा है। यह दक्षता को केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मूल रणनीति का हिस्सा बनाता है। इसके बिना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के गलत समय पर फंस जाने का खतरा है।

स्वच्छ ऊर्जा के पूर्ण मूल्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को तत्काल निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला, उसे घरों और कार्यालयों को अपनी बैटरियों को वर्चुअल पावर प्लांट से जोड़ने में सक्षम बनाना होगा, जिससे ग्रिड को चरम मांग को पूरा करने में मदद मिल सके। दूसरा, उसे उपकरण दक्षता मानकों में तेजी लानी होगी। उसे बाजारों को 4- और 5-स्टार उत्पादों की ओर ले जाना होगा और मानकों को लगातार ऊपर उठाना होगा। तीसरा, उसे छोटे और मध्यम उद्यमों को कुशल मोटर, पंप और प्रक्रियाएँ अपनाने में सहायता करनी होगी। चौथा, उसे टैरिफ संरचनाएँ अपनाकर लचीली मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को सक्षम बनाना होगा जो उच्च नवीकरणीय उपलब्धता वाले समय में मांग को स्थानांतरित करने के लिए उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करें।

पाँचवाँ, उसे पुराने, ऊर्जा-खपत करने वाले उपकरणों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन देना होगा। छठा, उसे बिजली वितरण कंपनियों को "बिजली सेवाएँ" खरीदने में सक्षम बनाना होगा, जैसे कि ग्रीन कूलिंग, जिससे आरटीसी स्वच्छ ऊर्जा से संचालित उच्च-कुशल एयर कंडीशनिंग संभव हो सके।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार भारत का GEF 2026-27 तक घटकर 0.548 तथा 2031-32 तक घटकर 0.430 रह जाएगा।

इसे हासिल करने के लिए सिर्फ़ सौर और पवन ऊर्जा फार्म बनाने से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। इसके लिए एक लचीली प्रणाली दृष्टिकोण की ज़रूरत है - जिसमें दक्षता केंद्र में हो।
भारत ने 2005 और 2019 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है, जैसा कि UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। लेकिन बढ़ता GEF एक संतुलित दृष्टिकोण की माँग करता है: नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण और पारेषण में आपूर्ति-पक्ष निवेश में तेज़ी लाएँ, साथ ही घरों, उद्योगों और शहरों में दक्षता को समाहित करें। यदि भारत वास्तव में अपने ग्रिड को कार्बन-मुक्त करना चाहता है, तो दक्षता को पहला ईंधन बनना होगा - और भविष्य को जीवाश्म ईंधन से नहीं, बल्कि लचीलेपन से शक्ति मिलनी चाहिए।

## संपादक के नाम चिठी

भारत की ऐतिहासिक जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया है ("भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास, जीता विश्व कप", 3 नवंबर)। यह सिर्फ़ एक खेल का पल नहीं था - यह इतिहास का निर्माण था। वर्षों से, 2017 का टूर्नामेंट हमें याद दिलाता रहा है कि क्या हो सकता था। यह जीत आखिरकार उस समापन की तरह लग रही है जिसका हम सभी को इंतज़ार था - दृढ़ता के फल की कहानी। क्या इसे और भी ख़ास बनाता है? इससे भी खास है इसके पीछे का सफ़र— समानता, बेहतर मैच फीस और महिला प्रीमियर लीग के उदय के लिए क्रमिक प्रयास। यह देखकर खुशी होती है कि मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी अग्रणी खिलाड़ियों के प्रयास फलीभूत हुए हैं। यह जीत लड़कियों की एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने, बल्ला या गेंद उठाने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी कि वे भी इतिहास रच सकती हैं।

पवित्रा एम.
त्रिची

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में, नीली टीम की टीम अब 1983 जैसा ही पल देखने को मिल रहा है। यह कोई आदर्श टूर्नामेंट नहीं था, क्योंकि भारत ग्रुप चरण में लगातार तीन मैच हार गया था, लेकिन खिलाड़ियों को उस समय ज़बरदस्त वापसी का श्रेय जाता है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जेमिमाह सेमीफाइनल में रोड्रिग्स की जीवन की यादगार पारी को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे 1983 में कपिल देव की 175 रनों की यादगार पारी को याद किया जाएगा। भारत की सफलता में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा।

सार्थक जैन
गुरुग्राम

हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व और शेफाली वर्मा की निडर बल्लेबाजी ने खेल की महिमा को नए सिरे से परिभाषित किया है।

इस जीत से महिलाओं के खेलों के प्रति स्थायी परिवर्तन, अधिक निवेश, दृश्यता और सम्मान की भावना पैदा होगी। अब समय आ गया है कि भारत की हर लड़की यह जान ले कि क्रिकेट अब सिर्फ उसका खेल नहीं है, यह हमारा भी खेल है।

प्रज्ञा पालीवाल
पंजाब

यह जीत देश भर की महिलाओं को किसी खेल को अपनाने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करेगी। यह तालिबान जैसी दमनकारी सत्ताओं को भी संदेश देती है कि महिलाओं का सशक्तीकरण राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी है। और गर्व.

आरएस नरूला
पटियाला

अधिक पत्र ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें।
letters@thehindu.co.in पर ईमेल किए गए पत्रों में पूरा डाक पता और पूरा नाम या नाम के आद्याक्षर अवश्य होने चाहिए।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

**कल्पमेधा**

*वे लोग जो थोड़ी-सी अल्पकालिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक आजादी का त्याग करते हैं, वे न तो आजादी के और न ही सुरक्षा के लायक होते हैं।*

*– बेंजामिन फ्रैंकलिन*

# बेलगाम हादसे

सरकार के तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद देश भर में सड़क हादसों की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चाहे वाहन में सवार लोग हों या फिर पैदल यात्री, सड़क पर चलना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं रह गया है। दुर्घटनाओं के लिए यातायात नियमों का पालन नहीं करना, लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाना और सड़क निर्माण एवं देखरेख में खामियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर सवाल है कि इन व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने का दायित्व किसका है? गौरतलब है कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह बजरी से लदे एक ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इससे पहले, रविवार को राजस्थान के फलोदी में दो वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बस और जीप आपस में टकरा गए। सोमवार को जयपुर के हरमाड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी दी। इन हादसों में पचास से अधिक लोगों की जान चली गई।

सरकार और प्रशासन की ओर से अक्सर यह दावा किया जाता है कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, दुर्घटना संभावित स्थलों को चिह्नित करना, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और देखभाल की निगरानी करना शामिल हैं। मगर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हाल की एक रपट कुछ और ही सच्चाई बयां करती है। इसके मुताबिक, वर्ष 2023 में 1.72 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में गई है और यह आंकड़ा वर्ष 2022 के मुकाबले 2.6 फीसद अधिक है। इनमें से 68 फीसद से ज्यादा मौतें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई हैं। साफ है कि सरकार की ओर से सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जो सुधारात्मक योजनाएं और उपाय किए जाते हैं, वे प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। आखिर इन योजनाओं को सरकारी कागजों से बाहर निकालकर सही मायने में जमीन पर उतारने में गंभीरता क्यों नजर नहीं आती है?

जयपुर के हरमाड़ा में जो सड़क हादसा हुआ, उसका मंजर तो किसी फिल्म के डरावने दृश्य की तरह था। एक ट्रक ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर वह तेज रफ्तार से कई वाहनों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। इस घटना की प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की बात सामने आई है। सवाल है कि अगर सड़कों पर इस तरह की भयानक घटनाएं होती हैं, तो वाहनों में सवार और पैदल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सड़कों पर जगह-जगह गति मापक यंत्र लगाए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या यह व्यवस्था ठीक से काम कर पा रही है। अगर नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाती है, तो फिर तेज गति से वाहन चलाने वालों के हौसले बेलगाम क्यों हैं? जाहिर है, व्यवस्था में कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खमियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि वाहनों की रफ्तार से लेकर सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता तक की निगरानी के लिए एक सशक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए। साथ ही गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी सख्त जरूरत है, तभी सड़कें आम लोगों के लिए सुरक्षित बन पाएंगी।

# यादगार जीत

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के फलक पर हौसला और कोशिश के स्तर पर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने हर बार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की और कई बार अपनी क्षमता को साबित भी किया, लेकिन रविवार को इस टीम के बूते भारतीय क्रिकेट में एक शानदार और यादगार कामयाबी दर्ज हुई। नवी मुंबई के डीवाइ पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम का जैसा प्रदर्शन रहा, उसे बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी के सभी स्तर पर खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन संतुलन और तालमेल का परिणाम कहा जा सकता है। इस मैच में टास दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता, लेकिन उसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती हिचक के बाद जिस रफ्तार और लय के साथ दो सौ निन्यानबे रन का लक्ष्य सामने रख दिया, उसे हासिल करना प्रतिद्वंद्वी टीम के लिए एक चुनौती बन गई। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की टीम छियालीसवें ओवर में दो सौ छियालीस रन बना सकी। कप्तान लारा ने एक सौ एक रन की पारी खेली और अपनी टीम को लड़ाई में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में भी जैसी रणनीति अपनाई, उसमें वे दक्षिण अफ्रीका को खिताबी मैच में हार से नहीं बचा सकीं।

भारतीय क्रिकेट की मुख्यधारा में भले ही पुरुष टीम को ज्यादा सुर्खियां मिलती रही हैं, मगर इसके समांतर महिलाओं की क्रिकेट टीम ने भी अपनी निरंतरता बनाए रखी है और समय-समय पर इसे साबित भी किया है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बार के फाइनल में शानदार जीत दर्ज करने से पहले भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल और प्रतियोगिता के अन्य मैचों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फाइनल में जीत की भूमिका उसी से बनी थी। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश की महिला क्रिकेट की टीम ने विश्व कप पर पहली बार कब्जा जमाया है। इससे पहले 2005 और 2017 में भारतीय महिलाओं की टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन तब खिताब से वे दूर रह गई थीं। इस बार विश्व कप की विजेता बन कर उन्होंने साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में भारत की महिला खिलाड़ियों की टीम भी एक समांतर शक्ति है।

# सुशासन की राह में प्रबंधन का संतुलन

**नव लोक प्रबंधन कोई प्रशासनिक सिद्धांत नहीं है और न ही कोई आंदोलन, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है जहां हर हाल में बेहतरी की खोज बनी रहती है। जो निजी हित के साथ-साथ पूरे समाज के लिए सुधार की गुंजाइश पैदा करता है।**

**सुशील कुमार सिंह**

नव लोक प्रबंधन समाज एवं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है। गौरतलब है कि इस नए प्रबंधन में नागरिक या ग्राहक को केंद्र में रखा जाता है। परिणामों के लिए उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने नव लोक प्रबंधन को नब्बे के दशक में अपनाया। इसमें कोई दुविधा नहीं कि यह प्रबंधन आसानी से वामपंथ और दक्षिणपंथ की सीमा लांघता है और सुशासन की अवधारणा में अंतर्निहित हो जाता है। सुशासन एक ऐसी विचारधारा है जहां लोक अवधारणा को मजबूती मिलती है साथ ही लोक सशक्तीकरण पर बल दिया जाता है। यह एक आर्थिक परिभाषा है और इसमें न्याय का सरोकार निहित है। शासन वही अच्छा जिसका प्रशासन अच्छा होता है। दोनों तभी अच्छे होते हैं जब लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण कम लागत में अधिक करने की योजना भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए कहीं अधिक आवश्यक है। इसका मूल कारण यहां आमदनी अठन्नी होना और खर्चा रुपया है।

नव लोक प्रबंधन कोई प्रशासनिक सिद्धांत नहीं है और न ही कोई आंदोलन, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है, जहां हर हाल में बेहतरी की खोज बनी रहती है। जो निजी हित के साथ-साथ पूरे समाज के लिए बेहतर की गुंजाइश पैदा करता है। भारत में लोक प्रबंधन के नवीन आयामों में लोक कल्याणकारी व्यय को घटाया गया है। मसलन रसोई गैस से हटाई गई सबसिडी और ऊपर से लगातार बढ़ती कीमत। लोक उद्यमों का विनिवेश व निजीकरण और उनमें समझौता। विकेंद्रीकरण और निजी निकायों द्वारा ठेके पर कार्य आदि। हालांकि ई-गवर्नेंस को लागू करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नव लोक प्रबंध और सुशासन के चलते ही संभव हुआ है। जैसे ई-बैंकिंग, ई-टिकटिंग, ई-सुविधा, ई-अदालत, ई-शिक्षा समेत विभिन्न आयामों में इलेक्ट्रानिक पद्धति का समावेश आदि के कारण सुशासन में निहित पारदर्शिता को मजबूती मिली है। इतना ही नहीं सरकारी संगठनों का निगमीकरण और 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' यानी निजी-सरकारी सहभागिता जैसी तकनीकों पर आगे बढ़ाना नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम ही हैं।

वर्ष 1997 का नागरिक अधिकारपत्र, 2005 का सूचना का अधिकार कानून, 2006 में ई-गवर्नेंस आंदोलन, प्रशासनिक सुधार के लिए आयोगों का गठन, समावेशी विकास पर अमल करने समेत 'स्मार्ट सिटी' और 'स्मार्ट विलेज' आदि विभिन्न परिप्रेक्ष्य भारत में लोक प्रबंध के नए आयाम को ही दर्शाते हैं। दरअसल, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन का एक-दूसरे से तार्किक संबंध है। प्रशासनिक सुधार राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम होती है। सरकार परिवर्तन और सुधार की दृष्टि से जितना अधिक जनोन्मुख होगी, सुशासन उतना अधिक प्रभावी होगा। मगर जब सरकारें कुशलता के साथ अर्थव्यवस्था पर तो जोर देती हैं, लेकिन जब आम जनमानस में इसकी प्रभावशीलता समावेशी अनुपात में नहीं होती, तो पूंजीवाद बढ़ता है। हालांकि पूंजीवाद के विकास के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था की कई लहर होती है, जहां पहली लहर में बाजार मुख्य होता है। वहीं दूसरी लहर प्रतियोगिता के लिए जानी जाती है।

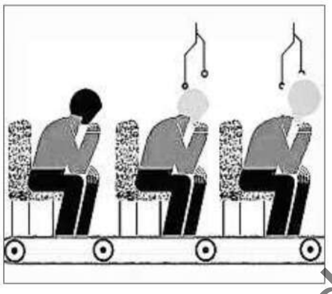

भारत गांवों का देश है, लेकिन अब बढ़ते शहरों के चलते इसकी पहचान गांव तक ही सिमट कर नहीं रही। देश खेत-खलिहानों के साथ-साथ कल-कारखानों के साथ आगे बढ़ चला है। बीते 78 वर्षों में परत-दर-परत विकास हुआ है।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने के साथ सामुदायिक और सामाजिक विकास की अवधारणा पर काम शुरू हो गया था। बावजूद इसके समावेशी ढांचे का न जाने क्यों पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई बनी हुई है। वर्ष 1991 में उदारीकरण वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारत में बदलाव की एक नई लहर लेकर आया। वर्ष 1992 में समावेशी विकास और सुशासन की धारणा ने मूर्त रूप लिया। फिर भी बुनियादी विकास, मानव विकास सूचकांक को लेकर जद्दोजहद कम नहीं हो रही है।

> **मानव विकास सूचकांक 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत यहां 130वें स्थान पर है। जबकि 123 देशों में वैश्विक भूख सूचकांक-2025 में देश 102वें स्थान पर है। वहीं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। इस मामले में वर्ष 2015 में यह 76वें स्थान पर था। साफ है कि देश भुखमरी और गरीबी से तो जूझ ही रहा है, वहीं रही-सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी है। शासन, प्रशासन और सुशासन शब्द अच्छे हैं। मगर इन आंकड़ों से देश की तस्वीर धुंधली लगती है। नव लोक प्रबंधन अच्छे शासन के लिए अच्छा उपाय हो सकता है। किसी भी देश में बेरोजगारी स्वयं में गरीबी की जड़ है।**

नवीन लोक प्रबंधन ने नौकरशाही को नई दिशा में मोड़ने और उसे नई संरचना देने का भी प्रयास किया है। नया लोक प्रबंधन एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर कई उत्प्रेरक तत्त्वों का प्रभाव है। भारत जैसे देश में प्रतियोगिता नागरिकों को ग्राहक बना देती है और सफल ग्राहक वही है जो कमाई के साथ बाजार तंत्र को अंगीकार कर सके। आर्थिक दृष्टि से अनेक वर्ग हैं जो बाजार के साथ-साथ कदम-से-कदम मिलाने सक्षम नहीं हैं। यह कहना अतार्किक न होगा कि विकासशील देशों का बाजार हो या प्रतियोगिता इसका स्वरूप बड़ा होता है। मगर मानव संसाधन में समुचित दक्षता और उचित रोजगार की कमी से यह विफल हो जाता है या फिर जनता असफल हो जाती है। जिस देश में 80 करोड़ नागरिकों का गुजर-बसर सरकार की ओर से दिए गए पांच किलो मुफ्त अनाज से होता हो, वहां बाजार और प्रतियोगिता का अर्थ अनसुलझे सवाल की तरह ही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य भी पूरा हुआ है या नहीं, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है।

सुशासन के मूल्यांकन की भी तीन परते हैं। जिसमें मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक इसके हिस्से हैं। यदि यह किसी भी स्तर पर है, तो सुशासन को ही नुकसान पहुंचाता है। उद्यमशीलता का दम भरने वाली सरकारों पर भी सवालिया निशान लगाता है। मानव विकास सूचकांक 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत यहां 130वें स्थान पर है। जबकि 123 देशों में वैश्विक भूख सूचकांक-2025 में देश 102वें स्थान पर है। वहीं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। खास यह भी है कि वर्ष 2015 में यह 76वें स्थान पर था। साफ है कि देश भुखमरी और गरीबी से तो जूझ ही रहा है, वहीं रही-सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी है। शासन, प्रशासन और सुशासन शब्द अच्छे हैं। मगर इन आंकड़ों से देश की तस्वीर धुंधली लगती है। नव लोक प्रबंधन अच्छे शासन के लिए अच्छा उपाय हो सकता है। किसी भी देश में बेरोजगारी स्वयं में गरीबी की जड़ है। इन दिनों भारत में बेरोजगारी दर रेकार्ड स्तर को पार कर चुकी है। गरीबी उन्मूलन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना जारी है। मगर हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है।

देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के बावजूद भरपेट भोजन कई लोगों के हिस्से से अभी दूर भी है। इतना ही नहीं खाद्य पदार्थों की कीमत में भी आए दिन उछाल देखा जाता रहा है। गेहूं, आटा, चावल और दाल के साथ-साथ तेल, आलू और प्याज के भाव भी कमोबेश बढ़ते रहते हैं। यह नव लोक प्रबंधन और सुशासन दोनों दृष्टि से उचित नहीं है। सवाल यह है कि देश किससे बनता है और किस के साथ चलता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और साफ है कि कोई भी जनता समावेशी और बुनियादी विकास से अछूती रहने वाली व्यवस्था देर तक नहीं चाहेगी। यदि महंगाई, बेरोजगारी तथा जीवन से जुड़ी तमाम व्यवस्था पटरी पर न हों, तो लगता है कि जनता का शासन कहीं जनता पर शासन तो नहीं हो गया। हालांकि जहां सुशासन की बयार की बात हो और उद्यमशील सरकार में संतुलन का भाव व्याप्त हो, वहां लोकतंत्र और जनता का शासन ही कायम रहता है।

## दुनिया मेरे आगे

# जिज्ञासा की जड़ें

**समराज चौहान**

मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। उसकी बुद्धि, विवेक और विचारशक्ति उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अगर हम गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि मनुष्य अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। हालांकि यह प्रकृति और उसके रहस्यों के विस्तार के कारण है। विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म- हर क्षेत्र में मनुष्य की यात्रा जारी है और जितना ज्ञान वह अर्जित करता है, उसके समांतर कई क्षेत्रों में उसकी अज्ञानता भी उजागर होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव अल्पज्ञ है। मनुष्य ने चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई, महासागरों की गहराई नापी और पृथ्वी के छोर तक यात्रा की, लेकिन आज भी वह अपने ही मन की गहराई नहीं माप पाया है। हमारी भावनाएं, चेतना और हमारे विचार किस ढंग से काम करते हैं, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। मनुष्य जितना ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपने भीतर झांकने से कतराता है।

प्रकृति के रहस्यों को समझने के मामले में मनुष्य की अभी सीमित पहुंच रही है। विज्ञान ने भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं का कुछ अनुमान लगाना सीखा है, पर उन्हें रोक पाने की शक्ति आज भी उसके पास नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान की तकनीक विकसित हुई है, फिर भी अचानक आने वाले आंधी-तूफान या बाढ़ जैसी आपदाएं मनुष्य को उसकी असहायता का अहसास कराती हैं। यह सब प्रमाण है कि प्रकृति के विस्तार के समांतर मनुष्य अभी भी ज्ञान की सीढ़ियों के शुरुआती सोपान पर खड़ा है।

ऐसे संदर्भ अक्सर सामने आते रहते हैं कि जब-जब मनुष्य ने इस बात पर गुमान किया कि वह सब कुछ जान चुका है, तभी कोई नई खोज या आविष्कार उसकी भूल को उजागर कर देता है। कभी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र समझा गया, तो कभी यह विश्वास किया गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन बाद में विज्ञान ने इन धारणाओं को गलत साबित किया। इससे स्पष्ट है कि हमारी जानकारी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है।

मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसका जन्म और फिर उसकी मृत्यु है। आज तक कोई वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद जीवन का क्या स्वरूप होता है। धर्म और दर्शन ने इसके अलग-अलग उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सका। यह भी हमारी अल्पज्ञता का प्रमाण है। ज्ञान के इस अभाव का एक और उदाहरण समाजशास्त्र और राजनीति में देखा जा सकता है। हजारों साल से सभ्यताएं बनती और बिगड़ती आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी, जिसमें सभी को समान अवसर और पूर्ण न्याय मिल सके। युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, भूख और गरीबी आज भी मानवता को चुनौती दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अभी तक जीवन का सही मार्ग नहीं खोज पाया।

मनुष्य की अल्पज्ञता केवल भौतिक या सामाजिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी दिखाई देती है। हम अपने सुख-दुख का कारण तक सही ढंग से नहीं समझ पाते। कभी छोटी-सी असफलता हमें निराशा के गहरे अंधकार में धकेल देती है, तो कभी तुच्छ-सी सफलता पर हम अहंकार से भर जाते हैं। यह अस्थिरता बताती है कि हम अपने मन और भावनाओं को जानने और नियंत्रित करने में कितने असमर्थ हैं। फिर भी, इस अल्पज्ञता का एक सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ नहीं जानता, इसलिए उसमें हर समय कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। यही जिज्ञासा उसे नए प्रयोगों और खोजों की ओर प्रेरित करती है। यों यह अपने आप में एक सवाल है कि पूर्णता क्या है और क्या ज्ञान को कभी पूर्ण मान लिया जा सकता है? अगर मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होता, तो शायद उसकी यात्रा एक मुकाम पर पहुंच कर समाप्त हो जाती। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अल्पज्ञता मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है।

> **इंसान सब कुछ नहीं जानता, इसलिए उसमें हर समय कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। यही उसे नए प्रयोगों और खोजों की ओर प्रेरित करती है। यों यह अपने आप में एक सवाल है कि पूर्णता क्या है और क्या ज्ञान को कभी पूर्ण मान लिया जा सकता है? अगर मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होता, तो शायद उसकी यात्रा एक मुकाम पर पहुंच कर समाप्त हो जाती।**

आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से प्रगति हो रही है। इसके बावजूद जब कोई महामारी फैलती है या कोई नया विषाणु सामने आता है, तो पूरा मानव समाज हिल उठता है। पिछली महामारी के दौरान जो हुआ, वह भी हमें सिखाता है कि सारी उपलब्धियों के बावजूद हम सीमित ज्ञान वाले प्राणी हैं। इस सीमा को स्वीकार करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम यह मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। विनम्रता और जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अहंकार से ग्रस्त होकर अगर हम सोचें कि अब और जानने को कुछ नहीं बचा, तो वही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव अल्पज्ञ है। मगर यही अल्पज्ञता उसे निरंतर आगे बढ़ने, सीखने और खोजने की प्रेरणा देती है। सच्चा ज्ञानी वही है, जो अपनी अज्ञानता को पहचान सके। जब तक मनुष्य में यह विनम्रता बनी रहेगी, तब तक वह ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मनुष्य के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन यह सागर की केवल कुछ बूंदें भर हैं। वास्तविक सागर अब भी असीम है। हमें अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके लगातार जिज्ञासु बने रहना चाहिए। तभी मनुष्य जीवन सार्थक होगा और उसकी यात्रा अनंत ज्ञान की ओर निरंतर चलती रहेगी।

## सावधानी की जरूरत

आए दिन लोगों के साथ साइबर धोधाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार इस खतरे से निपटने के नए उपाय तलाश रही हैं। इसी क्रम में एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसके तहत फोन करने वाले व्यक्ति का नाम मोबाइल की स्क्रीन पर दिखेगा। इसका उद्देश्य है कि लोग सतर्क रहें और किसी संदिग्ध व्यक्ति के जाल में न फंसें। उनके साथ धोखाधड़ी न हो। यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। मगर सवाल यह है कि क्या इससे समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। मोबाइल का नया नंबर लेते समय कई लोग फर्जी दस्तावेज का उपयोग करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर नाम दिखने के बावजूद यह पहचान पाना मुश्किल होगा कि फोन करने करने वाला असली है या नकली। कई बार हमें अनजान नंबर से भी जरूरी या आपातकालीन काल आती हैं। ऐसे में हर अनजान काल को संदिग्ध मान लेना व्यावहारिक नहीं है। जरूरत है कि मोबाइल सिम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की जाए, फर्जी पहचान पर सख्त कार्रवाई हो और साइबर अपराधियों पर त्वरित दंडात्मक कदम उठाए जाएं।

*– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया*

## गरिमा के विरुद्ध

हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में माहवारी के दौरान छुट्टी स्वीकृत करने के लिए जिस तरह की जांच कराने की खबर आई, वह शर्मनाक है। हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं और अब तक महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आज महिलाएं घर और बाहर, दोनों जगह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। फिर वे समानता और सम्मान की अधिकारी भी हैं। फिर भी कुंठित मानसिकता के कारण उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है। माहावारी प्रकृति का एक चक्र है। इसे हम कैसे भूल सकते हैं? इस दौरान महिलाओं को किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, यह स्त्री ही जानती और महसूस कर सकती है। वह तनाव की कई परतों से गुजरती हैं। जीवन की कई चुनौतियों के बीच वह सब कुछ संभालती हैं। अपना काम करती जाती हैं। वे मां, बहन, बेटी, पत्नी और न जाने कितने किरदार निभाती हैं। किसी भी स्तर पर उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

*– हुकम सिंह, ग्वालियर*

## तकनीक की मुश्किल

इंटरनेट के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति लाने का काम किया है। उनतीस अक्तूबर 1969 में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच संदेश भेजा गया था। इस छोटे से प्रयोग ने पूरी दुनिया को इंटरनेट से परिचय कराया और एक सूत्र में बांध दिया। उस ऐतिहासिक घटना की याद में और इंटरनेट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। आज इंटरनेट केवल सूचना का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम बन चुका है। मगर इसके साथ ही साइबर अपराध, निजता का हनन और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। अतः आवश्यकता है कि इंटरनेट का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिकता के साथ किया जाए। इंटरनेट दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि यह मानवता की साझा उपलब्धि है और इसका सदुपयोग ही हमें और समानता-आधारित विश्व की ओर ले जा सकता है।

*– हिमांशु शेखर, गयाजी*

## जोखिम का सफर

पिछले कुछ समय में वातानुकूलित बसों में अलग-अलग जगहों पर आग लगने की कई घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। जिन बसों में आग लगी, वे पूरी तरह जल कर खाक हो गईं। एकाध घटना को छोड़ दें, तो जितने हादसे हुए हैं, उनमें आग लगते ही दरवाजे बंद हो गए और यही बड़ा कारण रहा भारी नुकसान का। बस हो या ट्रेन, भले ही उनमें आपातकालीन खिड़कियां हों, फिर भी उनमें से यात्रियों को बाहर निकलने के दरवाजे आगे और पीछे दोनों ओर होने चाहिए। बसों में स्वचालित दरवाजे बदले जाएं ताकि गेट बंद न हो पाएं और वे आसानी से तुरंत खोले जा सकें। सुविधा की दृष्टि से 'आटो लाक' को बेहतर बताया जाता है, लेकिन ये अब जान-माल के दुश्मन भी बन गए हैं। अचानक दुर्घटना होने पर तुरंत जरूरत पड़ने पर दरवाजे नहीं खुलते। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

*– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com



https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर



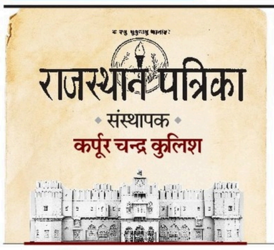


# विश्व कप का ताज हमारी बेटियों को करेगा प्रेरित

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार रात को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो धमाका किया, उसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी। बनी रहनी भी चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। विश्व कप चैंपियन बनना छोटी उपलब्धि हो भी नहीं सकती। 52 साल हुए हैं महिला क्रिकेट विश्व कप को शुरू हुए और यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों की बपौती माना जाने वाला यह ताज वहां से निकलकर भारत के मस्तक पर सुशोभित हुआ है। इसे महिला क्रिकेट में वर्चस्व का स्थानांतरण माना जा सकता है, ठीक पुरुष विश्व कप की तरह जब 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज से क्रिकेट की सत्ता छीन ली थी। वह कमाल कपिल देव की टीम ने किया था। अब ठीक वैसा कारनामा महिलाओं के लिए हरमनप्रीत कौर की टीम ने कर दिखाया है।

जब मील का पहला पत्थर कायम होता है तो आगे से आगे मंजिलों के लिए रास्ते खुलते जाते हैं। दुनिया जानती है कि कपिल देव की टीम के विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट में किस कदर सकारात्मक बदलाव आए और भारतीय टीम की आज की धाक में भी उसी जीत का कहीं न कहीं योगदान है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महिला विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली है। खेल का माहौल अब बहुत सिर चढ़कर बोलेगा और यह बुलंदियों तक पहुंचने के अनेक मार्ग भी खोलेगा। आने वाली कई-कई पीढ़ियां भारत की इस जीत से प्रेरित और प्रभावित होंगी। जिस तरह से कोई भी किसी रोल मॉडल में अपनी छवि देखता है, ठीक उसी तरह लड़कियां इस जीत की नायिकाओं में खुद को फिट बिठाने और उनका कारनामा दोहराने में लग जाएंगी। हरमनप्रीत कौर के शब्दों में हम जीत सकते हैं, इसके प्रति अविश्वास कभी भी नहीं रहेगा। बस आगे प्रगति के सोपान तय करने के लिए हमें इस जीत को अपनी आदत बनाना होगा। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लंबे समय तक यह आदत बनी रहेगी और भारत के सिर पर और कई ताज सुशोभित होते रहेंगे।

भारतीय टीम पूरी तरह संतुलित और क्षमतावान थी। यह चैंपियन बनने की पूरी हकदार थी। अकेली यही टीम थी जिसने किसी के लिए भी मुकाबला आसान नहीं होने दिया। लीग मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को पसीना लाने वाली यही टीम थी। यह ऐसा समय था, जब टीम कुछ लड़खड़ाई थी, लेकिन एक बार जो यह संभली तो इसके बाद उसके सामने टिकने लायक कूवत किसी की नहीं रही थी। सात बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के 338 रन बनने के बावजूद उसे आसानी से पीट देने के बाद भारत के विश्व कप विजेता बनने में कोई संशय शेष नहीं रहा था। फाइनल का परिणाम इसकी गवाही है कि दक्षिण अफ्रीका हमारे सामने बिल्कुल टिक नहीं पाया। देश का मान बढ़ाने के लिए बेटियों को सलाम!

**बिहार चुनाव :** ऐसा मार्गदर्शक नक्शा चाहिए जो नारों व सपनों की जगह आंकड़ों और जवाबदेही पर टिका हो

# घोषणा पत्र : लोकलुभावन बनाम वित्तीय अनुशासन

के.एस. तोमर
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार
@patrika.com

**असल सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा वादे करता है, बल्कि यह है कि कौन अपने वादों को टिकाऊ रूप में लागू कर सकता है। लोकलुभावन वादों से चुनाव जीते जा सकते हैं, पर विकास को टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन अनिवार्य है।**

बिहार में चुनावी समर अपने निर्णायक चरण में है और घोषणा पत्रों की जंग भी खुलकर सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के घोषणा पत्रों के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट है। महागठबंधन का दृष्टिकोण भावनात्मक और समाजवादी है, जो तत्काल राहत देता है पर दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। जबकि एनडीए का दृष्टिकोण विकासोन्मुख और निवेश-आधारित है, जो धीमा अवश्य है पर स्थायी परिणामों की दिशा दिखाता है। जहां महागठबंधन वोटरों को 'सहज राहत' का वादा करता है, वहीं एनडीए 'रोजगार और आत्मनिर्भरता' को नया सूत्र बनाकर चुनावी विमर्श को बदलना चाहता है।

एनडीए ने अपने 'संकल्प पत्र' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास, निवेश और रोजगार को मुख्य आधार बनाया है। एनडीए ने लोकलुभावन वादों से बचते हुए एक संतुलित दस्तावेज पेश किया है जो निरंतरता, प्रशासनिक अनुशासन और आर्थिक यथार्थ पर केंद्रित है। एनडीए के संकल्प पत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का वादा किया गया है, जो सरकारी भर्तियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), रक्षा उत्पादन और टेक्सटाइल उद्योगों के क्लस्टर विकसित करने का खाका प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 'लाखपति दीदी' योजना को विस्तारित कर 'मिशन करोड़पति' की घोषणा की गई है, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर ऋण और प्रशिक्षण समर्थन मिलेगा। कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश की योजना है- जिसमें फिश फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण कृषि ढांचा प्रमुख हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 7 नए एक्सप्रेस-वे, 3600 किमी नई रेल परियोजनाएं और हर जिले में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का रोडमैप रखा गया है। साथ ही पिछड़ी जातियों और गरीब वर्गों के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना और 10 लाख तक की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि यह घोषणा पत्र 'विकास की निरंतर यात्रा' का हिस्सा है- जिसका लक्ष्य बिहार को 'गरीबी से प्रगति' की ओर ले जाना है।

इसके विपरीत, महागठबंधन का घोषणा पत्र लोकलुभावन वादों से परिपूर्ण है। 'बिहार का तेजस्वी प्रण' शीर्षक से जारी इस दस्तावेज में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, मुफ्त बिजली, छात्रों को भत्ता और महिलाओं को मासिक सहायता जैसे कई वादे शामिल हैं। इन योजनाओं का आर्थिक बोझ अत्यंत भारी है। यदि 'एक परिवार-एक नौकरी' की नीति लागू होती है और अनुमानतः 1.25 करोड़ परिवारों को औसतन 1.5 लाख वार्षिक वेतन दिया जाता है, तो राज्य पर हर वर्ष लगभग 1.9 लाख करोड़ का नया भार आएगा जो उसकी मौजूदा वित्तीय क्षमता से कई गुना अधिक है। ओपीएस की बहाली और बिजली व वस्तुओं पर सब्सिडी से पूंजीगत व्यय में कटौती होगी, जिससे सड़क, उद्योग और शिक्षा जैसे दीर्घकालीन क्षेत्रों में निवेश की गति मंद पड़ सकती है।

एनडीए का घोषणा पत्र अपेक्षाकृत व्यावहारिक जरूर दिखता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिहार की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है। 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का लगभग 9.2% था, जिसे 2025-26 में घटाकर 3% (करीब 32,700 करोड़) पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात 38% है, जो देश में सबसे ऊंचों में से एक है। राजस्व व्यय 80% से अधिक है और वेतन, पेंशन व ब्याज भुगतान मिलकर राज्य की आय का 70% हिस्सा खा जाते हैं। ऐसे में बड़े निवेश और कल्याणकारी योजनाएं समानांतर रूप से चलाना आसान नहीं होगा। एनडीए की योजनाएं तभी सफल होंगी जब निजी निवेश आकर्षित हो, कर संग्रह में वृद्धि हो और केंद्र से पर्याप्त सहायता मिले। बिहार का औद्योगिक आधार कमजोर है, शहरीकरण दर कम है और भूमि उपयोग की जटिलताएं अब भी बाधा बनी हुई हैं। अतः एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य तभी साकार होगा जब औद्योगिक निवेश धरातल पर उतरे।

बिहार की सबसे बड़ी समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि व्यय-दक्षता और जवाबदेही का अभाव है। पिछले वर्षों में बड़ी परियोजनाएं अधूरी रह गईं, कई केंद्रीय अनुदान खर्च नहीं हो सके। ऐसे में घोषणा पत्र चाहे किसी का भी हो, उसकी विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब उसमें सार्वजनिक लागत का खुलासा, वार्षिक वित्तीय ऑडिट, और समयबद्ध क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा दी जाए।

असल सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा वादे करता है, बल्कि यह है कि कौन अपने वादों को टिकाऊ रूप में लागू कर सकता है। अब राजनीतिक ईमानदारी की असली परीक्षा वित्तीय गणित में है- हर रुपया कहां से आएगा, कहां खर्च होगा और उसकी निगरानी कैसे होगी। सबसे बड़ी चुनौती है- संवेदनशीलता और गणना के बीच संतुलन साधना। लोकलुभावन वादों से चुनाव जीते जा सकते हैं, पर विकास को टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन अनिवार्य है। राज्य को चाहिए एक ऐसा मार्गदर्शक नक्शा जो न तो केवल नारों पर टिका हो और न ही सपनों पर- बल्कि आंकड़ों और जवाबदेही पर आधारित हो। जैसे-जैसे चुनाव अभियान तेज होगा, मतदाताओं को नेताओं से एक ही सवाल पूछना चाहिए- 'स्लोगन नहीं, हिसाब दिखाइए।'

## प्रसंगवश

# बजट घोषणाएं जनता के लिए कागजी सपना न बनकर रह जाए

### नए एक्सप्रेस-वे और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बजट घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं?

यह सही है कि बजट में लोकलुभावन घोषणाओं का उद्देश्य केवल विकास नहीं होता, बल्कि राजनीतिक लाभ लेना और अपनी छवि चमकाना भी होता है। इसीलिए ये घोषणाएं अक्सर जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। बात चाहे राजस्थान में बनने वाले नए एक्सप्रेस-वे की हो या जयपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की, बजट में इन पर तालियां तो खूब बजीं, पर धरातल पर काम अधूरा ही है। इलेक्ट्रिक बसों का सपना तो दो बजट से दिखाया जा रहा है, लेकिन आज भी यात्रियों को कबाड़ हो चुकी लो-फ्लोर बसों में सफर करना पड़ रहा है। कमोबेश यही कहानी एक्सप्रेस-वे योजनाओं की है। राजस्थान में नौ एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा हुई थी, जिनमें से दो तो पहले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की योजना में शामिल थे। शेष सात में से सिर्फ दो पर ही काम शुरू हो पाया है।

असल समस्या घोषणा में नहीं घोषणाओं के क्रियान्वयन में है। बजट में घोषित अनेक योजनाएं कागज पर चमकदार रहती हैं, जमीन पर नहीं। इनमें देरी के पीछे राजनीतिक स्वार्थ, नौकरशाही की सुस्ती और मंजूरी प्रक्रिया की जटिलता सबसे बड़ी वजहें हैं। राजनीतिक लाभ के लिए अक्सर योजनाएं घोषित तो कर दी जाती हैं लेकिन उनकी वास्तविक जरूरत या व्यावहारिकता को दरकिनार कर दिया जाता है। जरूरी है कि हर योजना की घोषणा से पहले उसकी व्यावहारिकता, वित्तीय उपलब्धता और जमीनी तैयारी की जांच की जाए। हर परियोजना के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय हो और बीच-बीच में प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। राज्य और केंद्र स्तर पर एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए जो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करे। यदि किसी विभाग या अधिकारी के कारण परियोजना अटकती है, तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। जब तक योजनाओं को राजनीतिक हथियार की बजाय विकास का साधन नहीं माना जाएगा, तब तक ये घोषणाएं जनता के लिए सिर्फ कागजी सपने ही बनी रहेंगी।

- महेन्द्र सिंह शेखावत
mahendra.shekhawat@in.patrika.com

## बुक इनसाइट

# द गॉड ऑफ द वुड्स

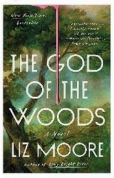


लिज मूर का नया उपन्यास 'द गॉड ऑफ द वुड्स' एक रोचक थ्रिलर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में शामिल हो चुका है। लेखिका, जो 'लॉन्ग ब्राइट रिवर' जैसी मशहूर किताब की रचयिता हैं, यहां जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करती हैं। कहानी एक छोटे से शहर के जंगल में घूमती है, जहां प्रकृति और इंसानी मन दोनों की अंधेरी परतें खुलती हैं। लेखिका ने कहानी की शुरुआत में एक शांत और हरे-भरे जंगल के दृश्य को बखूबी चित्रित किया है। कहानी की नायिका एक युवा महिला है जो अपने बचपन के दोस्त की गुमशुदगी की जांच करती है। वर्षों पुराना यह मामला जंगल से जुड़ा है जहां एक प्राचीन देवता प्रचलित है। जंगल को 'गॉड ऑफ द वुड्स' कहा जाता है क्योंकि यहां एक रहस्यमयी शक्ति लोगों को अपनी ओर खींचती है। जांच के दौरान पुराने राज खुलते हैं। परिवार के झूठ, दोस्ती की दरारें और प्रकृति का क्रूर चेहरा। थ्रिलर होने के बावजूद किताब मनोवैज्ञानिक गहराई देती है। पर्यावरण, मानवीय लालच और मिथकों का मिश्रण इसे खास बनाता है।

## फैक्ट फ्रंट

# शिवलिंग फूल : अनोखा आकार

भारत की जैव विविधता हमेशा से अनोखे और रहस्यमय पौधों के लिए जानी जाती है। इन्हीं में से एक है शिवलिंग फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम अमॉर्फोफैलस पैयोनीफोलियस है। यह फूल अपने अनोखे आकार और दुर्लभ गुणों के कारण चर्चा में रहता है। इसका नाम 'शिवलिंग फूल' इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा है। बीच में लंबा स्पाइक और उसके चारों ओर फैला हुआ बड़ा बैंगनी-लाल रंग का कवर। यह फूल मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाया जाता है। इसका कंद जमीन के अंदर सालों तक दबा रहता है। 3-4 साल में केवल एक बार, मानसून के बाद यह अचानक उगता है। जो शिवलिंग जैसा स्पाइक दिखता है, उस पर हजारों नर और मादा फूल एक साथ होते हैं। एक ही पौधे में नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन यह स्व-परागण नहीं करता। आदिवासी इलाकों में इसका कंद दवा के रूप में इस्तेमाल होता है।

**खतरा** अमरीका शुरू करने जा रहा परमाणु परीक्षण

# दुनिया में क्या फिर लौट आएगा परमाणु परीक्षणों का दौर?

पथनबोईना रामकृष्ण
शोधार्थी, जेएनयू
@patrika.com

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक चौंकाने वाली घोषणा की है कि अमरीका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अन्य देशों की ओर से किए जा रहे परमाणु परीक्षणों ने अमरीका को भी यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। यह नीति परिवर्तन 1992 से चले आ रहे अमरीका के परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक प्रतिबंध को समाप्त कर देगा, जिसके तहत अमरीका ने तीन दशक से अधिक समय से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है।

वर्तमान में अमरीका अपने परमाणु बमों के भंडार की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगों का उपयोग करता है। ट्रंप का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब रूस ने हाल ही 'पोसीडॉन' नामक एक परमाणु-सक्षम और परमाणु-संचालित पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है, जिसे टॉरपीडो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एसआइपीआरआइ ईयर बुक 2025 के अनुसार, अमरीका के पास कुल 5177 और रूस के पास 5459 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनमें सक्रिय सैन्य भंडार और सेवानिवृत्त वॉरहेड्स दोनों शामिल हैं। चीन की स्थिति भी तेजी से बदल रही है। अमरीकी अनुमान बताते हैं कि 2023 से हर साल वह करीब 100 नए वॉरहेड्स जोड़ रहा है, और 2030 तक उसके पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार हो सकते हैं। रूस और चीन के बीच 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से संबंध इतने मजबूत हो गए हैं कि वे अब वास्तविक रूप से एक गठबंधन में बदल चुके हैं। अमरीका को एक नहीं, बल्कि रूस और चीन की संयुक्त परमाणु क्षमता का सामना करना है। इसी वजह से अमरीका ने अगले 30 वर्षों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर अपने परमाणु शस्त्रागार, 'न्यूक्लियर ट्रायड' और उसकी तकनीकी संरचना को पूरी तरह नया रूप देने की योजना बनाई है।

यह स्पष्ट संकेत है कि दुनिया अब हथियारों की नई दौड़ की ओर बढ़ रही है। ट्रंप की ताजा घोषणा रूस और चीन दोनों को अपने परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को और तेज करने का बहाना देगी। शीत युद्ध के दौर में, जोखिमों के बावजूद अमरीका और सोवियत संघ ने परमाणु अप्रसार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था। उन्होंने हथियार नियंत्रण समझौतों में सक्रिय भागीदारी की थी। लेकिन आज की स्थिति कहीं अधिक जटिल है, रूस और चीन दोनों ही अमरीका के साथ हथियार नियंत्रण वार्ताओं में रुचि नहीं दिखा रहे।

इस अनिश्चितता का असर अब अन्य देशों की परमाणु नीतियों पर भी पड़ेगा, जो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। यह तय है कि ट्रंप का बयान वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की भूमिका लिख सकता है।

## रूस में जंगलों के बीच रहस्यमयी शिलाएं

*रूस के कोमी गणराज्य में स्थित मैनपुपुन्योर शिला संरचनाएं सात विशाल पत्थर स्तंभों का समूह हैं, जो करोड़ों वर्षों में प्राकृतिक क्षरण से बने हैं। जंगलों के बीच बिना किसी सड़क के इस स्थल तक पहुंचने में दो दिन लग जाते हैं, लेकिन यहां की अद्भुत सुंदरता और रहस्य मन मोह लेते हैं।*

**दृष्टिकोण** भाव को आत्मसात करके ही लेखन संभव

# क्रिएटिव राइटिंग को चुनौती नहीं दे सकेगा एआइ

सिद्धायनी जैन
स्वतंत्र लेखिका एवं स्तंभकार
@patrika.com

जीवन के विविध माध्यमों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के बढ़ते दखल ने कुछ संवेदनशील लोगों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मशीनी लेखन सर्जनात्मक लेखन (क्रिएटिव राइटिंग) पर हावी हो जाएगा? यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण लगता है क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एआइ की मदद से लिखी कविताओं को ही पोस्ट नहीं किया बल्कि कहानी और उपन्यास लिखने का भी दावा किया है।

अर्थशास्त्र का एक नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह सामान्य स्वभाव है कि शॉर्टकट व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। सबकी सामर्थ्य में होता भी नहीं है कि वो हमेशा धैर्य को धारण कर सकें। इसीलिए तो मर्यादा के निर्वहन को हमारे यहां तप की संज्ञा दी गई है। एक छोटे से प्रॉम्प्ट के सहारे यदि लेखक या कवि होने का किसी व्यक्ति का सपना पूरा होता है तो शब्द साधना में उसकी रुचि क्यों रहेगी? यदि ऐसा होता है तो सृजन की दुनिया के लिए यह सचमुच एक चुनौती है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग इतनी आसान भी नहीं है, जितना उसे समझ लिया गया है। किसी भाव को आत्मसात किए बिना उस पर प्रभावशाली कविता, कहानी या उपन्यास लिख देना संभव नहीं होता। एआइ सूचनाओं और जानकारियों का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करता है। ऐसे में यह तो संभव है कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट के बाद किसी विषय पर एआइ की मदद से एक निश्चित भाव वाली रचना को प्राप्त कर लिया जाए लेकिन वह रचना मर्मस्पर्शी हो सकेगी, इसमें संदेह ही रहेगा क्योंकि पाठक या श्रोता के मर्म को स्पर्श करने के लिए भावों के जिस आसमान में विचरना होता है, एआइ या किसी भी तकनीक के लिए वो फिलहाल संभव नहीं है।

हां, एआइ कल्पना को नया विस्तार अवश्य दे सकता है। एआइ से लिखी गई कविताओं में तुकबंदी तो हो सकती है, लेकिन भावों की वह लय नहीं हो सकती जो कवि से लिखवाती है-'लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती/ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।' हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली इन पंक्तियों को लिखने के लिए जीवन के जिन अनुभवों और भावों के जिस स्पंदन की आवश्यकता होती है, किसी मशीनी लेखन के लिए उन्हें प्राप्त कर पाना आसान नहीं होगा। भावों को अभिव्यक्त करने का हुनर व्यक्ति को न केवल सुख देता है, बल्कि यश भी देता है। इस यश से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग जोड़-तोड़ के लेखन से स्वयं को रचनाकार करने की जुगत में रहते हैं। एआइ का लेखन ऐसे लोगों को भले ही रास आ जाए लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के लिए एआइ चुनौती नहीं बन सकेगा। जिस बौद्धिकता (इंटेलीजेंस) के नाम की शुरुआत में ही कृत्रिम (आर्टिफिशियल) शब्द जुड़ा हो, वो रचनात्मकता की राह का रोड़ा कैसे बन सकती है?

## आपकी बात

### ऊर्जा पार्कों की स्थापना हो

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण जैसे कदम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं। इनसे स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता भी सुदृढ़ होगी।

- योगेश स्वामी, सूरतगढ़

patrika.com पर पढ़ें

### पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें https://shorturl.at/7sOIU

### आज का सवाल

बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए स्कूलों में क्या उपाय किए जाने चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

**समाधान** सर्वाधिक लचीलेपन और दूरदर्शिता से होगा भविष्य का निर्माण

# जलवायु संकट के बीच कैसे आगे बढ़ें भारतीय व्यवसाय

डॉ. अरुणाभा घोष
संस्थापक-सीईओ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)
@patrika.com

जलवायु संकट भारत के कारखानों के दरवाजे तक पहुंच चुका है। विभिन्न व्यवसायों और उद्यमियों के लिए अब यह सुदूर घटित होने वाला पर्यावरणीय खतरा नहीं है, बल्कि आज की आर्थिक हकीकत है। मौसम की चरम परिस्थितियां- जैसे बाढ़ से सप्लाई चेन डूब रही है और लू से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता घट रही है- पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके बावजूद इस संकट में हमारी पीढ़ी के लिए एक व्यावसायिक अवसर भी छिपा है।

एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, 82 प्रतिशत कंपनियां पहले से ही डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन घटाने) से आर्थिक लाभ दर्ज कर रही हैं। जलवायु-लचीलापन, कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ाया गया कदम प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन और विकास का नया इंजन है। अब सवाल यह नहीं है कि कोई कदम उठाना है या नहीं, बल्कि यह है कि कैसे इसका नेतृत्व करना है। साक्ष्यों को देखें तो भारतीय कंपनियों ने पहले ही 45,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जिससे ऊर्जा लागत में भारी कमी आई है। चूंकि लगभग 70 प्रतिशत निर्यात नेट-जीरो बाजार से संबंधित है, इसलिए डीकार्बोनाइजेशन वैश्विक व्यापार में प्रवेश करने के लिए नई कीमत है।

वैश्विक स्तर पर, विश्व की आधी से अधिक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के सामने पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में गिरावट से नुकसान होने का जोखिम मौजूद है। इन जलवायु झटकों से बचने के लिए बफर का निर्माण इससे होने वाले नुकसान की तुलना में किफायती है। दूरदर्शी कार्यकारी अधिकारियों के लिए यह वास्तविकता तीन मानसिक बदलावों की जरूरत बताती है। लचीलेपन (रेजिलियंस) को अपनी बैलेंस शीट का सबसे अच्छा दोस्त मानें, आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने के बजाय साझी निर्भरता का एक नेटवर्क मान कर चलें और वेस्ट यानी कचरे को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में देखें। इस दिशा में तीन व्यावहारिक कदमों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है।

पहला, जलवायु संकट के झटकों को सहने के लिए संचालन और सप्लाई चेन को नए सिरे से तैयार करें। दशकों से एशिया-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आपदा के आर्थिक नुकसान के आधे हिस्से का सामना कर रहे हैं। बीमा में 'सुरक्षा अंतर' के साथ, पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से वैश्विक नुकसान 320 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया था। भारत में चार में से तीन जिले बाढ़, सूखे या लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आपकी पूरी वैल्यू चेन किसी जलवायु झटके का सामना कर सके। यह संचालन से संबंधित जोखिम को घटाने का सबसे बेहतरीन उपाय है।

दूसरा, क्लाइमेट एक्शन को महज अपनी नीति नहीं, बल्कि अपने उत्पाद का मुख्य हिस्सा बनाएं। इस दशक में वही कंपनियां जीतेंगी, जो उन समाधानों का निर्माण और विक्रय करेंगी, जिसकी भारत को जरूरत है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के एक रिसर्च के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में 2021-22 में कार्यरत भारतीयों की संख्या 47 प्रतिशत बढ़ी है और यह लगातार बढ़ रही है। इस दशक में केवल अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन का बाजार आधा ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है।

तीसरा, एक किफायती और स्वच्छ भविष्य के लिए निवेश करें। नए बिजली उत्पादन के सबसे किफायती स्रोत के रूप में स्वच्छ ऊर्जा के उभरने के साथ, अब पर्यावरणहितैषी होना सबसे किफायती विकल्प है। भारत ने 15 वर्षों में सौर ऊर्जा दरों को 90 प्रतिशत तक घटाया है। आज बैटरी स्टोरेज के साथ नए सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली नए कोयला संयंत्रों की बिजली से सस्ती है।

संयुक्त राष्ट्र के आगामी जलवायु सम्मेलन 'कॉफ्रेंस ऑफ पार्टीज' (कॉप30) जलवायु वित्त के तहत खरबों की धनराशि जुटाने पर जोर देगा। 2030 तक हमारी ऊर्जा मांग यूरोपीय संघ से अधिक हो जाने के साथ भारतीय व्यवसायों के लिए विकल्प बहुत ही स्पष्ट हैं। भविष्य का निर्माण सबसे विशाल से नहीं, बल्कि सर्वाधिक लचीलेपन और दूरदर्शिता से होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

## एम्स में हिंदी

हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई आरंभ करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी एम्स में मेडिकल शिक्षा, शोध और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का जो दिशानिर्देश जारी किया है, वह हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाने की उसकी नीति का ही परिचायक है. यह बदलाव अस्पतालों के किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इससे रोजाना के कामकाज, पत्र व्यवहार, नोटिंग वगैरह में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा. मसलन, बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान अंग्रेजी का इस्तेमाल कम करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात कही गयी है, तो संस्थान में लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में तैयार कराने का निर्देश दिया गया है. एम्स के सभी अनुभागों को निर्देश दिये गये हैं कि इसकी प्रगति रिपोर्ट भी भेजी जाये. इस बदलाव का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए ज्यादा सुलभ और पारदर्शी बनाना है. एम्स की पढ़ाई में भी हिंदी को प्रोत्साहित करने के बारे में कहा गया है. निर्देश जारी किया गया है कि हिंदी में छपी पुस्तकें खरीदी जायें और शोध कार्य हिंदी में किये जाने को प्रोत्साहित-सम्मानित किया जाये. हालांकि छात्रों के लिए हिंदी को अपनाने की व्यवस्था अभी वैकल्पिक रहेगी. लिहाजा, जो छात्र अंग्रेजी में ही पढ़ाई कर सकते हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता. दरअसल, जिन राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करायी जा रही है, वहां भी अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्दों को उसी रूप में रखा गया है, उनका हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है. फिर एम्स में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि हिंदी की किताबें न होने के साथ-साथ एम्स में दक्षिण भारत के अनेक छात्र पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए हिंदी में पढ़ाई करना कठिन होगा. अलबत्ता स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दिशानिर्देश बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें मरीजों के कार्ड पर दवाओं के नाम हिंदी में लिखे जाने की बात कही गयी है, ताकि आम लोगों को जानकारी आसानी से समझ में आये. अगर एम्स, दिल्ली की बात करें, तो इसके ओपीडी में रोज आने वाले हजारों मरीजों में से ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, जो अंग्रेजी में दवा का नाम पढ़कर कई बार गलत दवा ले लेते हैं. खासकर वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षा से वंचित लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है. नये दिशानिर्देश से इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी.

**सभी एम्स में मरीजों के कार्ड पर दवाओं के नाम और सलाह हिंदी में लिखे जाने के स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है. इससे खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को लाभ होगा.**

# ट्रंप का एशिया दौरा, निशाने पर भारत

**प्रभु चावला**
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

**ट्रंप का एशिया दौरा क्या भारत को अलग-थलग करने के उद्देश्य से आयोजित था, जो अपनी आबादी की ताकत और नवाचार से लगातार आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है? मोदी को कमतर करने की कोशिश में ट्रंप ज्यादा ही जोखिम ले रहे हैं. डिजिटल क्रांति और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ऊंची छलांगें लगा रहा भारत निषेध, प्रतिबंध या रोकथाम की परवाह नहीं करता. भारत की साझेदारी मॉस्को से वाशिंगटन तक विस्तृत है, ऐसे में, इसका कद छोटा करने की कोशिश भ्रामक है. बहुध्रुवीय विश्व का जो सूर्य उग रहा है, मोदी उसके अग्रदूत हैं. ग्लोबल साउथ के उभार के बीच ट्रंप के एकध्रुवीय विश्व का सपना बिखर सकता है.**

आसियान के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कद्दावर व्यक्ति की तरह पहुंचे. फिर जोश में अपनी मुट्ठियां लहराते हुए वह पारंपरिक नर्तकों की टोली में शामिल हो गये. इस तरह कुआलालंपुर में अपने रूटीन आगमन को उन्होंने अमेरिकी धूम-धड़ाके में तब्दील कर दिया, जिसके दृश्य एक से दूसरे महादेश तक वायरल हुए. जो इलाका लंबे समय से जटिल वैश्विक ताकतों के असर से प्रभावित है, वहां ट्रंप का व्यवहार पछतावे की भावना से रहित एक वर्चस्ववादी की तरह का था. मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया के उनके तूफानी दौरे का कारण दोस्तों व शत्रुओं को अपनी शर्तें मनवाने की मंशा से आयोजित था. अपनी यात्रा के जरिये उन्होंने एकध्रुवीय विश्व का संदेश दिया, जहां अमेरिका ही वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और असर तय करता है.

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का गवाह बनते हुए उन्होंने खुद को एक ऐसे शांतिदूत के रूप में पेश किया, जिसने दशकों पुराने सीमा विवाद का हल निकाला है. 'यह बहुत बड़ा कदम है, दूसरा कोई यह काम नहीं कर सकता था', ट्रंप ने कहा. यह उनका एक ऐसा दांव था, जिससे न सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के सीमांत में स्थिरता की गारंटी बनी, बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी अब यहां के संसाधनों का अबाध दोहन कर सकेंगी. मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से गलबहियां के साथ ट्रंप ने वहां के उद्यमियों से अमेरिकी बुनियादी ढांचों और टेक कंपनियों में 70 अरब डॉलर के निवेश का आश्वासन भी हासिल किया. इससे जहां अमेरिका में अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा, वहीं कुआलालंपुर भी वाशिंगटन से जुड़ा रहेगा. टोक्यो में ट्रंप ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की तथा रक्षा संबंध मजबूत करने का दबाव भी डाला. वहां संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने आदतन शेखी बघारते हुए कहा, 'जापान हमारा बेहद उपयोगी साझेदार है, लेकिन हम न्यायपूर्ण समझौता करना चाहते हैं, किसी को अनुचित लाभ नहीं दे सकते'. ट्रंप के एशिया दौरे का चरम दक्षिण कोरिया में दिखा, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम दोनों के बीच शानदार बातचीत हुई- चीन ताकत का महत्व समझता है.' उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का भी खुलासा किया, जिसके तहत चीन द्वारा बौद्धिक संपदा और अपने बाजार तक पहुंच देने के वादे के बदले अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी वापस ली है. बाद में उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ 18.8 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात का समझौता किया. वहां उनका जोर शांति स्थापना और परमाणु मुक्त होने पर था. लेकिन शांति के पुजारी होने का उनका दावा तब खोखला लगा, जब उन्होंने घरेलू नीति में आक्रामकता का परिचय दिया. युद्ध रोकने व वैश्विक स्थिरता स्थापित करने के दावों के बीच ट्रंप ने जब दशकों से जारी प्रतिबंध के बीच अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण करने की बात कही, तो यह उनके व्यक्तित्व के विरोधाभास के बारे में बताता था. आलोचकों का मानना है कि ट्रंप का यह दौरा एशिया में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को कमतर करने की रणनीतिक कोशिश थी.

मोदी ग्लोबल साउथ की एक ताकतवर आवाज हैं, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करते हैं. जी-20 जैसे मंचों के जरिये वह पश्चिमी देशों की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति के खिलाफ विकासशील देशों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं. रूस और यूक्रेन के तनावों के बीच अपने निरपेक्ष रवैये से पश्चिमी टेक कंपनियों का निवेश आकर्षित कर भारत ने खुद को एक लचीले राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, जिसकी तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित ट्रंप की यह यात्रा दरअसल मोदी के इस उभार को रोकने की मंशा से थी और नयी दिल्ली को नजरअंदाज कर भारत के पड़ोसियों व प्रतिद्वंद्वियों से संवाद करने के उनके इरादे को बताती थी. मोदी को 'गहरे दोस्त' और 'सख्त आदमी' कह कर ट्रंप मोदी को संकट में डालने का काम कर रहे थे.

अपने एशिया दौरे में ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और जापान पर टैरिफ में कमी की. उन्होंने ऐसे समझौते किये, जिससे ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगे दबाव कम हुए. चरणबद्ध कटौती के जरिये उन्होंने चीन के साथ रिश्ते में नरमी बरतने का भी संकेत दिया. पर भारत को ऐसी कोई राहत नहीं मिली. भारतीय इस्पात, एल्युमीनियम और टेक्सटाइल्स पर लगे टैरिफ पहले जितने ही ऊंचे हैं. टोक्यो में ट्रंप ने कहा, 'भारत एक महान देश है, पर उसने हमें भारी चोट पहुंचायी है, इसलिए हमने भी करारा जवाब दिया'. ट्रंप की यह टिप्पणी उनकी हालिया नीति के अनुरूप ही है, जिसके तहत भारत की निर्यात महत्वाकांक्षा को दंडित किया गया है, जबकि दूसरे देशों को पुरस्कृत किया जा रहा है. ट्रंप का यह पक्षपाती आचरण दक्षिण पूर्व एशिया में भी दिखा, जहां उन्होंने अमेरिकी निर्यातों पर शुल्क छूट के बदले मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के साथ व्यापार ढांचे की घोषणा की. ट्रंप ने जान-बूझकर भारत को इससे अलग ही नहीं रखा, बल्कि दक्षिण चीन सागर विवाद के संदर्भ में वियतनाम से वाशिंगटन की नजदीकी भारत को घेरने की अमेरिकी रणनीति के बारे में ही बताती है. ट्रंप उन देशों से बेहतर रिश्ते बना रहे हैं, जो भारत के उभार से चिंतित हैं. एशियाई देशों में हुआ उनका भव्य स्वागत अमेरिकी शक्ति के प्रति महादेश के आकर्षण के बारे में ही बताता है.

ट्रंप का यह दौरा क्या भारत को अलग-थलग करने के उद्देश्य से आयोजित था, जो अपनी आबादी की ताकत और नवाचार से लगातार आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है? मोदी को कमतर करने की कोशिश में ट्रंप ज्यादा ही जोखिम ले रहे हैं. डिजिटल क्रांति और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ऊंची छलांगें लगा रहा भारत निषेध, प्रतिबंध या रोकथाम की परवाह नहीं करता. भारत की साझेदारी मॉस्को से वाशिंगटन तक विस्तृत है, ऐसे में, इसका कद छोटा करने की कोशिश भ्रामक है. ट्रंप अपनी मनमानी शैली जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, पर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करने की कोशिश में उन्हें झटका लग सकता है. बहुध्रुवीय विश्व का जो सूर्य उग रहा है, मोदी उसके अग्रदूत हैं. लिहाजा ग्लोबल साउथ के उभार के बीच ट्रंप के एकध्रुवीय विश्व का सपना टूट और बिखर सकता है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

# विश्व कप जीत नया इतिहास रचा हमारी बेटियों ने

**अभिषेक दुबे**
वरिष्ठ खेल पत्रकार
abhishekdubey1975@gmail.com

**हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह जीत आने वाले कई दशक तक भारत में महिला खेल की दिशा और दशा तय करेगी. पहले कोई लड़की क्रिकेट खेलना चाहती थी, तो सवाल होता था, क्यों? लेकिन दो नवंबर, 2025 को हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में विश्व कप जीतने के बाद सवाल होगा- क्यों नहीं?**

मायानगरी मुंबई और बॉलीवुड की फिल्मों ने न जाने कितने सपनों को सच होते हुए अपने कैनवास पर उतारा है. पर रविवार की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वह ब्लॉकबस्टर रिलीज किया, जो आने वाले कई दशक तक भारत में महिला खेल की दिशा और दशा तय करेगा. हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा सिर्फ इस ब्लॉकबस्टर के अहम किरदार नहीं हैं, बल्कि वे नाम हैं, जो आने वाले पीढ़ियों को गेंद और बल्ले से वैसा ही कमाल करने के लिए उत्साहित करेंगे, जैसा किसी दौर में कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत ने किया था. इतिहास में कई तारीख मील का पत्थर साबित होती हैं. पहले कोई लड़की क्रिकेट खेलना चाहती थी, तो सवाल होता था, क्यों? लेकिन दो नवंबर, 2025 को हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में विश्व कप जीतने के बाद सवाल होगा- क्यों नहीं?

भारतीय पुरुष क्रिकेट आज जो भी है, उसकी नींव कपिल देव की कप्तानी में 1983 वर्ल्ड कप की जीत के साथ लॉर्ड्स के मैदान में रखी गयी. भारतीय महिला क्रिकेट आगे जिस मंजिल तक पहुंचेगी, उसकी नींव हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विश्व कप की जीत के साथ नवी मुंबई में रखी गयी. विश्व क्रिकेट का ग्लोबल ऑर्डर भी 1983 में बदला और क्रिकेट का केंद्र इंग्लैंड से भारत बन गया. यह कोई इत्तफाक नहीं कि महिला विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीम खिताब की दौड़ में नहीं थी. इससे पहले हुए 12 महिला विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने सात बार, इंग्लैंड ने चार बार और न्यूजीलैंड ने एक बार जीता था. लेकिन नवी मुंबई में नया विश्व चैंपियन बनना तय था.

भारत के चैंपियन बनने से तय हो गया है कि भारत लंबे समय तक पुरुष व महिला, दोनों क्रिकेट की आर्थिक धुरी बने रहने में सफल होगा. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को महाशक्ति बनने के लिए दो चरणों से गुजरना पड़ा- 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में इंग्लैंड में जीत मिली और 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत जीता. महिला क्रिकेट टीम ने यह प्रक्रिया अब विश्व चैंपियन बन कर पूरी की है. वर्ष 2017 और 2022 के विश्व कप में नाकामी ने हरमनप्रीत कौर को इस कदर बदला कि वह सिर्फ जीत के लिए जीने लगीं. इस विश्व कप में लगातार तीन हार के बावजूद हरमनप्रीत ने हार न मानते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेली. आधुनिक खेल को जिंदा रखने के लिए एक ब्रांड चाहिए और स्मृति मंधाना के तौर पर भारतीय महिला टीम के पास वह बड़ा ब्रांड है. भारतीय महिला टीम का विश्व कप अभियान प्रतिका रावल के लिए एक सपने का हकीकत बनने जैसा था. स्मृति के साथ वह भारत को ठोस शुरुआत दिला रही थीं, पर एक शतकीय पारी खेलने के बाद प्रतिका चोटिल होकर टीम से बाहर हो गयीं. शेफाली वर्मा एक साल से टीम से बाहर थीं. प्रतिका के चोटिल होने पर टीम में आयीं शेफाली ने फाइनल में न सिर्फ एक बहुमूल्य पारी खेली, बल्कि नाजुक मोड़ पर दो विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. जेमिमा विश्व कप से पहले और विश्व कप के दौरान खराब फॉर्म से जूझ रही थीं. पर सेमीफइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वह पारी खेली, जिसे जानकार विश्व कप क्रिकेट इतिहास की सबसे असरदार पारी मानते हैं. इस ऐतिहासिक पारी और जीत के बाद जिस साफगोई और ईमानदारी के साथ जेमिमा ने अपनी बात रखी, वह युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी. इसके अलावा दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, क्रांति गौड़ जैसों का प्रदर्शन और संघर्ष बहुत प्रभावित करने वाला रहा. कोच अमोल मजूमदार का भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं हो सका. फिर भी उन्होंने क्रिकेट से नाता नहीं तोड़ा. उनके जुनून को देख उन्हें महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया. उन्होंने टीम को हुनर के साथ भरोसा दिया, पारंपरिक ताकतों को आधुनिक क्रिकेट से जोड़ा और एक टीम तैयार की, जो विश्वविजेता बनी. इस टीम में कहानियां और कई हैं. यह जीत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'बेटी खिलाओ' के नारे को अमली जामा पहनायेगी.

यह ब्लॉकबस्टर भले दो नवंबर, 2025 को रिलीज हुई हो, पर इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जब महिला क्रिकेट टीम को सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया. इस ब्लॉकबस्टर के प्रोड्यूसर भले ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ प्रमुख जय शाह हों, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नयी गति दी है, लेकिन इसके पहले नायक महेंद्र कुमार शर्मा और हमीदा हबीबुल्लाह थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी. दो नवंबर, 2025 को ट्रॉफी हासिल करने के लिए स्टेज पर भले ही हरमनप्रीत कौर समेत 15 महिला क्रिकेटर थीं, लेकिन इस अभियान को यहां तक पहुंचाने में शांता रंगास्वामी, डायना एडुलजी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, संध्या अग्रवाल और अंजुम चोपड़ा समेत कई पूर्व खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने लाख बाधाओं के बावजूद क्रिकेट खेलते हुए विश्व चैंपियन बनने का सपना देखा था. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

### देश दुनिया

## वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयासों की दरकार

दो नयी वैश्विक रिपोर्ट ने एक बार फिर बांग्लादेश में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते संकट और उसे बनाये रखने वाली राजनीतिक जड़ता को उजागर कर दिया है. लैंसेट काउंटडाउन 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 2.25 लाख मौतें मानव जनित वायु प्रदूषण के कारण हुईं. वहीं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में यह संख्या बढ़कर 2.7 लाख पर पहुंच गयी. दोनों रिपोर्ट में बांग्लादेश को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना गया है. इसके बावजूद यहां की सरकारें वायु प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल मानने में विफल रही हैं. यह निष्क्रियता अक्षम्य है और इसके लिए नीतिगत विरोधाभास जिम्मेदार है. अकेले 2023 में, बांग्लादेश ने जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देने में 8.2 अरब डॉलर खर्च किये और उन्हीं उद्योगों को लाभ पहुंचाया जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं. ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 2016 से चौगुनी हो गयी है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी एक प्रतिशत से भी कम रही है. यह आर्थिक असंतुलन का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां जनता का पैसा प्रदूषणकारी ऊर्जा पर खर्च किया जा रहा है, जबकि नागरिक इसकी कीमत बीमारियों, उत्पादकता में कमी और अकाल मृत्यु के रूप में चुका रहे हैं. लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में गर्मी के कारण श्रम हानि से अर्थव्यवस्था को 24 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा, जो नैतिक और आर्थिक विफलता से कम नहीं है. वायु प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर सरकार का खंडित दृष्टिकोण भी चिंताजनक है. हमारे पास स्वच्छ वायु अधिनियम, उद्योगों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन मानक, या केंद्रीकृत निगरानी या जवाबदेही तंत्र नहीं है. बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को समझना होगा कि वायु प्रदूषण का संकट महज पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है. हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, उत्सर्जन सीमा लागू करने, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने और एक स्वतंत्र वायु गुणवत्ता निगरानी प्राधिकरण बनाने को प्राथमिकता देनी होगी.

The Daily Star

### जन्मशती विशेष

# विभाजन की पीड़ा को जीने वाले फिल्मकार थे ऋत्विक घटक

**प्रो डॉ कृष्ण कुमार रत्तू**
वरिष्ठ लेखक एवं मीडिया विश्लेषक
drkkrattu@zohomail.com

भारतीय फिल्मों की संघर्षशील अभिव्यक्ति के नायक निर्माता-निर्देशक ऋत्विक घटक की आज जन्मशती है. उन्हें याद करना भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन स्मृतियों को स्मरण करना है, जिनमें भारतीय सिनेमा का यथार्थ दिखाई देता है. ऋत्विक घटक को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समानांतर सिनेमा की नींव डाली और भारतीय सिनेमा को एक नयी सोच दी. उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के दुख-दर्द को जिस तरह परदे पर उकेरा, वह आम जनमानस को छूता है. उनके सिनेमा में भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जमीन का दुख-सुख बराबर दिखता है. यही उनकी खूबी है. वे एक अद्भुत फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक भी थे.

भारतीय फिल्म निर्देशकों के बीच घटक का स्थान सत्यजीत रे और मृणाल सेन के समान है. ऋत्विक घटक का जन्म चार नवंबर, 1925 को ढाका में हुआ था. पर विभाजन के बाद वह कोलकाता आ गये. छह फरवरी, 1976 को मात्र 50 वर्ष की आयु में ही वह इस दुनिया से विदा हो गये. वर्ष 1947 में विभाजन के बाद जिस तरह लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर कोलकाता आये, उसे ऋत्विक घटक कभी भूला नहीं सके. सिनेमा की दुनिया में उनका यह अनुभव बखूबी नजर आता है, जिसने सांस्कृतिक विच्छेदन और निर्वासन के लिए एक अधिभावी रूपक का काम किया और उनके बाद के रचनात्मक कार्यों को एक सूत्र में पिरोया. वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने भी उनके कार्यों को समान रूप से प्रभावित किया. उन्होंने विभाजन की पीड़ा को जिस तरह अपनी फिल्मों में उकेरा है, वह गहरे प्रभावित करती है.

**ऋत्विक घटक**
(04 नवंबर, 1925–06 फरवरी, 1976)

ऋत्विक घटक के रचनात्मक जीवन की बात करें, तो 1948 में, उन्होंने अपना पहला नाटक 'कालो सायर' (द डार्क लेक) लिखा और ऐतिहासिक नाटक 'नबान्न' के पुनर्लेखन में हिस्सा लिया. उन्होंने नाटकों का लेखन, निर्देशन करने के साथ ही उसमें अभिनय भी किया. 'बर्टोल्ट ब्रेख्त' और 'गोगोल' को बंगला में अनुवादित किया. वर्ष 1957 में, उन्होंने अपना अंतिम नाटक 'ज्वाला' (द बर्निंग) लिखा और निर्देशित किया. उन्होंने फिल्म जगत में निमाई घोष के 'छिन्नमूल' (1950) के साथ अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में प्रवेश किया. वर्ष 1952 में घटक ने 'नागोरिक' का निर्देशन किया, पर यह फिल्म उनके मरने के बाद 1977 में ही रिलीज हो पायी. घटक की ये दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुईं. उन्होंने अपने शुरुआती कार्यों में नाटकीय और साहित्यिक पहचान पर जोर दिया और एक वृत्तचित्रीय यथार्थवाद, जो लोक रंगमंचों से ली गयी शैली के प्रदर्शन से युक्त होता था, को ब्रेख्तियन फिल्म निर्माण के उपकरणों के साथ संयोजित किया. 'अजांत्रिक' (1958) उनकी पहली व्यावसायिक रिलीज थी. निर्जीव वस्तु को दर्शाने वाली यह भारत की कुछ प्रारंभिक फिल्मों में से एक है. हिंदी फिल्म 'मधुमती' (1958), पटकथा लेखक के रूप में घटक की बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, यह पुनर्जन्म के विषय पर बनी सबसे पहली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म के लिए घटक ने सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्मफेयर पुरस्कार का अपना पहला नामांकन अर्जित किया था.

बतौर निर्देशक और पटकथा लेखक ऋत्विक घटक ने 'नागोरिक' (नागरिक) (1952), 'अजांत्रिक' (अयान्त्रिक, दयनीय भ्रान्ति) (1958), 'बाड़ी थेके पालिए' (भगोड़ा) (1958), 'मेघे ढाका तारा' (बादलों से छाया हुआ सितारा) (1960), 'कोमोल गंधार' (ई-फ्लैट) (1961), 'सुवर्णरेखा' (1962), 'तिताश एकटि नदीर नाम' (तिताश एक नदी का नाम है) (1973), 'जुक्ति, तोक्को आर गोप्पो' (कारण, बहस और एक कहानी) (1974) बनायी. वहीं 'मुसाफिर' (1957) 'मधुमती', (1958), 'स्वरलिपि' (1960), 'कुमारी मन' (1962), 'दीपेर नाम टिया रोंग' (1963), 'राजकन्या' (1965) के वे पटकथा लेखक रहे. उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध फिल्में रहीं- 'मेघे ढाका तारा', 'कोमल गंधार' और 'सुवर्णरेखा'. ये तीनों फिल्में कलकत्ता (वर्तमान में कोलकाता) पर आधारित एक त्रयी हैं, जिसमें शरणार्थी जीवन की स्थितियों का चित्रण किया गया है. वर्ष 1966 में घटक पुणे चले गये, जहां उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआइआइ) में शिक्षण का कार्य किया. हालांकि एफटीआइआइ में उनके फिल्म शिक्षण का कार्यकाल संक्षिप्त था, फिर भी एफटीआइआइ में बिताये गये वर्षों के दौरान उन्होंने दो छात्र फिल्मों- 'फियर' और 'रौन्डेवू' के निर्माण में योगदान किया.

उनकी अंतिम फिल्म आत्म कथात्मक थी, जिसका नाम था 'जुक्ति, तोक्को आर गोप्पो'. इसमें उन्होंने मुख्य चरित्र नीलकंठो (नीलकंठ) की भूमिका निभायी थी. बीमारी और असमय निधन के कारण उनकी कई फिल्में अधूरी ही रह गयीं. ऋत्विक घटक भारतीय सिनेमा के युगपुरुष थे और हमेशा रहेंगे. वे भारतीय सिनेमा की एक ऐसी धरोहर हैं, जो सदैव हमारी स्मृतियों में बसे रहेंगे.

### आपके पत्र

**सीबीएसइ परीक्षा की तिथि घोषित**

सीबीएसइ की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तिथि घोषित हो गयी है. परीक्षार्थियों के पास तैयारी के लिए तीन महीने का समय बचा है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि वे अभी से लिखने का अभ्यास करें. लिखकर याद करने और दोहराने से न केवल प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह याद रह पायेंगे, बल्कि इससे लिखने का अभ्यास भी हो जायेगा. इस कारण परीक्षा हॉल में आप पूरे प्रश्नों के उत्तर लिख पायेंगे. यहां अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को बिना किसी डर के परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें.

**राधिका सहाय**, पटना

**मशीन से हो नालों की सफाई**

सेप्टिक टैंक या नालों की सफाई करते हुए दम घुट जाने से अक्सर सफाईकर्मियों की मृत्यु हो जाती है. अखबारों में खबरें छपती हैं, और फिर हम सब इस घटना को भूल जाते हैं. मृतकों की कोई चर्चा भी नहीं होती और परिवार वाले इसे दुर्घटना मानकर रो-धोकर चुप हो जाते हैं. जबकि यह पूरी तरह से संबंधित विभाग की लापरवाही है. आज जबकि हर काम के लिए मशीनें बन चुकी हैं, तो फिर सेप्टिक टैंक या नालों की सफाई के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते.

**राजेश कुमार**, धनबाद

**पोस्ट करें :** प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPapersPaid

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 04-11-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMA12 User: cci Time: 11-03-2025 22:58 Color:


# नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 4 नवंबर 2025


जीवन में समझौता करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है।
*– डेल कार्नेगी, अमेरिकी लेखक*

## भारत की मुश्किल

सितंबर 2018 में चीन पर 10% टैरिफ लगाने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि पेइचिंग कई बरसों से अमेरिका का फायदा उठा रहा है और उन्हें पता है कि उसे कैसे रोकना है। वह ट्रंप का पहला कार्यकाल था और उस पूरे रेजीम में चीन को लेकर उनका रवैया ऐसा ही सख्त रहा। लेकिन, दूसरे कार्यकाल के 10 महीने के भीतर ही उनका रुख बिल्कुल उल्टा हो चला है। अब वह चीन को खतरे के रूप में नहीं, उसकी दोस्ती को स्थायी शांति और सफलता के लिए जरूरी मान रहे हैं।

**US-चीन समझौता ।** डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की और इसके बाद कई अहम घोषणाएं हुईं। रेयर अर्थ मिनरल्स, ट्रेड टैरिफ और अमेरिकी कृषि उत्पाद पर जो गतिरोध था, वह सुलझता दिख रहा है। दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात यह नहीं कि दोनों महाशक्तियों के बीच सुलह हो गई, बल्कि यह है कि दोनों एक ऐसे गठजोड़ की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक की कोशिशें असफल रही हैं।

AI Image

ट्रंप-शी में डील

**चीन प्लस वन ।** यह पार्टनरशिप इस सदी के सबसे बड़े भू-राजनीतिक बदलाव की वजह बन सकती है और इसका असर जिन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, उनमें भारत भी है। अभी तक माना जा रहा था कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका उसके बरक्स भारत को खड़ा कर रहा है। कोरोना के दौर में चीन प्लस वन पॉलिसी चली, तो चर्चा में भारत ही रहा और इसका उसे फायदा भी मिला। अब जब वॉशिंगटन और पेइचिंग करीब आ रहे हैं, तो यह पॉलिसी भी शायद ज्यादा न चल पाए।

**रेयर अर्थ ।** अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर लड़ रहे चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ा। पिछले ही महीने जब चीन ने निर्यात से जुड़े नए नियम लागू किए तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे सभी की लड़ाई बताते हुए भारत से मदद मांगी। लेकिन, अब ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अमेरिका को छोड़कर भारत और बाकी दुनिया की है।

**नई नीति ।** नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच अभी तक व्यापार समझौता नहीं हुआ है। रूस के साथ तेल खरीद भी भारतीय कंपनियों ने कम कर दी है। दूसरी ओर, चीन को ट्रंप छूट दे रहे हैं और टैरिफ भी कम कर दिया है। ये संकेत हैं कि इन दोनों देशों को लेकर भारत को अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। और बात केवल व्यापार की नहीं है, Quad जैसे गठजोड़ का भविष्य भी अधर में है।

### ऐवें कुछ भी

## एक बब्बर शेर अर्ज़ है...

आलोक सिंह भदौरिया

**एक चुटकुला** सुना था कि जेल में बंद एक कैदी दूसरे से पूछता है कि तुम यहां कैसे आए? दूसरा बेरुखी से जवाब देता है, सरकार को कंपटीशन पसंद नहीं। पहले वाले ने कहा- खुलकर कहो। तो दूसरा पूरी तरह से खुल गया, बोला- सरकार नोट छापती है, हम भी छापने लगे थे। हमारे ज्यादा असली लगते थे। सरकार को बर्दाश्त न हुआ, हम पकड़े गए।

ऐसा ही यूपी के जिला बाराबंकी में हुआ। यहां पर देवा शरीफ का एक युवा निहायत ही पर्यावरण प्रेमी है। उसे जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। एक दिन उसने सोचा कि प्रांत के इस हिस्से में कोई बब्बर शेर नहीं है। इस पर कुछ किया जाना चाहिए। उसने कुछ प्रयास किया और बाराबंकी के सुरम्य जंगलों में बब्बर शेर की एक तस्वीर खींचने में कामयाबी पाई। इतना ही नहीं, उसके पगमार्क तक के फोटो खींच लिए।

अपनी उपलब्धि को उसने नवंबर पहले सप्ताह में वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी पर शेयर कर दिया। इस खबर ने समाज के एक बड़े वर्ग को तुरंत प्रभावित किया। इनमें वे लोग बड़ी संख्या में थे जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना का लाभ उठाने को तैयार नहीं थे। ये जंगलवॉक के बहाने सुबह-शाम लोटा लेकर जंगल जाते थे। बब्बर शेर की इस खबर से उनकी दिनचर्या, स्वेच्छाचारिता और पर्यावरण प्रेम में फौरी तौर पर बदलाव हुआ।

लेकिन इस पर सबसे ज्यादा ऐतराज वन विभाग को हुआ। वह मानने को राजी नहीं हुआ कि प्रांत के इस हिस्से में बब्बर शेर मौजूद हो सकता है। बाराबंकी पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाई और कुछ घंटों में वह होनहार युवा थाने में पाया गया। थानेदार महोदय ने तुरंत ही उसके साथ एक पॉडकास्ट किया। इसमें युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि माईबाप हमने AI की मदद से शेरे बब्बर का फोटो बनाया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा होगा कि जब अफ्रीका से करोड़ों खर्च करके मध्यप्रदेश के कूनो में चीते लाए जा सकते हैं तो क्या हम बाराबंकी में बब्बर शेर लाने की वैचारिक पहल नहीं शुरू कर सकते?

### बोल वचन

शैलेंद्र पांडेय

## घने अर्थों वाला गाछ

**कहते हैं कि** हर बात का एक समय होता है, लेकिन अगर किसी की आदत हो इसके पहले ही उम्मीद बांध लेने की, तो उसी के लिए बंगाल के बुजुर्गों ने कहा है, 'गाछे कटहल, मुखे तेल'।

AI Image

मैथिली में आकर मुख की जगह होंठ हो जाते हैं, 'गाछ में कटहल, होंठ पर तेल' - यानी कटहल अभी पेड़ पर ही है और तैयारी शुरू हो गई। यहां गाछ का मतलब है पेड़। गाछ संस्कृत के गच्छ से बना है, जिसका अर्थ होता है जाना, चलना, बढ़ना। पेड़ भी तो आखिर बढ़ते ही हैं। यह शब्द बांगला, मैथिली और भोजपुरी भाषा में इस्तेमाल होता है। बांगला में गाछी भी बोलते हैं - पेड़ों के झुरमुट या बाग-बगीचे को। पेड़ जब छोटा हो, तो भी वह 'गाछी' या 'गछिया' हो जाता है। उत्तर बंगाल में एक पान होता है गाछ, जबकि इस इलाके में काली मिर्च को गाछमरिच भी बोलते हैं। हिंदी शब्दसागर के मुताबिक, खजूर की उस नरम कोंपल को गाछी कहा जाता है जो तरकारी बनाने में इस्तेमाल होती है। पशुओं की पीठ पर बोझा लादने से पहले जो बोरा डालते हैं, वह भी गाछी है। जैसे इस शब्द से जुड़ी कहावत समय की अहमियत बताती है, वैसे ही इसमें समाज से जुड़ा अभिमान भी है। मगही में कहते हैं - गाछ से गिरल बानर यानी समाज से अमान्य व्यक्ति।

### जो कमाल कपिल देव की टीम ने किया था, हरमनप्रीत कौर की टीम ने भी वही किया है

# इस वर्ल्ड कप जीत में 1983 वाली बात है

मनोज जोशी

**52 रनों** की जीत से 52 साल का सूखा खत्म। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दिखाया कि कैसे गिरकर उठा जाता है। कैसे अपनी असफलता को सफलता में बदला जाता है। ऐसा ही कुछ 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल की टीम ने किया था। उस कामयाबी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। आज हरमन और उनकी टीम ने उन्हीं लम्हों की याद ताजा करा दी है।

**1983 से समानताएं ।** क्या अमनजोत कौर का साउथ अफ्रीका की वन वूमन आर्मी लौरा बोलवाट का कैच कपिलदेव के गॉर्डन ग्रीनिज के कैच को लपकने की याद ताजा नहीं कराता? क्या शेफाली वर्मा अपने हर शॉट के साथ उस वक्त के ओपनर श्रीकांत की याद फिर से जिंदा नहीं कर दी? क्या दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड खेल में 1983 के मोहिंदर अमरनाथ और 2011 के युवराज सिंह की झलक नहीं दिखी? क्या स्मृति मांधना की 18 नंबर की जर्सी हाल में विराट कोहली की 18 नंबर की जर्सी की याद ताजा नहीं कराती? ऋचा घोष बतौर हिटर कुशल फिनिशर साबित हुईं। हरमन तो इस कामयाबी के साथ ICC टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तानों – कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा - की सूची में आ गई हैं।

**कई गेमचेंजर ।** दरअसल, यह एक टीम वर्क की जीत है। इस टीम को गिरकर उठना आता है। ठीक कपिल देव की टीम की तरह। तब भारत ने दो मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। इस बार लीग में एक के बाद एक हार के बावजूद टीम बिखरी नहीं। जेमिमा रॉड्रिक्स को पिछली बार वर्ल्ड कप में चुने जाने लायक भी नहीं समझा गया था। इस बार उन्हीं जेमिमा ने मुश्किल ऑस्ट्रेलिया को आसान बनाकर पीटा। शेफाली भी प्रतिका के इंजर्ड होने पर मिले मौके को दोनों हाथों से भुनाने में कामयाब रहीं। सच तो यह है कि टीम में एक नहीं, कई-कई गेम चेंजर हैं।

**फर्क भी अहम है ।** तब में और अब में फर्क इतना है कि महिला टीम को आज बड़ी धनराशि मिलने लगी है। उनके लिए विमिन्स प्रीमियर लीग (WPL) जैसी धन अर्जित करने वाली लीग शुरू हो गई है, जहां दुनिया की टॉप खिलाड़ियों के साथ खेलकर वे मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का पाठ बखूबी पढ़ चुकी हैं। 1983 में कपिल देव की टीम को इनाम देने के लिए BCCI के पास पैसे नहीं थे और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लता मंगेशकर नाइट कराके पैसे इकट्ठे किए गए थे लेकिन आज भारतीय महिला क्रिकेटरों को अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि हासिल करने का सम्मान मिला है।

**बदलेगी तस्वीर**
- महिला क्रिकेट के प्रति खेल जगत में आकर्षण बढ़ेगा
- खिलाड़ियों को कंपनियों से ज्यादा एंडोर्समेंट मिलेंगे
- स्टेडियम में दर्शकों की संख्या में और इजाफा होगा

**बढ़ेगा क्रेज ।** 2011 की तरह ही इस बार भी मुंबई नगरी टीम लकी साबित हुई। मुंबई में WPL के मैच देखने भारी भीड़ आती थी, पर दूसरे सेंटर पर महिलाओं के मैचों में दर्शकों का रवैया पुरुषों के क्रिकेट जैसा नहीं रहता था। अब संभवतः ऐसा नहीं होगा। मुंबई जैसा ही रेस्पॉन्स अब दूसरे केंद्रों में भी देखने को मिलेगा।

**एंडोर्समेंट्स में इजाफा ।** स्मृति मांधना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स और पूजा वस्त्रकर के पास कई ऐसे ब्रैंड हैं, जिनका वह प्रचार करती हैं। जल्द ही इनके एंडोर्समेंट्स में उछाल आने वाला है और टीम की बाकी क्रिकेटरों के पास भी कई कंपनियां आएंगी। ऐसा ही 1983 की वर्ल्ड कप जीत के बाद देखने को मिला था। खिलाड़ियों को नौकरी देने भी कई और कंपनियां आगे आ सकती हैं।

**टर्निंग पॉइंट ।** भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक लंबा सफर तय किया है। 2006 में महिला क्रिकेट जब BCCI के अंतर्गत आई, तब से उसकी किस्मत बदलने लगी। डोरमेटरी की जगह फाइव स्टार होटलों ने और ट्रेन सफर की जगह फ्लाइट के सफर ने ले ली। जिस महिला क्रिकेट को 19 साल पहले BCCI की एक लायबिलिटी माना जाता था, वही अब उसकी बड़ी ताकत है।

**टिके रहने की चुनौती ।** एवरेस्ट पर पहुंचना बड़ी बात है, इस पर बने रहना उससे भी बड़ी बात है। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगला वनडे वर्ल्ड कप जीतने में टीम इंडिया को 28 साल लग गए थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार महिला क्रिकेट टीम जीत की इस पटरी पर बनी रहेगी और इस कामयाबी को अगली बार भी दोहराएगी।

*(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं)*

### कांटे की बात

अगर हमें 3 नवंबर तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिलती है तो दुबई में होने जा रही ICC की बैठक में हम इस मामले को उठाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ICC हमारे साथ न्याय करेगी और हमें ट्रॉफी दिलाने में मदद भी करेगी।

**देवजीत सैकिया,** *BCCI के सचिव*

### AI की दुनिया

## प्राचीन यूनानी ज्ञान से चीन ने बनाई 1000 गुना तेज़ चिप

*1900 में यूनान के समुद्र से करीब 2000 साल पुरानी एक मशीन मिली थी – एंटीकाइथेरा। उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा गया था। अब चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी चिप बनाई है, जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकती है। इस चिप की तकनीक एंटीकाइथेरा जैसी है।*

AI Image
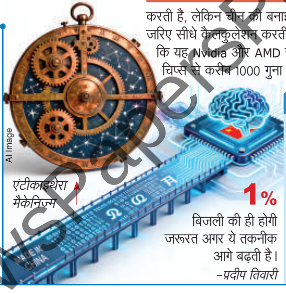


**Nvidia से भी आगे**

**मौजूदा डिजिटल** चिप 0 और 1 पर काम करती हैं, लेकिन चीन की बनाई एनालॉग चिप अपने सर्किट के जरिए सीधे कैलकुलेशन करती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि यह Nvidia और AMD जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों की चिप्स से करीब 1000 गुना आगे निकल गई है।

**1%** बिजली की ही होगी जरूरत अगर ये तकनीक आगे बढ़ती है।

*–प्रदीप तिवारी*

**RRAM का कमाल**

टेक्नॉलजी के तेज विकास में दो रुकावटें प्रमुख थीं – ऊर्जा की खपत और धीमी डेटा प्रॉसेसिंग। इस चिप ने इन दोनों का हल निकाल लिया है। यह चिप रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमरी (RRAM) पर बनी है। यह डेटा को स्टोर और प्रॉसेस, दोनों करती है।

### जनता जंक्शन — इरफ़ान

## ट्रंप के मनमौजीपन से शीत युद्ध जैसी नौबत

### कॉमन रूम

मनीष गुप्ता, न्यूयॉर्क से

**शांति के** नोबेल पुरस्कार पर नजरें गड़ाए बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की Truth Social पोस्ट ने सारी दुनिया को हिला दिया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात से ठीक पहले यह उकसावे वाला कदम था या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के 8000 किमी तक मार करने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण की प्रतिक्रिया - कहना मुश्किल है। लेकिन, उनके एक बयान ने शीत युद्ध की यादों को ताजा कर दिया।

**अनिश्चित राजनीति ।** ट्रंप का कहना है कि जब बाकी देश खुलेआम परमाणु हथियारों की रेस में शामिल हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहें? अमेरिका ने 23 सितंबर 1992 को आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद संसद के एक प्रस्ताव के जरिए 'टेस्ट मोराटोरियम' यानी परीक्षण पर रोक लगाई गई, जिसे अभी तक निभाया गया है। लेकिन, ट्रंप इसे जारी रखने के मूड में नहीं। अमेरिका में इन दिनों मीम्स चल रहे हैं कि 'भगवान और शैतान के इरादे का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर ट्रंप कब क्या बोलेंगे - यह कोई नहीं बता सकता!' ट्रंप की राजनीति हमेशा से 'बम फोड़ने' की रही है।

**अब ज्यादा खतरा ।** 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर 'लिटिल बॉय' नामक 15 किलोटन क्षमता का परमाणु बम गिराया था और तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ठीक तीन दिन बाद नागासाकी पर 'फैट मैन' नाम का थोड़ा बड़ा बम गिराया गया, जिसकी जलन आज तक चुभती है। आजकल के मेगाटन परमाणु हथियारों के सामने वे बहुत छोटे थे। आज दुनिया को खत्म करने के लिए विश्व युद्ध की दरकार नहीं है, बस एक सिरफिरा शासक चाहिए।

**नए हथियार क्यों ।** अभी पूरी दुनिया में 12,500 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसमें से अमेरिका के पास 5,225 और रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। चीन 2020 में 300 से बढ़कर आज 600 पार कर चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास 250-300, भारत और पाकिस्तान 170-170, इस्राइल 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। इतने ही बम काफी हैं पूरी दुनिया को कई बार खत्म करने के लिए।

**नाजुक स्थिति ।** अमेरिका का भारत रणनीतिक साझेदार है। लेकिन, जब अमेरिका 'तुरंत परीक्षण' जैसी बातें करता है, तो दक्षिण एशिया के लिए हालात बिगड़ सकते हैं। भारत-चीन-पाकिस्तान का परमाणु त्रिकोण पहले से ही एक डगमगाते संतुलन की डोर पर टिका है। और ट्रंप के रवैये में मनमौजीपन वाली अनिश्चितता है। किसी को नहीं पता कि कल वह किसे 'गुड फ्रेंड' कहेंगे और किसे 'बैड डील'। ट्रंप के बयान ने हमें 20वीं सदी के साये से खींचकर एक और ज्यादा तेज, ज्यादा डरावने 'शीत युद्ध' में धकेल दिया है।

*(लेखक फिल्मकार और राइटर हैं)*

## जंगलराज के जवाब में रोज़गार का वादा

हेमंत राजौरा

**बिहार में** 'जंगलराज बनाम सुशासन' दो दशकों से चुनावी विमर्श की धुरी रहा है। NDA, विशेषकर BJP और JDU, हर चुनाव में 2005 से पहले के लालू-राबड़ी शासन को जंगलराज बताकर मतदाताओं को याद दिलाने की कोशिश करती रही हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने कानून-व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में कितनी दूरी तय की है। इस बार भी NDA नेता अपने भाषणों में 2005 से पहले की स्थिति की याद दिला रहे हैं।

### अपराध में शीर्ष पर बिहार

NDA के इस पुराने नैरेटिव के सामने महागठबंधन ने अब आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों ही हर घर से एक को रोजगार और महिलाओं को मासिक सहायता जैसे वादों के जरिए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। हालांकि, महागठबंधन ने अपराध का मुद्दा भी पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मोकामा हत्याकांड और हाल के कई आपराधिक मामलों को उठाकर वह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुशासन का दावा खोखला हो चुका है। तेजस्वी NCRB के आंकड़ों के हवाले से भाषण में बता रहे हैं कि बिहार अपराध में शीर्ष पर है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार में आने पर 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे।

दरअसल, बिहार का मतदाता वर्ग बदल चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार मतदाता हैं, जिनमें से 1 करोड़ 77 लाख मतदाता 18 से 29 वर्ष के हैं। बिहार के इन युवा वोटरों ने RJD के उस शासन को देखा नहीं है। ऐसे में उन पर इस नैरेटिव का असर पड़ना आसान नहीं होगा।

### विशुद्ध राजनीति — कसौटी

लोकनीति-CSDS के 2020 के मतदान बाद सर्वेक्षण के आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं। साल 2015 में जहां सिर्फ 9% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और नौकरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 20% तक पहुंच गया। यानी पांच साल में मतदाताओं की प्राथमिकता अपराध से रोजगार की ओर निर्णायक रूप से शिफ्ट हो चुकी थी।

इसी सर्वेक्षण के अनुसार, 18 से 29 वर्ष के 37% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि 36% ने NDA को। हालांकि सर्वे के मुताबिक अधिक महिलाओं ने महागठबंधन की बजाय NDA पर भरोसा जताया था। यही वजह है कि एक बार फिर महिला वोटरों को लुभाने के लिए NDA के नेता जंगलराज के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं।

### दिल्ली से कंट्रोल

तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय नौकरियों की कमी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला कर रहे हैं कि बिहार की सरकार अब दिल्ली से कंट्रोल होती है। साथ ही वह महंगाई और असमानता के प्रश्न को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर स्थानीय असंतोष को बल देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी हमला कर रहे हैं, चाहे वह डॉनल्ड ट्रंप के सीजफायर बयान का मामला हो या भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद। राहुल गांधी का आरोप है कि BJP भले ही दुनिया में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का नैरेटिव बनाती हो, लेकिन असल में उनकी कूटनीति और आंतरिक नीतियां कमजोर हैं। देखना होगा कि राज्य के मतदाता किसके नैरेटिव और वादों पर यकीन करते हैं?

## सत्य जिनका आश्रय होता है उन्हें डर कभी नहीं सताता

श्री श्री आनंदमूर्ति

**मन हमेशा** किसी न किसी वस्तु की खोज में लगा रहता है। बिना किसी लक्ष्य या आश्रय के मन टिक नहीं सकता। यदि मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता, तो वह अनजाने में ही बुरे कर्मों की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आदत ऐसी है। इसलिए जो लोग भौतिक वस्तुओं से मन को प्रभावित नहीं होने देते, उन्हें किसी अभौतिक सत्ता से जुड़ना पड़ता है। वही है परम पुरुष, जिसका अस्तित्व अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी है।

परम पुरुष ही सत्य है, और कहा गया है - सत्ये नास्ति भयम् कश्चित्, यानी सत्य में कोई भय नहीं। जो सत्य को अपना आश्रय बनाते हैं, वे निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि परम पुरुष सबसे साहसी और निर्भीक हैं। अतः उनके शरणागत में भी यह गुण अवश्य आते हैं। सत्य ही निडर है और अंततः सत्य की ही विजय होती है। असत्य क्षणभंगुर है - आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन सत्य सदा विद्यमान रहता है।

आध्यात्मिक जगत का मार्ग सत्य से आच्छादित है। जो व्यक्ति सत्य के संकल्प से प्रारंभ करता है, वह देवत्व की ओर अग्रसर होता है। देवयान वह मार्ग है जो मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म और फिर आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलकर ऋषियों ने आप्तकाम अवस्था प्राप्त की यानी जिनकी सभी इच्छाएं सत्य के माध्यम से पूर्ण हो गई हों।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, वह अस्थायी है। फल, धन, ज्ञान या प्रसिद्धि, ये सब नश्वर हैं। लेकिन जो ज्ञान सीधे आत्मा के भीतर से प्रकट होता है, वह आप्त वाक्य कहलाता है, और वही स्थायी है। कहा भी गया है, सब दिन होत न एक समान। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन सत्य से मिला ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता।

सच्चा साधक वही है जो असत्य के क्षणिक मोह से मुक्त होकर सत्य की शरण में जाता है। असत्य की नींव पर कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता। जिसने सत्य का आश्रय लिया, वही परम ब्रह्म या परम पुरुष के साथ एक हो सकता है। यही सच्चे अर्थों में प्रगति और मुक्ति का मार्ग है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

### रीडर्स मेल

## दुर्घटनाओं से सबक लें

**3 नवंबर** का संपादकीय 'खामियों ने ली जान' पढ़ा। आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने से 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु की घटना व्यवस्था की कई खामियों को उजागर करती है। पहले भी हरिद्वार के मनसादेवी, गोवा के शिरगांव, आंध्रप्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से कई जानें जा चुकी हैं। जहां भीड़ अधिक हो वहां पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात किए जाएं।

**शकुंतला महेश नेनावा,** ईमेल से

**nbtedit@timesofindia.com** पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

# प्रवाह

75 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

पारिस्थितिकी तंत्र के पतन को रोकने के लिए, उसकी ही तरह सोचना आवश्यक है। -डगलस पी. व्हीलर

**अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक जी-2 बैठक के बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनके चीनी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय सैन्य संचार चैनल की स्थापना पर जो सहमति बनी है, उससे सवाल उठता है कि क्या वैश्विक व्यवस्था वाकई बदल रही है?**

## क्या दुनिया बदल रही है

दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक जी-2 बैठक के बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनके चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुन के बीच सैन्य संचार चैनल स्थापित करने पर जो सहमति बनी है, वह वैश्विक राजनीति में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। दिलचस्प यह है कि इससे कुछ ही घंटे पहले हेगसेथ एक अलग ही अंदाज में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आह्वान कर रहे थे कि वे दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा फैलाई जा रही अस्थिरता से मुकाबला करने के लिए दृढ़ रहें और अपनी समुद्री सेना को मजबूत बनाएं। दरअसल, दक्षिण चीन सागर, ताइवान और टैरिफ से जुड़े मुद्दों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अमेरिकी व चीनी राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय रिश्तों पर जमी बर्फ जब पिघलने लगी है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उसका असर ट्रंप के करीबी माने जाने वाले हेगसेथ के रुख में भी दिखे। यह सही है कि ट्रंप एक व्यवसायी हैं, और वह राजनीति भी उसी ढंग से करते हैं। लेकिन, चीन को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव अगर इस कदर आया है कि वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध इससे बेहतर कभी नहीं रहे, तो इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या वैश्विक व्यवस्था वाकई बदल रही है। नहीं भूला जा सकता कि दक्षिणी चीन सागर एशिया के सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जहां बीजिंग तकरीबन पूरे क्षेत्र पर, तो आसियान के सदस्य फिलीपीन, वियतनाम, मलयेशिया और ब्रुनेई भी इसके तटीय क्षेत्रों पर दावा करते रहे हैं। फिलीपीन के साथ तो चीनी समुद्री बेड़े का अक्सर टकराव होता रहता है, लेकिन चूंकि बीजिंग आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आसियान इस मामले में कड़े कदम नहीं उठा पाता। हाल ही में, भारत ने भी अमेरिका के साथ दस वर्षीय रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्वतंत्र, खुले और नियम-

आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के पीछे अमेरिका ही मुख्य शक्ति रहा है। यही नहीं, 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने क्वाड को पुनर्जीवित किया था, जब उनके प्रशासन ने पहली बार चीन को एक रणनीतिक खतरे और प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया था। ऐसे में, क्षेत्र की राजधानियों में चिंताओं व उनके सवालों के मद्देनजर सैन्य स्तर पर चीन के साथ बातचीत करने का अमेरिका का फैसला आगे क्या रंग दिखाता है, यह देखने वाली बात होगी।

## भारत एक उम्मीद को जिंदा रखे हुए है

**भारत ऐतिहासिक तौर पर पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है और उसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भी वैश्विक औसत से कम है। इसके बावजूद वह पश्चिमी देशों की अनदेखी के बावजूद कॉप सम्मेलनों में जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज उठा रहा है, उससे उम्मीदें बंधती हैं।**

वैश्विक समुदाय जलवायु रिकॉर्डों के टूटने की बढ़ती आवृत्ति, तीव्रता और पैमाने को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। औसत वैश्विक तापमान हर दशक में लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। जलवायु संकट से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) करता है। अब तक जलवायु नीति पर जिस सोच का दबदबा रहा है, वह पश्चिमी देशों की है, जो प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन या व्यापार की वस्तु मानती है।

औद्योगिक क्रांति की इसी बुनियादी सोच ने पश्चिमी देशों में आर्थिक विकास को तो बढ़ाया, लेकिन इसकी कीमत पारिस्थितिकी तंत्र की तबाही, जैव विविधता के नुकसान और जलवायु संकट के रूप में चुकाई है। जलवायु सम्मेलन (कॉप) की बैठकों में यह साफ दिखता है कि विकसित देशों ने न तो वित्तीय सहायता और न ही तकनीकी सहयोग के अपने वादों को पूरा किया है। इसके चलते बातचीत की यह पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने 2023 में नया रिकॉर्ड बनाया-57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, जो 2022 की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा क्षेत्र का रहा, जहां जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध उपयोग अब भी जारी है। यह तब है, जब वैज्ञानिक प्रमाण पेरिस समझौते में उल्लिखित तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए सीमित समय अवधि की चेतावनी दे रहे हैं।

**शहजाद पूनावाला | डॉ. विजेता रत्तानी**

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समान नहीं होते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ता है। भारत दुनिया के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों में से एक है। *डाउन टू अर्थ* रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में, भारत में 322 दिनों में चरम मौसमी घटनाएं हुईं- जैसे बाढ़, सूखा, हीटवेव, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव और हिमनदों का पिघलना। इनका असर लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य, सफाई

व्यवस्था, आधारभूत ढांचे, जल और खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा देश के विकास पर पड़ा। *जर्मनवॉच संस्था* द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन दशकों में चरम मौसमी घटनाओं के कारण भारत में 80,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है और देश को लगभग 180 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है।

इस मामले में प्राचीन भारतीय दर्शन एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा, एकत्व और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाता है। यह दर्शन पृथ्वी को केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई (मातृभूमि) के रूप में देखता है। 'वसुधैव कुटुंबकम' का विचार संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। *बृहदारण्यक उपनिषद* में सर्वात्मभाव की बात होती है, यानी सभी के साथ अपनी पहचान। *भगवदगीता* सामूहिक पर्यावरण संरक्षण को समुदायों के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानती है। यह पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण ही है, जिसे वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय एजेंडा का मार्गदर्शक बनना चाहिए।

यद्यपि, भारत ऐतिहासिक रूप से जलवायु संकट का जिम्मेदार नहीं रहा है और उसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भी वैश्विक औसत से काफी कम है, फिर भी वह इस मुद्दे पर बेहद सक्रिय है। भारत ने जलवायु, ऊर्जा व अनुकूलन से जुड़े महत्वाकांक्षी तथा सार्थक लक्ष्य तय किए हैं, जो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान और दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीतियों में भी दर्ज हैं। इन दस्तावेजों में 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी दोहराया गया है। यह सोच अनेक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के रूप में सामने आई है।

आज भारत दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में तीसरे पायदान पर। भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 2014 से जून, 2025 तक 41 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है-यह 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 116.25 गीगावॉट तक पहुंच गई है। 2005 से 2020 के बीच, भारत के जीडीपी की एमिशन तीव्रता में 36 फीसदी की कमी आई है। विकास की दृष्टि से, भारत ने 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है और 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दस लाख से भी अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में पिछले 10 वर्षों में 46 फीसदी की वृद्धि हुई है।

हाल के समय में, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, नई तकनीक, कार्बन प्राइसिंग, ऊर्जा संक्रमण, हरित इमारतों के नियम, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ऊर्जा की बचत और भंडारण, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में काफी निवेश किया है। इसका मकसद है आत्मनिर्भरता बढ़ाना और पर्यावरण से जुड़ी नौकरियां पैदा करना। जलवायु वार्ताओं (कॉप) में भारत ने विकसित देशों से मांग की है कि वे गरीब और विकासशील देशों को वित्तीय मदद, तकनीक और क्षमता निर्माण में सहयोग करें। भारत ने यह भी कहा है कि विकसित देशों को विकासशील देशों में एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट अनुकूलन को संभव बनाना चाहिए। इस तरह भारत ग्लोबल साउथ की ओर से एक अहम आवाज बनकर सामने आया है। अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना आदि की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने कॉप 26 में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) शुरू किया। इसके जरिये भारत ने दुनिया से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली अपनाएं, जो भारत की पारंपरिक सोच से मेल खाती है।

भारत ने कई देशों के साथ मिलकर जलवायु संरक्षण के उपायों को आगे बढ़ाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन जैसी पहलों के जरिये भारत ने ऐसे मंचों का नेतृत्व किया है, जो ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं, ठोस अनुभवों और सहयोग के आदान-प्रदान को संभव बनाते हैं, जिससे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। भारत ने जलवायु और ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अन्य वैश्विक मंचों पर भी मजबूती से उठाया है। लिहाजा, जब दुनिया जलवायु संकट की आग में झुलस रही है, जब हर देश समाधान की तलाश में है, तब भारत एक उम्मीद बनकर उभरा है।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

**नॉर्मन विंसेंट पील**

आपका मंत्र 'मैं विजेता हूं' का होना चाहिए। जब भी मन में संदेह या डर पैदा हो, तो अपने भीतर की उस आवाज को जगाइए, जो कहती है कि 'हां, मैं कर सकता हूं।'

### विश्वास ही हर सफलता का मूल है

*अगर आप उन लोगों में से हैं, जो हर वक्त हार की आशंका से घिरे रहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरा ठहरिए और सोचिए, क्योंकि हार की सोच ही आपको धीरे-धीरे पराजय की ओर धकेलती है। जिस ओर आपका मन सोचता है, वही दिशा आपकी जिंदगी ले लेती है। अगर आप बार-बार हार की कल्पना करते हैं, तो जीवन भी आपको वही लौटाएगा। इसलिए, अपने भीतर झांकिए, अपनी सोच को पुनः शिक्षित कीजिए। आपका मंत्र 'मैं विजेता हूं' का होना चाहिए। जब भी मन में संदेह या डर उठे, तो अपने आप से प्रेमपूर्वक बात करें। अपने भीतर की उस आवाज को जगाइए, जो कहती है कि 'हां, मैं कर सकता हूं।' हालांकि, ऐसा आप तभी कर सकते हैं, जब आपको खुद पर और ईश्वर पर भरोसा हो। विश्वास ही हर सफलता की जड़ है। नकारात्मक विचारों की उस पुरानी आदत को छोड़ दीजिए, जो आपको यह भरोसा दिलाती है कि आपसे बड़ा कोई है या कोई परिस्थिति आपको झुका सकती है।*

*एक प्रेरक उदाहरण है गोंजालेस का, जिसने वर्षों पहले टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। उसे उससे पहले शायद ही कोई जानता था। वह बारिश की वजह से टूर्नामेंट से पहले अभ्यास भी नहीं कर पाया। फिर भी, उसने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप जीती। कुछ खेल विशेषज्ञों ने कहा कि उसकी तकनीक में कई खामियां थीं, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मानसिक दृढ़ता और खेल व जीवन के निराशाजनक उतार-चढ़ावों से कभी हार न मानने का उसका जज्बा। यही उस इन्सान की विजयी सोच थी। हर मुश्किल के सामने उसने हारने के बजाय टिके रहने का विकल्प चुना और यही मानसिक तथा आध्यात्मिक गुण उसे चैंपियन बना गया। विश्वास ही वह शक्ति है, जो इन्सान को अंधेरे में भी मजबूती से कदम बढ़ाने का साहस देती है। जब सब आसान लगे, तब तो हर कोई आगे बढ़ सकता है, पर जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब जो आदमी चलता रहता है, जिंदगी में कामयाबी उसी को मिलती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कभी निराशा तथा चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए। गोंजालेस का जीवन इसी दर्शन का जीता-जागता उदाहरण है। उसकी कहानी बताती है कि कमजोरियां रुकावट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को जागृत करने का अवसर होती हैं। बचपन में बीमार, हकलाने वाले और आत्मग्लानि में डूबे गोंजालेस के बारे में एक समय यह माना जाता था कि वह अपनी कमजोर शारीरिक स्थिति के कारण जीवित ही नहीं रह पाएगा। लेकिन वह एक दिन तब बदला, जब उसके भीतर विश्वास की ज्योति जगी। उसने जाना कि जब मन दृढ़ हो और आत्मा को ईश्वर की शक्ति का साथ मिल जाए, तो कोई भी इन्सान असंभव लगने वाले काम को भी शानदार जीत में बदल सकता है।*

#### खुद पर भरोसा करना सीखें

**सूत्र**

*जब इन्सान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। यही वह ताकत है, जो भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है और हर कठिन परिस्थिति में रास्ता दिखाती है। सकारात्मक सोच को अपना साथी बनाइए तथा हर काम को नई उम्मीद के साथ शुरू कीजिए। जितना विश्वास आप खुद पर करेंगे, मंजिल की राह उतनी ही आसान होगी।*

## दूसरा पहलू

एसोसिएशन में नहीं, बल्कि ट्रेडमार्क एक्ट के तहत फिल्म या वेब सीरीज के टाइटल का रजिस्ट्रेशन वैध होता है।

### फिल्मों के टाइटल के पीछे की कहानी

**बॉलीवुड** की कई फिल्में जैसे प्यार का मंदिर, आशिकी, दबंग आदि में एक ट्रेंड नजर आया कि फिल्म टाइटल उस मूवी के किसी एक या अधिक गीत के मुखड़े का हिस्सा होता है। फिल्म के प्रचार-प्रसार के दौरान भी उसी टाइटल का उपयोग किया जाता है, ताकि दर्शक उसे देखने का मन बनाएं। फिल्म के टाइटल को विशिष्ट आर्ट वर्क के रूप में ट्रेडमार्क व कॉपीराइट कानून, दोनों के अंतर्गत पंजीकृत कर सकते हैं। कुछ टाइटल इतने आकर्षक होते हैं कि लेखक, निर्माता-निर्देशक इन्हीं पर आधारित फिल्में, वेब सीरीज, ओटीटी सीरीज बनाने की इच्छा रखते हैं।

**विकास आसावत**

फिल्म के टाइटल को विशिष्ट आर्ट वर्क के रूप में ट्रेडमार्क व कॉपीराइट कानून, दोनों के अंतर्गत पंजीकृत कर सकते हैं।

वर्ष 2002 में 'शोले' के टाइटल संबंधी ट्रेडमार्क विवाद के उच्च न्यायालय तक पहुंचने पर सर्वप्रथम इस मुद्दे ने फिल्म जगत में टाइटल के स्वामित्व पर ध्यान खींचा। बीस वर्ष बाद फैसला वादी यानी फिल्म निर्माता कंपनी के पक्ष में आया व प्रतिवादियों को एक मोटी रकम चुकाने के साथ-साथ 'शोले' नाम, 'शोले.कॉम' डोमेन नाम का उपयोग न करने व डोमेन नामों को वादी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। फिल्म 'शोले' का कोई संदर्भ देने, उसके किसी चित्र या क्लिपिंग व नाम का इस्तेमाल करने से भी रोका गया।

वर्ष 2002 में 'शोले' के टाइटल संबंधी ट्रेडमार्क विवाद के उच्च न्यायालय तक पहुंचने पर पहली बार इस मुद्दे ने फिल्म जगत में टाइटल के स्वामित्व पर सबका ध्यान खींचा।

इसी वजह से निर्माता इसके ट्रेडमार्क पंजीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनील दर्शन द्वारा स्टार इंडिया (अब जियोस्टार इंडिया) के विरुद्ध टाइटल 'लुटेरे' का वेब सीरीज में इस्तेमाल करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। सुनील दर्शन की यह फिल्म वर्ष 1993 में रिलीज हुई थी व इसके टाइटल का पंजीकरण वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में कराया गया था। फैसले के अनुसार, फिल्म के शीर्षक को कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं कर सकते और एसोसिएशन के सदस्यों के बीच आंतरिक अनुबंध के तहत टाइटल रजिस्ट्रेशन गैर-सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। चूंकि, कॉपीराइट एक सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के साथ उसकी स्टोरीलाइन में भी मौजूद होता है, इसलिए जब दो फिल्मों की कहानी भिन्न है, केवल शीर्षक में समानता है, तो कॉपीराइट अधिनियम कार्रवाई योग्य दावे को सुनिश्चित नहीं करती।

अतः फिल्म व ओटीटी जगत में टाइटल व किरदार पर ट्रेडमार्क द्वारा कानूनी अधिकार अर्जित करना नितांत आवश्यक है। केवल गुडविल, एसोसिएशन में टाइटल रजिस्ट्रेशन व स्क्रिप्ट सहित संपूर्ण मूवी का कॉपीराइट पंजीकरण टाइटल पर अधिकार से वंचित कर सकता है। ट्रेडमार्क व कॉपीराइट के उपयुक्त रजिस्ट्रेशन की सही जानकारी व विमर्श ही फिल्म व वेब सीरीज टाइटल के संरक्षण की गारंटी है।

## आंकड़े

### सोने का भंडार

जून 2025 तक अमेरिका सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार रखने वाला देश है। इसके बाद देशों का क्रम निम्नवत है। भारत आठवें पायदान पर आता है।

| | |
|---|---|
| जर्मनी | 3,350 |
| इटली | 2,452 |
| फ्रांस | 2,437 |
| रूस | 2,330 |
| चीन | 2,299 |

आंकड़े देशों में स्वर्ण भंडार के, मीट्रिक टन में। | स्रोत : World Gold Council

**दत्तात्रेय ने परिंदे से कहा, 'हे पक्षी, आज तू मेरा गुरु बना। मैंने तुझसे सीखा कि जिस वस्तु पर अनेक लोग अधिकार जताते हों, उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है।'**

## पक्षी की सीख

**अवधूत** दत्तात्रेय हर क्षण किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहा करते थे। वह पशु-पक्षियों एवं कीट-पतंगों की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखा करते और विवेचना कर उनसे शिक्षा प्राप्त करते। दत्तात्रेय अक्सर कहते थे, 'जिनसे मैं कोई भी शिक्षा लेता हूं, वह मेरे गुरु हैं।'

एक दिन वह वन जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक पक्षी आगे-आगे उड़ा जा रहा है और एक दर्जन परिंदे उसका पीछा कर रहे हैं। पीछा करने वाले पक्षी आगे वाले से अलग नस्ल के हैं। दत्तात्रेय ने ध्यान से देखा कि आगे वाले विहग की चोंच में रोटी का टुकड़ा है और उसे छीनने के लिए ही सभी पंछी उसका पीछा कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ चोंच मारकर उसे घायल कर रहे हैं। पक्षियों के आक्रमण से लहूलुहान हुए उस परिंदे ने अचानक चोंच से रोटी का टुकड़ा गिरा दिया। पीछा कर रहे किसी अन्य विहग ने उस टुकड़े को लपक लिया। अब अन्य खग उसे घेरकर चोंच मारने लगे। पहले वाला पक्षी चोंचों के प्रहार से घायल होकर नीचे उतरकर एक वृक्ष पर बैठ गया।

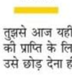

**अंतर्यात्रा**
संकलित

दत्तात्रेय ने हाथ जोड़कर उसे संकेत करते हुए कहा, 'हे पक्षी, आज तू भी मेरा गुरु हुआ। मैंने तुझसे आज यही सीखा है कि संसार में जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए ज्यादा लोग अधिकार जताते हों, उसे छोड़ देना ही उचित है।'

## अमर उजाला

**पुराने पन्नों से** — 4 नवंबर, 1949

### नगर में हिंदी दिवस की धूम

नगर में हिन्दी दिवस की धूम

आगरा नागिरी प्रचारिणी सभा में हिन्दी दिवस नगर के प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी के सभापतित्व में मनाया गया। सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास करके यह माँग की गई कि हिन्दी को फौरन राजभाषा घोषित किया जाय व केन्द्रीय सरकार के सारे कार्य हिन्दी में हों।

—संयुक्त प्रान्तीय तंतुवाय वैश्य सम्मेलन २ व ३ नवंबर को रामलीला

आगरा नागिरी प्रचारिणी सभा में नगर के प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी के सभापतित्व में हिंदी दिवस मनाया गया। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके यह मांग की गई कि हिंदी को फौरन राजभाषा घोषित किया जाए।

## परेशानियों का सबब बनती घटनाएं

**भले ही भारतीय समाज जातिविहीन नहीं हो सकता, किंतु जन्मना श्रेष्ठता-निकृष्टता की भावना से तो बाहर आया ही जा सकता है।**

श्यौराज सिंह बेचैन

**मुद्दा**

विश्व को सर्वप्रथम सभ्यता सिखाने का गौरव अनुभव करने वाले देश में मनुष्य को इतना सभ्य और प्रबुद्ध तो होना ही चाहिए कि दूसरे मनुष्य के सम्मान, गरिमा और अस्तित्व को क्षति पहुंचाना उसे स्वयं ही अप्रिय लगने लगे। संविधान के साये में जहां समता, स्वतंत्रता और बंधुता फलती-फूलती हो, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण रोकने का दायित्व आम नागरिक से लेकर राजकीय एवं सांविधानिक संस्थाओं का प्राथमिक दायित्व हो जाता है। बदकिस्मती से विगत माह ऐसी कई अप्रिय और अशोभनीय घटनाएं हुईं, जो सभ्य नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनीं। ये घटनाएं 'सामाजिक न्याय' की दृष्टि से उपेक्षित-वंचित व कमजोर समुदाय से आने वालों के साथ हुईं। केसी त्यागी ने 'मौतें और सवाल' लेख में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले के हवाले से कहा है कि पंजीकृत 54,574 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में सैंतीस हजार साठ अनूसूचित जाति से हैं। दिल्ली में विगत 15 वर्षों में सौ से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।

प्रकारांतर से लगातार प्रकाशित हो रही खबरें चौंकाती हैं, मसलन-भिंड, मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया, तीन गिरफ्तार। लखनऊ में मंदिर के पास गलती से पेशाब करने के कारण 60 वर्षीय बुजुर्ग को मूत्र चाटने को मजबूर किया गया। मध्य प्रदेश खनन का विरोध करने पर दलित व्यक्ति पर पेशाब किया गया। मथुरा में अनुसूचित जाति के दूल्हे को बग्गी से उतार कर धमकाया, डीजे बंद कराया, दबंगों ने दूल्हे के परिजनों को पीटा। मध्य प्रदेश के भिंड में रुद्रप्रताप सिंह जाटव (35) को मामूली कहा-सुनी पर गैर-दलित पड़ोसियों ने पीट-पीट कर मार दिया। अलीगढ़ में अनुसूचित जाति के युवक की बरात को दबंगों ने रोका। भोपाल-दलितों का आरोप, पुलिस हिरासत में हुआ उत्पीड़न, भोपाल ही में अंतर्जातीय-विवाह कर लेने पर पत्नी के परिवार ने दलित युवक की हत्या कर दी। अंबेडकर नगर में 17 वर्षीय इंटर की दलित छात्रा की टाई से गला घोंट कर हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में मां के सामने अनुसूचित जाति के युवक की हत्या। दलित बुजुर्ग से मंदिर की सीढ़ियां चटवाने का आरोप। इस संदर्भ में, 'दलितों पर बढ़ा अत्याचार' शीर्षक से सपा नेता अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने बुजुर्ग के साथ-साथ रायबरेली दलित युवक की हत्या और लखनऊ में हुए दलित बुजुर्ग के अपमान का मुद्दा उठाया, परंतु ऐसा ही उत्पीड़न तो 2017 में भी हुआ था, जब सपा राज में यादव पुलिस और दबंग ग्रामीण यादव दलित उत्पीड़न कर रहे थे। मायावती की जाति से संबंधित दलितों को तो हर स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। गंगुर्रा (बदायूं) का प्रसंग इस लेखक ने मौके पर दर्ज किया था, जहां थाना प्रभारी अनिल यादव ने जाटवों के घरों में घुसकर महिलाओं को अपशब्द कहे थे। तभी इन पंक्तियों के लेखक ने कहा था 'अब यूपी में भाजपा आएगी', क्योंकि मायावती निष्क्रिय थीं और सपा द्वारा दलित उत्पीड़न कानून की हदें तोड़ रहा था।

सम्मान का सवाल हाल ही में पूर्व प्रधान न्यायाधीश गवई पर फेंके गए जूते के संदर्भ में चर्चा के शीर्ष पर था। 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर, अपनी जाति छिपा कर 'मैं भी दलित हो सकता हूं' कह रहे थे। बेशक उन्हें जज साहब के कथित बयानों, 'बुलडोजर' से देश नहीं चलेगा, कानून से चलेगा और अपने विष्णु भगवान से कहो, वे अपनी खंडित प्रतिमा खुद ही ठीक करा लेंगे, से आपत्ति थी, जिसे उन्होंने 'सनातन का अपमान' कहा और अपने एक्शन को ईश्वर का आदेश बताया, लेकिन उन्होंने सांविधानिक तरीके से आपत्ति, शिकायत और असंतुष्टि जाहिर नहीं की, बल्कि दुनिया को अपना सनातनी चेहरा दिखाया। मामला अनुसूचित जातियों की गरिमा और संविधान निर्माता की प्रतिष्ठा से जुड़ा था।

धर्म-जातियों के संस्कारगत आग्रह अपनी जगह, लेकिन समग्रता में यह मानवीय सभ्यता और संयत व्यवहार का प्रश्न है, जो तय करता है कि नागरिक के तौर पर हम अपनी सांविधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं और अपने लोकतंत्र को राजनीति की हदबंदी से निकाल कर समाज, साहित्य और संस्कृति में कितना विकसित कर पाए हैं? वैश्विक सभ्यताओं में हम किस कोटि की नागरिक चेतना का परिचय दे पाए हैं?

भले ही भारतीय समाज जातिविहीन नहीं हो सकता, किंतु जातियों के बीच का भेदभाव, जन्मना श्रेष्ठता-निकृष्टता से तो बाहर आया ही जा सकता है। बेशक संविधान प्रदत्त समता, स्वतंत्रता और बंधुता इन्हीं मूल्यों की पुष्टि करती है, परंतु सिद्धांत और व्यवहार की दूरी कम नहीं होगी, तो भारत की दुनिया में अनोखी पहचान कैसे कायम है? हिंसा, असहिष्णुता और अनुदारता का मार्ग अपना कर तो विश्वगुरु नहीं बना जा सकता। जरूरी है कि हम 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की भावना को आत्मसात करें, वरना बाहर कितना भी प्रकाश फैलता जाए, भीतर का अंधेरा 'सर्वेभवंतु सुखिनः' के हमारे पथ को आलोकित करने में बाधक ही होगा।

-लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सीनियर प्रोफेसर हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

# परमाणु परीक्षण

पाकिस्तान अगर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में जुटा है, तो यह भारत के लिए चिंतन का गंभीर विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अगर यकीन करें, तो भारत का यह अस्थिर और आतंकवाद समर्थक पड़ोसी देश परमाणु हथियारों के परीक्षण में जुटा है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह बड़ा खुलासा किया है। क्या वाकई यह सच है? अगर पाकिस्तान ने ऐसे परीक्षण किए हैं, तो भारत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षण का आकार-प्रकार क्या है? नियम-कायदा तो यही है कि ऐसा कोई भी परीक्षण बताकर किया जाना चाहिए, पर दुनिया में चुपचाप परीक्षण का इतिहास रहा है। पाकिस्तान का इन दिनों जो तेवर-कलेवर है, उससे भी आशंका होती है कि वह ऐसे परीक्षण कर सकता है। यदि ट्रंप ने अपने स्वभाव के मुताबिक, बस यूं ही पाकिस्तान का नाम ले लिया है, तब भी भारत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भारत का आश्वस्त होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की रणनीति उसी के अनुरूप तैयार की जा सके। भारतीय सुरक्षा तंत्र को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालांकि, ज्यादा आशंका यही है कि ट्रंप ने अपने हल्के-फुल्के अंदाज में ही पाकिस्तान का नाम लिया है। वास्तव में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपनी नीतियां बदल रहा है। परमाणु परीक्षण पर लगभग तीन दशक से रोक लगी हुई थी, इस रोक को हटाने की ओर ट्रंप चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी समय परमाणु परीक्षण को अंजाम दे सकता है। चूंकि ऐसे किसी परीक्षण से दुनिया में चिंता की लहर दौड़ सकती है, इसलिए ट्रंप आहिस्ता-आहिस्ता परीक्षण के मुताबिक माहौल बनाने में जुटे हैं। ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण को रोकने वाला एकमात्र देश नहीं रह सकता। संकेत स्पष्ट है, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सहित अन्य शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। अमेरिका यह नहीं चाहता कि दूसरे देश लगातार शक्तिशाली होते चले जाएं। अतः ट्रंप परमाणु संबंधी नीतियों को बदलने के लिए लालायित हैं, लेकिन क्या इसके लिए पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी था? अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए है, तो क्या ट्रंप ने इस पर प्रत्यक्ष आपत्ति जताई है? आजकल पाकिस्तानी हुक्मरान से तो ट्रंप की खूब छन रही है। ऐसे में, क्या ट्रंप पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण न करने के लिए पाबंद नहीं कर सकते थे? ऐसे अनेक सवाल हैं, जिनके जवाब भारतीय राजनयिकों को जल्दी खोजने पड़ेंगे।

**अगर पाकिस्तान ने वाकई परमाणु परीक्षण किए हैं, तो भारत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस आणविक परीक्षण का आकार-प्रकार क्या है?**

यह दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने विश्व में जटिलताएं बढ़ा दी हैं, ठीक वैसे ही ट्रंप की परमाणु नीति भी साबित होने वाली है। पिछले महीनों में ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी माना है कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद वह और परमाणु परीक्षण के पक्ष में हैं। क्या यह विडंबना के साथ ही, एक तरह से नीतिगत त्रासदी नहीं है? वैसे, अमेरिका की नीतियां अपने लिए कुछ व दूसरों के लिए कुछ और रहती आई हैं, पर ट्रंप ने बगैर-लिहाज खुलेआम जो नीतिगत पहेलियां खड़ी की हैं, उनको सुलझाने व उसके अनुरूप नीतियां बनाने में दुनिया के सजग देशों को वर्षों लग जाएंगे। विशेष रूप से यूरोपीय देशों और भारत को इन पहेलियों पर ज्यादा गौर करना पड़ेगा।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
04 नवम्बर, 1950

### समाधानकारक नहीं

तिब्बत पर चीनी आक्रमण के संबंध में भारत-चीन के बीच हुआ पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया। इस पत्र-व्यवहार को पढ़कर चीनी आक्रमण का औचित्य स्पष्ट नहीं होता, बल्कि चीनी सरकार की यह अहम्मन्यता ही सामने आती है कि अपने कामों के बारे में वह शुभाकांक्षी मित्रों की भी सलाह या आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, शुभाकांक्षी मित्र की सलाह की उसकी प्रतिक्रिया यह है कि उलटे उस मित्र पर ही दोषारोपण किया जाने लगा है। यह रुख चीन की उस सरकार का है, जिसे अस्तित्व में आये अभी केवल एक वर्ष हुआ है और जिसकी सत्ता को अभी विश्व-समर्थन नहीं मिला है तथा विश्व के बहुसंख्यक राष्ट्रों के विरुद्ध होते हुए भी जिसको मान्य कराने के लिए भारत उनसे बुरा बनकर भी प्रयत्नशील है। यह ऐसा रुख है, जिसका सभ्य संसार अभ्यस्त नहीं है, परन्तु साम्यवादी दुनिया की शायद यही चाल है। अतः इससे हमारा समाधान हो या नहीं, इसपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

भारत ने तिब्बत पर चीनी आक्रमण को 'आश्चर्यजनक और खेदजनक' कहा, क्योंकि (1) चीन की नई सरकार की ओर से तिब्बत को मुक्त करने के चीनी निश्चय के बारे में बार-बार यह आश्वासन दिया गया कि वह शान्तिपूर्ण उपायों से ऐसा करने की इच्छा रखती है और (2) पारस्परिक वार्ता द्वारा कोई हल निकालने के लिए तिब्बती प्रतिनिधिमण्डल चीनी सरकार की सहमति से पहले दिल्ली आया और अब पेंकिंग जा रहा था। चीन सरकार को चाहिए था कि मित्र-देश के 'आश्चर्य' व 'खेद' की कद्र करती तथा उसे आश्वस्त करने की चेष्टा करती; किन्तु उसका उत्तर दूसरी ही भाषा बोलता है। 'तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है' और 'तिब्बत का प्रश्न पूर्णतः चीन का घरेलू प्रश्न है' इस आधार को बड़े रुखे रूप में प्रस्तुत करते हुए चीनी सरकार ने बड़ी शान के साथ कहा है, 'चीनी जनता की मुक्तिसेना को तिब्बत में प्रवेश करके तिब्बती जनता को मुक्त करना ही होगा।' यही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि 'चीन ने शान्तिपूर्ण वार्ताओं की इच्छा छोड़ी नहीं है और भारत पर आरोप किया है कि वह चीन विरोधी विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है तथा तिब्बत की समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के शामिल होने के प्रश्न को एक करना चीन के प्रति अपना विरोधी रुख प्रकट करने के सिवा कुछ नहीं है।

# बाहुबलियों में नेता तलाशती पार्टियां

**एक बाहुबली को उस दल ने टिकट दिया है, जो जंगलराज के खिलाफ लड़कर सत्ता में आया है, तो एक अन्य बाहुबली उस पार्टी के प्रचार में जुटा था, जो नया बिहार बनाने के दावे करती है।**

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

बिहार के विधानसभा चुनावों में दिलचस्पी रखने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षक लगातार कामना करते रहे कि इस बार चुनावों में सब कुछ बिहार की दूसरी चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल भले ही हो, पर कम से कम हिंसा न हो। उनकी यह सदिच्छा 30 अक्तूबर की दोपहर धरी की धरी रह गई। इस दिन मोकामा में बिहार की राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। जिन पर हत्या का आरोप लगा, उनमें शामिल अनंत सिंह भी बिहार के कुख्यात बाहुबलियों में से एक है और इस बार जद-यू के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है।

इस विधानसभा सीट पर साल 1990 से सिर्फ एक विधानसभा काल, यानी पांच साल को छोड़कर लगातार अनंत सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा है। बिहार में चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग, हत्याएं या अपहरण पहले आम बात थी, पर कुछ तो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन की सख्ती और कुछ लालू यादव के काल को जंगलराज घोषित कर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार की नीतियों के चलते साल 2005 के बाद इन घटनाओं में कमी आई थी।

मोकामा की इस राजनीतिक हत्या के बाद स्वाभाविक रूप से यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या बिहार के चुनावों में हिंसा की वापसी हो रही है? एक घटना से किसी सरलीकृत निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, पर एक चिंताजनक प्रवृत्ति तो रेखांकित की ही जा सकती है कि सफलता हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक दल को अपराधियों की मदद लेने में कोई गुरेज नहीं है। हत्यारोपी बाहुबली को एक ऐसे दल ने टिकट दिया है, जो जंगलराज के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आया था और मृतक बाहुबली उस दल (जन सुराज पार्टी) का प्रचार कर रहा था, जो नया बिहार बनाने का सपना दिखा रहा है।

यह भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि दो बाहुबलियों के बीच हुई हिंसा को दो जातियों के मध्य संघर्ष में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसे प्रदेश की दो महत्वाकांक्षी जातियों के मध्य सत्ता में बड़ी भागीदारी हासिल करने की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा संभवतः इसीलिए संभव हो सका है कि बिहार की जनता के एक बड़े हिस्से में अपराधियों के लिए मन में खास तरह का आदर मिश्रित आकर्षण दिखता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से सचेत बिहारी समाज अपराधियों के बीच अपने नायक तलाशने की कोशिश करे?

यह एक गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकता है कि क्या सिर्फ शिक्षा की बदहाली, रोजगार के अवसरों में कमी या बदहाल आधारभूत संरचनाएं ही बिहारी समाज में बाहुबलियों के प्रति दुर्निवार आकर्षण का कारण हैं या और भी बहुत कुछ है, जो इसकी अंतश्चेतना को इस तरह से छूता है कि वह समाजद्रोहियों को ही अपना नायक मानने लगता है। ये किसी ऐसे सिंघम की तरह दिखते हैं, जो अपनी जातियों के लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जातियां बिहार के चुनावों में कितनी गहरी पैठी हैं, इसका अंदाज डॉ राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा में उल्लिखित एक तथ्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने दुख के साथ यह स्वीकारोक्ति की थी कि सन् 1937 में हुए आम चुनाव में टिकट बांटते समय कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन क्षेत्रों की जातियों को ध्यान में रखा था, जबकि उन चुनावों में मतदाता सूची में नाम होने का मुख्य आधार शिक्षा और संपत्ति था।

देश के कुछ राज्यों में हिंसा चुनावों का अविभाज्य हिस्सा रही है। खास तौर से बिहार और बंगाल इस मामले में खासे बदनाम रहे हैं। एक दौर में इन्हीं के चलते भाषा को 'बूथ लुटेरा' जैसा शब्द मिला था। मुझे याद है कि जिन दिनों मतपेटियों में वोट डाले जाते थे, राज्यों में पुलिस बल कम होते थे और चुनाव आयोग काफी हद तक नख-दंत विहीन सिंह की तरह होता था। यह एक सामान्य दृश्य हो सकता था कि मतदान केंद्र के पास किसी अमराई या खेत में बैठकर कुछ दबंग ठप्पा लगा रहे हों। यह भी संभव था कि शुरू के कुछ घंटों के बाद ही घोषित कर दिया जाता कि मतदान खत्म हो गया है और शेष मतदाता घर जा सकते हैं।

सन् 1967 के चुनावों से शेषन युग (1990-96) की शुरुआत तक चुनावी अराजकता बढ़ती ही गई। मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन की सख्ती के चलते, जो कई मामलों में ज्यादती में तब्दील हो जाती थी, भारतीय चुनावों में कुछ हद तक शुचिता कायम हो सकी। बाद के तमाम चुनाव आयोग सिर्फ शेषन की राह पर, गिरते पड़ते ही सही, चलते रहे और चुनावों की प्रतिष्ठा कुछ हद तक बची रह सकी।

इन दिनों चुनावों में दिख सकने वाली शुचिता के बावजूद राजनीतिक दलों के मन में यह इच्छा कहीं न कहीं हमेशा बनी रही कि किसी भी तरह से सफलता हासिल की जाए, भले ही इसके लिए हिंसा का सहारा क्यों न लेना पड़े। बिहार और पश्चिम बंगाल दुर्भाग्य से ऐसी ही दो प्रयोगशालाएं रही हैं, जहां विभिन्न दल बाहुबली समर्थकों और उम्मीदवारों के जरिये चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते दिखते हैं। बंगाल में तो पिछले पचास वर्षों में हिंसा के बिना किसी चुनाव के हो सकने की कल्पना भी मुश्किल हो गई है। बूथ कैप्चरिंग से बढ़कर वहां स्थितियां गांव कैप्चरिंग तक पहुंच गई हैं। वहां के मतदाताओं की यह बेचारगी मीडिया में उनकी प्रतिक्रियाओं में साफ झलकती है कि चुनाव आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण तो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के दौरान रहता है, बाद में तो उन्हें अपनी सरकारी मशीनरी की दया पर ही रहना है।

दुलारचंद यादव की हत्या को किसी अपवाद की तरह नहीं लेना चाहिए। यह हमारी सामाजिक सरंचना में किसी छिपे हुए फोड़े जैसी है, जो कभी भी फूट पड़ने को बेकरार रहता है। जरा सी उत्तेजना इसे फूटने का कारण प्रदान कर सकती है। इसका इलाज एक निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव आयोग तो है ही, इसके साथ मूल्यों के स्तर पर भी समाज में बड़ी उथल-पुथल की जरूरत है। बिहार के तमाम पिछड़ेपन का कारण शिक्षा या चिकित्सा जैसी आधारभूत संरचनाओं की कमी के साथ ये मूल्य भी हैं और जब तक ये आम मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते रहेंगे, तब तक राजनीतिक दलों की भी मजबूरी होगी कि वे चुनावी प्रक्रिया में बाहुबलियों को महत्व दें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# महिला क्रिकेटरों को भी अब मिलने लगेगा बड़ा मंच

यहां स्कैन करें

रीमा मल्होत्रा | पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

विश्व कप में टीम इंडिया की खिताबी जीत देश में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल सकती है। 1983 में जब हमारे पुरुष खिलाड़ी पहली बार विश्व विजेता बने थे, तब जिस तरह का जोश व जुनून गांव-गांव में देखा गया था, ठीक उसी तरह की दीवानगी अब लड़कियों में महसूस की जा सकेगी। दरअसल, ऐसी जीत मिलने के बाद चीजें सकारात्मक दिशा में बदलती हैं। यह भरोसा पैदा होता है कि क्रिकेट में भी करियर है, आर्थिक स्थिरता है और सबसे अधिक आत्मनिर्भरता है, जो हरेक माता-पिता या लड़की का सपना होता है। यह जीत संदेश दे रही है कि यदि प्रतिभा है, तो उसे दिखाने का स्टेज भी अब है।

इन सबसे हालात कितने बदल सकते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मेरी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2003 में हुई थी और 2005 में जब हमारी टीम पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल खामोशी पसरी थी। उस समय हम अपनी पहचान ढूंढ़ रहे थे। वह एक ऐसा दौर था, जब पैशन तो था, लेकिन पैसा नहीं। मीडिया कवरेज तक नहीं था। हमें यह तक नहीं पता था कि टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलने की अहमियत क्या है? मगर अब देखिए, रविवार की रात डीवाई पाटिल स्टेडियम में 39 हजार से अधिक दर्शक मौजूद थे। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट दिग्गजों की भी मौजूदगी थी। यह बताता है कि जैसे-जैसे इसकी अहमियत लोगों तक पहुंचती गई, मीडिया कवरेज भी बढ़ता गया और लड़कियों की सुविधाएं भी बेहतर होती गईं, यानी मुश्किल वक्त था, वह अब बीत चुका है और नई पीढ़ी के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है।

**विश्व कप में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो जज्बा हमारी खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया है, उसकी अनुगूंज सुदूर इलाकों में सुनी जाएगी।**

विश्व कप की यह जीत कई संदेश दे रही है। 2017 के विश्व कप में जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, तब जीत इसलिए नहीं मिल सकी, क्योंकि हमें खुद पर कम विश्वास था। मगर इस बार 'ग्रुप स्टेज' में लगातार तीन हार के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने हौसला नहीं खोया। ऐसा इसलिए भी हो सका, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जरूरी बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए हैं। पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही अब महिला खिलाड़ियों की भी मैच फीस कर दी गई है। यही नहीं, खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा मिलने लगी है। अब उन पर अपने भविष्य को लेकर दबाव नहीं होता।

इस वक्त टीम इंडिया को कई बातें खास बनाती हैं। मसलन, खिलाड़ी एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। टीम में कोई एक मैच विनर नहीं है। जब मैं खेला करती थी, तब हमें लगता था कि मिताली राज रन बनाएगी, तभी हम जीत सकेंगे। मगर अभी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, प्रतिका रावल, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा जैसे कई नाम हैं, जो जिताने की क्षमता रखती हैं। टीम के पास एक ऐसा कोच (अमोल मजूमदार) है, जो बेशक टीम इंडिया के लिए कभी न खेला हो, लेकिन वह भारतीय टीम की जर्सी की कीमत जानता है। और, बीसीसीआई जैसे संगठन खिलाड़ियों की सुरक्षा में तत्पर हैं।

कुछ लोग अभी महिला और पुरुष क्रिकेट की तुलना में रमे हैं, खासकर स्पॉन्सरशिप पर वह चर्चा करना चाहते हैं। शायद वह यह जानना चाहते हैं कि बाजार किस तरह से महिला क्रिकेट का भविष्य बना रहा है। मेरा मानना है कि जो दिखता है, वह बिकता है। जब मैच का प्रसारण टीवी पर हो रहा हो, करोड़ों लोग उसे देख रहे हों और आईसीसी की पुरस्कार राशि पुरुष टूर्नामेंट से अधिक हो, तो समझा जा सकता है कि महिला क्रिकेट का अब कितना बड़ा बाजार बन चुका है। बीसीसीआई की 'समान वेतन' जैसी नीतियों ने प्रतिभाशील महिला खिलाड़ियों की फेहरिस्त लंबी बना दी है। डब्ल्यूपीएल के कारण छोटे-छोटे शहरों से बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे हैं। राज्यवार लीग टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिससे राज्यों से अच्छी टीमें आने लगी हैं। क्लब मैच ज्यादा होने लगे हैं। इन सबसे उन परिवारों के सपने को भी पंख मिले हैं, जो जरूरी संसाधनों के अभाव में अपनी बेटियों को मैदान तक नहीं ला पाते थे। लिहाजा, उम्मीद यही है कि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो जज्बा हमारी खिलाड़ियों में मैदान में दिखाया है, उसकी अनुगूंज अब सुदूर इलाकों में सुनी जाएगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# सरलता क्यों जरूरी

धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, जो चोंगा या लंगोट पहनता है, दिन में एक बार भोजन करता है, जिसने विधि-निषेध के अनगिनत व्रत ले रखे हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है, जो अपने अंतर में सरल है; जो कुछ बनने की फिराक में नहीं है। ऐसे मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, उसे किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है। अतः ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप उसको दें, उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है।

परंतु यथार्थ के पीछे दौड़ने वाला मन सरल नहीं है। वह मन, जो ढूंढ़ रहा है, पता लगा रहा है, टटोल रहा है, विक्षुब्ध है, वह सरल नहीं है। जो मन अंदर या बाहर से किसी भी दबाव के सांचे में ढलने का प्रयत्न कर रहा है, वह संवेदनशील नहीं हो सकता। जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, अर्थात अपने साथ घटित होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के प्रति सावधान होता है; जब मन कुछ बन नहीं रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। केवल तभी सुख-शांति संभव है, क्योंकि यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह यथार्थ का परिणाम है।

जब मन, हृदय सरल अतएव संवेदनशील हो जाते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की जा सकती हैं। वे कितनी भी जटिल क्यों न हों, उन्हें हम एक नई दृष्टि से, अलग ढंग से देख पाएंगे। वर्तमान समय में इसी की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस बाहरी विक्षोभ, अशांति, विरोधाभास का नए ढंग से, सर्जनात्मक तरीके से, सरलता से सामना करने की क्षमता रखते हों, न कि वामपंथी या दक्षिणपंथी सिद्धांतों व नुस्खों से बंधे हों। यदि आप सरल नहीं हैं, तो आप इसका सामना नवीन रूप से नहीं कर पाते।

कोई भी समस्या हो, उसका हल इसी दृष्टिकोण से हो सकता है। लेकिन यदि हम विचार के किसी ढर्रे में सोचते रहते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कोई और, तो हम उस समस्या को नए ढंग से नहीं ले सकते। अतः सरल होने के लिए हमें इन सबसे मुक्त होना होगा। इसलिए अपनी विचार-प्रकिया के प्रति सचेत होना, उसे समझने की क्षमता रखना और स्वयं को समग्रता में जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। उसी से

**सरल मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं है। ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप उसको दें, उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है।**

सरलता आती है, विनयशीलता आती है, जो न तो कोई सद्गुण है, और न कोई अभ्यास।

जब सच्ची विनयशीलता होती है- प्रयत्न से प्राप्त की हुई नहीं, तभी जीवन की मुंह बाए खड़ी समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तब वह सिर्फ अपनी कठिनाइयों व अपने महत्व के नजरिये से नहीं देखता, वह समस्या को सीधे-सीधे देख पाता है और तभी यह उसका समाधान कर सकता है।

**जे कृष्णमूर्ति**

**राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री**

**भारत ने सदैव रक्षा सहयोग में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखने पर बल दिया है। चेतावनी प्रणाली और मानवीय सहायता के क्षेत्र में हमारा अनुभव आसियान देशों को जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रति तैयारी और क्षमता सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।**

# केरल ने गरीबी दूर करने का दिखाया रास्ता

केरल की पावन धरती, जहां नारियल के हरे-भरे बागान समुद्र की लहरों का आलिंगन करते हैं और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून की बूंदों से सराबोर हो जाती हैं, एक ऐसी क्रांति की साक्षी बनी है, जो समूचे भारत को प्रेरणा दे रही है। 1 नवंबर को, केरल पिरवी दिवस के पवित्र अवसर पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐतिहासिक घोषणा की- केरल अब अत्यधिक गरीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। यह भारत का पहला राज्य है, जिसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आशाओं का उदय और समावेशी समाज के निर्माण की विजय है। कल्पना करें, उन घरों की, जहां कभी भूख और अभाव की छाया मंडराती थी, वहां आज आत्मसम्मान और समृद्धि की किरणें झिलमिला रही हैं। यह कहानी बताती है कि यदि नीयत साफ और इच्छाशक्ति अटल हो, तो गरीबी को जड़ से उखाड़ना असंभव नहीं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव 2021 में रखी गई, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी) को हरी झंडी दिखाई। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट ने केरल को देश में सबसे कम 0.55 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी दर के साथ शीर्ष पर रखा, लेकिन यह आंकड़ा सरकार के लिए रुकने का बहाना नहीं बना। इसके बजाय, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1,032 स्थानीय निकायों के सहयोग से 64,006 परिवारों की पहचान की गई, जो अत्यधिक गरीबी की जकड़ में थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एकसमान नीति थोपने के बजाय हर परिवार के लिए अलग माइक्रो-प्लान तैयार किए। स्थानीय निकायों, कुदुंबश्री जैसे सशक्त महिला समूहों और सामाजिक संगठनों को इस मिशन में सहयोगी बनाया गया। नतीजतन, केरल अति-गरीबी से मुक्त हो गया है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और जन-भागीदारी से परिपूर्ण थी, बल्कि मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखकर संचालित हुई।

केरल की इस उपलब्धि ने नई आशा जगाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य केरल की माइक्रो-प्लानिंग से सबक ले सकते हैं। केंद्र की योजनाएं- जैसे पीएम आवास, आयुष्मान भारत को ईपीईपी जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है। केरल की यह घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ति और दशकों की दूरदर्शी नीतियों-भूमि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रमाण है। यही कारण है कि वह गर्व से कह रहा है कि गरीबी-उन्मूलन संभव है।

**आरके जैन 'अरिजीत'**, शिक्षाविद

## अनुलोम-विलोम
### अति गरीबी मुक्त केरल

# यह आंकड़ों में हेराफेरी का नतीजा तो नहीं

केरल ने भले ही 'अति गरीबी' से मुक्त होने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह कहीं-न-कहीं आंकड़ों की हेराफेरी भी जान पड़ती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विगत 25 अक्तूबर को ही जब यहां के एससी-एसटी कल्याण मंत्री ने वायनाड को 'अति-गरीबी' से मुक्त होने की घोषणा की थी, तभी आदिवासी कार्यकर्ताओं ने इस सरकारी दावे की कलई खोल दी थी और बताया था कि सरकारी आंकड़ों व सच्चाई में काफी ज्यादा अंतर है। गौरतलब है कि वायनाड केरल के उन इलाकों में शुमार है, जहां आदिवासियों की एक बड़ी संख्या रहती है। यहां के आदिवासियों का कहना था कि वे अब भी भूख और अभाव में दिन गुजारने को मजबूर हैं।

यह स्थिति सिर्फ वायनाड की नहीं है, यहां के अधिकांश आदिवासी इलाकों में भूख, बेरोजगारी और भूमिहीनता आपको आसानी से दिख जाएगी। चूंकि आदिवासियों का संघर्ष बदस्तूर चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री का यह दावा कि उनका राज्य अति-गरीबी से मुक्त हो गया है, इन आदिवासियों के सम्मान पर चोट जैसा है। यह दावा इन लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? वह चाहते, तो कुछ वक्त लेकर यहां के हालात पूरी तरह सुधार सकते थे और फिर अपनी उपलब्धि का एलान करते। यह कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे समावेशी समाज की कल्पना कहीं अधिक साकार होती। आदिवासियों के लिए लड़ने वाले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि केरल के 90 फीसदी आदिवासी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। कई लोग प्लास्टिक की ढकी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जहां न बिजली है, न शौचालय और न ही पीने का साफ पानी। 'द मूकनायक' में छपी एक खबर के मुताबिक, आदिवासी समाज के बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और पिता के काम में हाथ बंटाना उनकी मजबूरी बनी हुई है।

हालांकि, ऐसी तस्वीर सिर्फ केरल में नहीं है। यह स्थिति कमोबेश पूरे देश में दिखती है। बेशक, अभी केरल के दावे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह सूबा मानव विकास के तमाम पैमानों पर सभी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। इसलिए, यह मुमकिन है कि आज नहीं तो कल, यह जरूर इस उपलब्धि को हासिल कर लेगा। तब तक, इसे न सिर्फ पूर्ववत अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाना होगा, बल्कि लोगों के जीवन-स्तर में बेहतरी के कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। केरल के आदिवासियों के लिए भले ही गरीबी अभी की हकीकत हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही इसका उन्मूलन हो जाएगा।

**हिमांशु कुमार**, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय जागरण

(10) मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 : कार्तिक शुक्ल - 14 वि. 2082


सौंदर्य दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं

# लड़कियों ने किया कमाल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीत कर केवल इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के साथ देश की लाखों लड़कियों के लिए खेलों और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खोलने का भी काम किया। इस जीत ने फिर यह सिद्ध किया कि लड़कियां लड़कों की ही तरह हर क्षेत्र में चुनौतियों से पार पा सकती हैं और अपने हौसले से देश-दुनिया को चमत्कृत कर सकती हैं। यह जीत लड़कियों के प्रति हमारे पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सिद्ध होनी चाहिए। यह बदलाव उन्हें आगे बढ़ने और खुद को साबित करने के मौके तो देगा ही, भारतीय समाज में खेलों की महत्ता भी बढ़ाएगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज के युग में खेल के मैदान में अर्जित की जाने वाली सफलताएं देश विशेष की प्रगति का सूचक हैं। महिला विश्व कप की जीत इसलिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पहले किसी अंतरराष्ट्रीय खेल में भारतीय लड़कियों की टीम ने कोई खिताब नहीं जीता था। यह जीत इसलिए भी विशेष है, क्योंकि महिला विश्व कप क्रिकेट में आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का दबदबा था। इसके पहले के सभी महिला विश्व कप क्रिकेट आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के नाम रहे। एक तरह से भारतीय टीम ने अपनी जीत से विकासशील देशों की महिला क्रिकेट टीमों को भी प्रेरणा प्रदान करने का काम किया। महिला वनडे विश्व कप जीत की प्रतीक्षा किस बेसब्री से की जा रही थी, इसका पता फाइनल मुकाबले को लेकर बने माहौल से भी चलता है और स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भीड़ से भी। यह माहौल और भीड़ इस कारण थी कि खेल प्रेमियों को कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी उत्साही टोली पर भरोसा था। इस भरोसे का आधार उनके खेल में आए सुधार के साथ यह भी था कि भारतीय महिला टीम दो बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। यह स्वाभाविक है कि इस जीत को 1983 के वनडे विश्प कप में कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम की ओर से हासिल की गई खिताबी जीत के समकक्ष बताया जा रहा है। उस जीत ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया था। महिला क्रिकेट के साथ ऐसा होना और आसान है, क्योंकि तब के मुकाबले आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम है। वास्तव में क्रिकेट बोर्ड की इस आर्थिक सक्षमता ने ही महिला क्रिकेटरों के विश्व विजयी अभियान को सुगम बनाया। बीसीसीआइ ने 2006 में महिला क्रिकेट की कमान अपने हाथ में ली थी। यदि उसने दो दशक के अंदर ही महिला क्रिकेटरों को शिखर पर पहुंचा दिया तो इसका कारण है उनके प्रोत्साहन के लिए उनकी पुरस्कार राशि पुरुषों के समान करना, उन्हें उनके जैसे संसाधन उपलब्ध कराना और महिला प्रीमियर लीग शुरू करना।

# राज्यहित सर्वोपरि

बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान गुरुवार को होगा। प्रचार का शोर चरम पर है। दोनों प्रमुख गठबंधनों की राज्य के विकास की घोषणाएं और वादे मतदाताओं के समक्ष हैं। इन्हीं वादों के आधार पर मतदाताओं को निर्णय करना है। वैसे देखा जाए तो बिहार की चुनावी राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। विकास से शुरू हुए मुद्दे अंत में जातीय और कुनबाई समीकरण का रुख कर लेते हैं। यह हर बार होता है। इस बार भी विकास के बोल के पीछे यही स्थिति बनती दिख रही है। परस्पर विरोधी एक-दूसरे पर राज्य के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। मतदाता भी कहीं खुलकर सामने आ रहे तो कहीं उनकी चुप्पी राजनीतिक दलों को परेशान कर रही। दलों के अपने-अपने दावे हैं। इन दावों के बीच मतदाता को राज्य के हित को सर्वोपरि रखना है। राज्य का विकास होगा तो आम आदमी का जीवन स्तर सुधरेगा। अतः जरूरी है कि मतदाता यह आकलन करें कि किस पक्ष में विकास का दम खम है। नेक नीयत है। साथ ही उनका ट्रैक रिकार्ड कैसा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने आकलन के अनुसार सही प्रत्याशी का चयन करें। जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर भविष्य को संवारने वाले को मौका देना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में मतदान का प्रतिशत उत्साहजनक नहीं रहा है। इस बार बिहार के मतदाता उत्साह दिखाएं। मतदान जरूर करें।

> मतदाता जाति व संप्रदाय से ऊपर उठकर मजबूत लोकतंत्र के लिए राज्यहित को सर्वोपरि रखकर मतदान करें

**कह के रहेंगे** — माधव जोशी

**जागरण जनमत** — कल का परिणाम

क्या जनसांख्यिकीय असंतुलन दूर करने के लिए जनसंख्या नीति आवश्यक हो गई है?

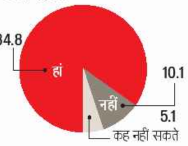


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की जीत लड़कियों को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी?

# फिर संघ के पीछे पड़ी कांग्रेस

हृदयनारायण दीक्षित

**सेक्युलर दल हिंदुत्व और संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, पर उनके पास न तो अल्पसंख्यक की परिभाषा है और न ही सांप्रदायिकता की**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस फिर आमने-सामने हैं। ताजा विवाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि निजी संगठन, व्यक्तियों के समूह और संघ के लिए सरकारी परिसर के उपयोग हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने सनातन परंपरा पर हमला बोलते हुए यह भी कहा था, 'अपनी संगति सही रखें। सनातनियों और संघियों से दूर रहें।' उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने पर वे संघ को प्रतिबंधित कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी संघ पर प्रतिबंध की जरूरत जताई है। उनके बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने भी संघ पर हमला बोला। नियम अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन से संबंध नहीं रख सकता और उसकी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट (1964) के अधीन कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध था। बाद में इसे संशोधित किया गया। अब इस सूची में संघ का नाम नहीं है। कांग्रेस द्वारा संघ की गतिविधियों को बाधित करने के प्रयास पहले भी हुए हैं। ऐसा प्रयास भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14) के अधीन विचार अभिव्यक्ति की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भारतीय संस्कृति आधारित राष्ट्रवादी समाज बनाना उसकी प्राथमिकता है। हिंदुत्व संघ का अधिष्ठान है। संघ ने इस देश की राजनीति, संस्कृति में आधारभूत सकारात्मक हस्तक्षेप किया है। 1925 में जन्मा संघ सौ बरस का हो गया है। उससे ईर्ष्या स्वाभाविक है। 1885 में जन्मी कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। संघ विरोधी राजनीतिक विचारधारा सेक्युलरवाद के नाम पर अल्पसंख्यकवाद चलाती रहती है। सेक्युलरवाद ने विचारधाराविहीन समाज बनाने का काम किया है, पर सेक्युलरिज्म तो आयातित और एक विजातीय विचार है। संघ का मूल आधार हिंदू राष्ट्रवाद है। सेक्युलर दल हिंदुत्व और संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, पर उनके पास न तो अल्पसंख्यक की परिभाषा है और न ही सांप्रदायिकता की। अल्पसंख्यकवाद ऐसी राजनीति का भयानक प्रेत है। देश में लगभग 14.2 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इसके बावजूद सेक्युलर राजनीति उन्हें अल्पसंख्यक बताती है। अल्पसंख्यक की भी कोई परिभाषा नहीं है। राजनीति का मजहबीकरण देश के लिए घातक है।

अवधेश राजपूत

अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के समय कहा था कि पहले सांप्रदायिकता की परिभाषा कीजिए। उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया।

सेक्युलरवाद की दृष्टि में संघ सांप्रदायिक है और इस्लामी एवं ईसाई विश्वास सेक्युलर हैं। यह दोहरापन है। कांग्रेस को संघ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे इंडियन मुस्लीम लीग से कोई समस्या नहीं। संघ से खार खाए कथित सेक्युलर नेता अक्सर कोप में आ जाते हैं और उसके खात्मे का एलान करते रहते हैं। कुछ समय पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने संघ के पथ संचलन कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। इस रोक को लेकर तर्क दिए गए कि पथ संचलन के कार्यक्रम के रास्ते में मस्जिद और चर्च पड़ते हैं। इसलिए अनुमति देना संभव नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि संघ को अनुमति देने से मना करने का फैसला संविधान के विरुद्ध है और लोकतंत्र के लिए असंगत भी। सरकार का निर्णय मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। संघ ने गांधी जयंती और स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम आयोजन की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनुमति नहीं दी। संघ ने तब न्यायालय की शरण ली। संघ के कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश बंगाल में भी होती रही है।

संघ पर पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी, 1948 को लगाया। आरोप लगाया गया कि संघ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है। कहीं कोई साक्ष्य नहीं थे, फिर भी यह प्रतिबंध एक वर्ष तक रहा और 11 जुलाई, 1949 को हटा दिया गया। संघ आगे बढ़ता रहा। वह सेक्युलरपंथियों की आंख की किरकिरी रहा। आपातकाल (1975-1977) में हिंसक गतिविधियों के आरोप के साथ संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। आपातकाल में सभी दलों के नेता जेलों में थे। तकलीफ सभी दलों को थी, पर अकेले संघ ने ही विरोध स्वरूप भूमिगत आंदोलन चलाया। सरकार ने संघ को लोकतंत्र विरोधी और विघटनकारी कह प्रतिबंधित कर दिया। 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई तो प्रतिबंध हटाया गया। अयोध्या आंदोलन से तमतमाए केंद्र ने 6 दिसंबर, 1992 को संघ पर प्रतिबंध लगाया। आरोप सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पहुंचाने और हिंसा फैलाने का लगाया गया। संघ की भूमिका सिद्ध नहीं हुई। 1993 में प्रतिबंध हटाया गया। संघ ने विचार निष्ठा और विशेष संगठन शैली के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन की हैसियत पाई है। यह तथ्य छद्म सेक्युलरवादियों को हजम नहीं होता।

हिंदुत्व सर्व समावेशी विचार है। सुदीर्घ काल से चली आ रही संस्कृति और उस पर आधारित जीवन पद्धति का नाम है हिंदुत्व। संघ पर पाबंदी लगाने को आतुर सेक्युलरपंथी हिंदुत्व की बढ़त से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी संगठन की गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोका। संघ बनाम केके धवन मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1970 में फैसला दिया था कि आरएसएस की गतिविधियां राजनीतिक नहीं हैं। केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि कर्मचारी संघ से जुड़ सकता है। यह सब जानते हुए भी सेक्युलरपंथी संघ से निपटने की बातें करते रहते हैं। कर्मचारी, अधिकारी भी नागरिक हैं। नागरिक होने के कारण उन्हें किसी संगठन के आयोजन में शामिल होने, उत्सव मनाने और सांस्कृतिक जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। संघ के समर्थकों को इससे वंचित करना राजनीतिक असहिष्णुता ही है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं)

response@jagran.com

# प्रदर्शन का जरिया बनी राजनीति

ब्रजेश कुमार तिवारी

**बड़े काफिले, भव्य मंच, चौबीसों घंटे ब्रांडिंग और डिजिटल विज्ञापनबाजी अब राजनीति का केंद्रीय आधार बन चुके हैं**

महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण आदि ने भारतीय राजनीति में सरल जीवन, सादगी, संयम और उच्च विचार की भावना को बढ़ावा दिया, लेकिन बीते दो-तीन दशकों में भारतीय लोकतंत्र का मूल उद्देश्य प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और लोकसेवा की जगह बाहरी आडंबर, चमक-दमक और महंगे प्रचार तंत्र की ओर झुका हुआ दिखता है। पहले नेता साधारण कारों से यात्रा करते थे, आज उनके काफिले में 40-50 महंगी गाड़ियां होना सामान्य है। नेताओं के साथ दौड़ते वाहनों की कतारें, हूटर, कमांडो स्टाइल सुरक्षा और समर्थकों के बीच शक्ति-प्रदर्शन का माहौल अपने आप में नई तरह की राजनीति का संदेश देता है। राजनीति अब विचार, नीति और काम की जगह दिखावे की भाषा बोल रही है। यह दृश्य अब आम हो गया है, पर क्या यह लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है या एक नई राजनीति की पहचान है, जहां सत्ता प्रदर्शन का माध्यम बन गई है?

इन दिनों बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार के नाम पर पैसे और प्रभाव का प्रदर्शन हो रहा है। इसे बाहुबली छवि वाले प्रत्याशी खास तौर पर कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए खड़े हुए कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 (32 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 354 उम्मीदवारों (27 प्रतिशत) ने बताया है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 241 विजेता सदस्यों में से 163 (68 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी। यह आंकड़ा 2015 में 58 प्रतिशत था। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के अनुसार लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 सदस्य ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 170 (31 प्रतिशत) के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विधानसभाओं का परिदृश्य भी अलग नहीं है। 28 राज्यों एवं तीन केंद्रशासित प्रदेशों के 4092 विधायकों में से 1861 (45 प्रतिशत) ने अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। राजनीति का अपराधीकरण चुनाव दर चुनाव संस्थागत होता जा रहा है। वर्तमान लोकसभा में 93 प्रतिशत सदस्य करोड़पति हैं। 2009 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत, 2014 में 82 प्रतिशत और 2019 में 88 प्रतिशत था।

गाड़ियों से पटा पटना का गांधी मैदान ● प्रेट्र

2024 में पुनः चुनाव लड़ रहे सांसदों की औसत परिसंपत्तियां पांच वर्षों में 43 प्रतिशत बढ़ीं। यह आंकड़ा बताता है कि सत्ता तक पहुंच आर्थिक पूंजी को तेजी प्रदान करती है। कारों के काफिले की लंबाई और 'शो-आफ' का बजट यहीं से आता है। यह बदलाव नई राजनीति की पहचान है, जहां नेता राजा जैसे दिखते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में भीड़ और जुलूस का परंपरागत स्थान रहा है, परंतु आज यह केवल समर्थन नहीं दर्शाता, बल्कि प्रभुत्व का संकेत देता है। गाड़ियों का लंबा काफिला यह 'आश्वस्ति' देता है कि नेता 'ताकतवर' है और 'अपने लोगों' की 'रक्षा' कर सकता है। यही मनोविज्ञान चुनाव-पूर्व डर और समर्पण पैदा करता है। इंटरनेट मीडिया के ड्रोन शाट्स और रील्स ने इसे और बढ़ाया है। काफिला जितना बड़ा और सिनेमाई दिखे, नेता को उतना ज्यादा बड़ा माना जाता है। बड़े काफिले, भव्य मंच, चौबीसों घंटे ब्रांडिंग, एआइ संचालित वीडियो और डिजिटल विज्ञापनबाजी अब राजनीति का केंद्रीय आधार बन चुके हैं। यह टिकट वितरण, उम्मीदवारी, नीति-निर्माण और मतदाता को भी प्रभावित करते है। इसी खिड़की से अपराध और धनशक्ति का गठजोड़ लोकतंत्र के भीतर न्यू नार्मल बनता दिख रहा है।

सेंटर फार मीडिया स्टडीज ने 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल अनुमानित खर्च एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक आंका। तब 9,000 करोड़ के आसपास की नकदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातुएं और 'फ्रीबीज' की जब्तियां हुई थीं। यह आंकड़ा प्रचार-युद्ध के शीर्ष-स्तर को परिभाषित करता है और यह भी इंगित करता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया भारत में विश्व की सबसे महंगी लोकतांत्रिक कवायदों में से एक बन चुकी है। सही मायने में यह चुनावी वित्त और आपराधिक नेटवर्क के गठजोड़ की गवाही है। जब चुनावी दान नीति-निर्माण को प्रभावित करे तो जनहित का स्थान 'रिटर्न-आन-इन्वेस्टमेंट' ले ही लेगा। नियमों को सख्ती से लागू करके इस संरचना को बदलना होगा। हमें राजनीति में गांधी, शास्त्री और पटेल जैसे आदर्शों की पुनर्स्थापना करनी होगी। दलों को टिकट बांटने में योग्यता, चरित्र और सेवा को तरजीह देनी चाहिए, न कि चमक-धमक को। जब अपराधी-नेटवर्क और धनशक्ति टिकट-वितरण का आधार बनेंगे तो ईमानदार कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर जांच-पड़ताल और तथ्यपरक पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा। यदि लोकतंत्र के आत्मा को बचाना चाहते हैं तो जनता को भी रवैया बदलना होगा। भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी नागरिक-भागीदारी का मंच है। यह मंच तभी सार्थक है जब नीति, प्रतिस्पर्धा, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, स्थानीय बुनियादी ढांचा केंद्र में हों। सादगी कोई सजावट की वस्तु नहीं, भारतीय राजनीति का आत्मा है। इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पार्टियों, संस्थाओं और सबसे बढ़कर मतदाताओं की है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### सच को स्वीकारें

जो मनोनुकूल नहीं है, जो अरुचिकर है, जिसकी आशा नहीं थी, उससे सामना होने पर मनुष्य या तो दुखी हो जाता है अथवा उसे बदलने की ठान लेता है। इसे अहंकार वश पुरुषत्व या संघर्षशीलता का नाम दे दिया जाता है। ऐसे कई संघर्ष जीवन में चलते रहते हैं। कभी वह सफल हो जाता है तो हर्ष से भर जाता है। जब सफल नहीं होता तो कुंठा पैदा होती है। यह निश्चित है कि जीवन में सभी कुछ वैसा नहीं होता, जैसा मनुष्य चाहता है। कुछ न कुछ ऐसा आवश्य होता है, जो उसे अप्रिय है। इस तरह सारा जीवन अनुकूल और प्रतिकूल के मध्य डोलते रहने में बीत जाता है। कई बार तनिक भी प्रतिकूलता अधिक अनुकूलता के आनंद को नष्ट कर देती है।

अगला जीवन कैसा होगा? किसी को भी ज्ञात नहीं है। वर्तमान को ही स्वर्ग या नर्क बनाना है। यह स्वयं मनुष्य के हाथ में है। परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार रचा है जिसे देखने और अनुभव करने हेतु एक जीवन कम है। सुंदर प्रकृति, मनमोहक पशु-पक्षी जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। सुंदर फूल, फल, वनस्पतियां तृप्त कर देने वाली हैं। ऋतुओं का बदलना सदा उत्सुकता बनाए रखता है। निद्रा जैसा सुख काल कोई नहीं है, जो मनुष्य के तन की संरचना में ही परमात्मा ने निहित कर दिया है। इनके आगे मनुष्य की रुचियां, अरुचि अत्यंत लघु हैं। मनुष्य व्यापकता के स्थान पर लघुता से जुड़ कर अपने लिए दुख आमंत्रित करता है। जैसा सामने आ रहा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना एक साहसिक कार्य है। दुख को सुख में बदलना सीखें। दुखों का पोषण कायरता है। दुखों को नकार देना, प्रिय-अप्रिय के सोच का चक्रव्यूह, जो जीवन के सुख पर ग्रहण बना हुआ है, उसे भेद कर बाहर निकल आना वीरता है। युद्ध में लगे घाव नहीं देखे जाते, विजय का उत्सव मनाया जाता है। जो सुख हैं, उनकी तीव्र अनुभूति दुखों को नकार देती है। मनुष्य जीवन मिला है, जो सारे जीवों से श्रेष्ठ है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

## पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

### मुस्लिम मतदाताओं के हित की बात

रामिश सिद्दीकी द्वारा लिखित आलेख 'वोट बैंक के दायरे से बाहर निकलें मुस्लिम' में जिन मुद्दों की चर्चा की गई है वे बेहद प्रासंगिक हैं। ये हरेक जाति, धर्म के मतदाताओं के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मुस्लिम मतदाताओं के लिए। दरअसल मतदाता होना नागरिकता का पर्याय है। नतीजतन सच्चा नागरिक कर्तव्य का निर्वहन तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखकर मतदान करे, जिसमें सभी देशवासियों का सम्यक हित निहित होता है। आजादी के बाद मुसलमानों में पृथकता, अलगाव का बीजारोपण उनको अल्पसंख्यक संबोधित करके किया गया। उनका इस तरह भयादोहन किया जाता रहा कि आम मुस्लिम मतदाता कभी स्वतंत्र नागरिक की हैसियत रखकर मतदान कर ही नहीं पाया। अगर ऐसा हुआ होता तो मुस्लिम मतदाता पंथनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता महसूस करता। वे यह देख पाने में सक्षम होते कि जिन नेताओं ने हमें बरगलाया, बहकाया वे ही अपने बच्चों के मामले में अलग रीति-नीति अपना रहे हैं। उनके बच्चे रोजी-रोजगार के लिए विदेश गए। मगर उनके इलाकों को आधुनिक अस्पताल, शिक्षण संस्थान से वंचित रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने विकास के लिए वोट करने के बजाय किसी को हराने के लिए किया। उनका यही दृष्टिकोण उन्हें वोटबैंक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हम सब 21वीं सदी के तकनीकी युग में जी रहे हैं। इस दौर में भी मुस्लिमों का किसी खास दल का वोटबैंक बना रहना समझ में नहीं आता। बदलते समय के अनुसार उन्हें अपने सोच भी बदलने चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, पटना

### जीत से बढ़ी जवाबदेही

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्वकप का खिताब जीतकर नया इतिहास रचा है। यह जीत 47 वर्षों की मेहनत, संघर्ष, समर्पण और धैर्य का परिणाम है। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि अवसर मिले तो वे किसी भी मंच पर पुरुष खिलाड़ियों की तरह ही शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। महिला टीम ने दबाव के हर पल में संतुलन बनाए रखा। कठिन परिस्थितियों में कप्तान हरमनप्रीत कौर की रणनीति, गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ और बल्लेबाजों की शांत लेकिन दमदार पारी ने इस अभियान को आदर्श रूप दिया। फाइनल मुकाबले में भारत के लिए शेफाली वर्मा ने बल्ले और गेंद से कमाल दिखाया। इस पूरे टूर्नामेंट में रिचा घोष ने 331 रन बनाए एवं 12 छक्के लगाए। यह जीत टीमवर्क, अनुशासन और सकारात्मक सोच का अद्भुत मिश्रण था। वर्षों तक महिला क्रिकेट उपेक्षा और सीमित संसाधनों से जूझता रहा। बजट, स्पांसरशिप, मीडिया कवरेज और बुनियादी सुविधाओं में असमानता के बावजूद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई। यह जीत यह संदेश देती है कि भारत की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाली नहीं हैं।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

### चुनावी घोषणा पत्र

चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र अब लोकलुभावन वादों का पुलिंदा बनकर रह गए हैं। इनमें ऐसे तमाम आकर्षक वादे होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के लिए पूरा करना संभव नहीं होता। हाल के समय में कई राज्यों में यह देखने को मिला है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के जिन वादों के साथ सत्ता में आए, उन्हें वे पूरा नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि राज्य विशेष की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी। कुछ राज्यों में तो यह भी देखने को मिला कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के वादों को आधे-अधूरे ढंग से पूरा किया या फिर उन्हें पूरा करने की घोषणा करने के बाद ठिठक गए। बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्रों में अनेक ऐसे वादे हैं, जो कुल मिलाकर लोकलुभावन ही हैं। राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में लोगों को लुभाने वाले तमाम वादे तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा? इसका एक कारण यह है कि आम जनता घोषणा पत्रों के वादों को लेकर ऐसे सवाल कभी नहीं पूछती कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य रखती है? जिस दिन जनता यह जानने की कोशिश करने लगेगी, घोषणा पत्र गंभीरता के साथ तैयार किए जाने लगेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा इसलिए नहीं हो पाता।

मनीष कुमार, पटना

## X पोस्ट

अब घर बैठी हर लड़की कह सकती है कि मैं भी कर सकती हूं। जो कल तक क्रिकेट देखती थीं, वे आज जीत रही हैं। देबाशीष सरकार@DebashishHiTs

वर्षों तक देश में क्रिकेट का मतलब सचिन, धौनी और विराट हुआ करते थे। आज वक्त ने करवट बदली है। महिला क्रिकेटरों की चर्चा हो रही है। गांवों की लड़कियों ने दीप्ति, स्मृति, हरमनप्रीत और जेमिमा के विजयी आंसुओं में अपने सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। भारत क्रिकेट प्रेमी देश तो बहुत पहले से था, पर आज जाकर क्रिकेट का सच्चा प्रेमी देश बना है। अतुल कुमार राय@AuthorAtul

इस चमत्कारिक जीत ने भारतीय नारी की शक्ति को ऊर्जा दी है। यह जीत महिला क्रिकेट में नई क्रांति लाएगी। कुछ उसी तरह जैसी 1983 में कपिलदेव की कप्तानी में टीम इंडिया को नई ऊंचाई मिली। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

महिला क्रिकेट को पूर्ण स्वीकार्यता मिल गई, दर्शक मिल गए, खिलाड़ियों को पहचान मिल गई। यह किसी टीम से बढ़कर क्रिकेट की जीत है। डा. भूपेंद्र सिंह@DrBS07

## जनपथ

बनीं चैंपियन बेटियां बाग-बाग दिल आज,
हीरे जैसी बेटियां हमको इन पर नाज।
हमको इन पर नाज ताज वे घर ले आईं,
चौके-छक्के मार आज दुनिया में छाईं।
चूके थे दो बार न चूकी अबकी हरमन,
करि सम्मिलित प्रयास अंततः बनीं चैम्पियन।

- ओमप्रकाश तिवारी


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 200


https://t.me/AllNewsPapersPaid

# { संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 4 नवम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

## महिला टीम को बधाई और सलाम

भारतीय खेल जगत के लिए रविवार 2 नवंबर एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्वकप में शानदार जीत दर्ज की है। 1973 से महिला क्रिकेट टीम न केवल ऐसी किसी ऐतिहासिक जीत के इंतजार में थी, बल्कि इसके साथ-साथ और बहुत से मोर्चों पर उसे सफल होने की जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। क्रिकेट खेलने का मैदान, तरीके, नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। दोनों वर्गों के खिलाड़ियों को एक जैसी मेहनत मैदान पर करनी पड़ती है। लेकिन महिला खिलाड़ियों के लिए संघर्षों का दायरा कहीं अधिक बड़ा है। पहला संघर्ष तो लैंगिक भेदभाव का ही है। क्रिकेट को जेन्टलमैन गेम कहा जाता है, यानी भद्रजनों का खेल। अंग्रेजों की मानसिकता उनके बनाए इस खेल में पूरी तरह झलकती है, जहां समाज के उच्च तबके के लोग ही भद्र माने जाते थे और उनके पुरुष ही इस खेल को खेल सकते थे। हालांकि वह युग अलग था। गेंद की तरह जब यह खेल भी सीमाओं के पार जाकर खेला जाने लगा तो इसमें देश और काल के हिसाब से तब्दीलियां आने लगी। महिलाओं ने भी क्रिकेट खेलना शुरु किया। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज ने आदतन उन्हें हतोत्साहित किया। इसके लिए कई तरीके आजमाए गए। टीशर्ट-लोअर पहनी महिलाओं का मजाक उड़ाना, उनकी शारीरिक क्षमता पर संदेह करना यह सब तो चलता ही रहा। इसके साथ महिला खिलाड़ियों को पुरुष टीमों की अपेक्षा कम फीस देना, उनके टीम प्रबंधन, सुविधाओं और संसाधनों पर खर्च न करना, महिला टीमों के मैच के लिए प्रायोजकों का न मिलना, ऐसी कई अड़चनें दिखाकर महिला खिलाड़ियों को यही संदेश बार-बार दिया गया कि वे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बनी हैं।

आज से 20 साल पहले के दौर में मिताली राज जैसी महिला क्रिकेटरों को इसी बात का दुख था कि महिला क्रिकेट टीम को न पहचान मिलती है, न सम्मान मिलता है, बल्कि उपेक्षा करने में कोई कमी नहीं की जाती। हालात अब भी कमोबेश वही हैं, इसलिए किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। हालांकि थोड़े बहुत बदलाव दिखना शुरु भी हो गए हैं। जीत के तुरंत बाद बीसीसीआई सचिव देवजित सैकिया ने घोषणा की है कि टीम, सहयोगी स्टाफ और चयनकर्ताओं को कुल 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि आईसीसी ने लगभग 37. 8 करोड़ रुपये का ईनाम विजेता टीम को दिया है। बीसीसीआई के पास धन और संसाधनों की कमी नहीं है, लिहाजा वह एक बड़ी राशि महिला टीम को दे रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि क्या बीसीसीआई की तरफ से महिला खिलाड़ियों को यही प्रोत्साहन आगे भी मिलता रहेगा। देश की कई महिला क्रिकेट खिलाड़ी, जो प्रतिभा होने के बावजूद कई किस्मों के भेदभाव में फंस जाती हैं, उन्हें इससे निकालने और आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड के पास क्या कोई योजना है। देवजित सैकिया ने यह भी कहा कि 'जय शाह के नेतृत्व में महिला क्रिकेट में क्रांति आई। मैच फीस समानता और पुरस्कार 300प्रतिशत बढ़े। यह जीत महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई देगी।' उनका यह बयान चापलूसी से प्रेरित लगता है। क्योंकि महिला क्रिकेट टीम में यह क्रांति खिलाड़ियों की अपनी मेहनत और संघर्षों से हार न मानने के जज्बे के कारण आई है। इसमें जय शाह का व्यक्तिगत योगदान क्या है, यह अब तक सामने नहीं आया है। बल्कि पिछले साल अक्टूबर में जब टीम की सदस्य जेमिमा रोड्रिग्स की मुंबई जिमखाना की सदस्यता केवल इसलिए खत्म कर दी गई, क्योंकि उनके पिता इवान रोड्रिग्स पर क्लब में धार्मिक गतिविधि चलाने का आरोप लगा, तब जय शाह ने जेमिमा के बचाव में कुछ कहा हो, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। बल्कि इस घटना के बाद जेमिमा को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। बताने की जरूरत नहीं कि ट्रोलर्स भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक थे।

केवल धर्म के आधार पर जेमिमा रोड्रिग्स को मानसिक तौर पर परेशान किया गया। लेकिन वे फिर भी मैदान पर डटी रहीं और भारत के लिए फाइनल का टिकट हासिल करने में उनका बड़ा योगदान रहा। अब जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ हो रही है, मगर इसके साथ क्या समाज इस बात को समझेगा कि किसी भी बात को तूल देकर धार्मिक विवाद खड़े करने का काम भाजपा के शासन में जिस तरह हो रहा है, उससे समाज खुद अपना कितना नुकसान कर रहा है। आज जब विश्व कप जीतने पर केवल खुशियां मनाई जानी चाहिए, तब ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभाव अब तक क्यों होता रहा।

इतनी ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि के बाद भी यह भेदभाव पूरी तरह खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बीसीसीआई ने कहा है कि भविष्य में पूर्ण समानता सुनिश्चित होगी। अब पुरस्कार भी समान होंगे। लेकिन यह भविष्य क्या उस आने वाले कल की तरह होगा, जो कभी आता ही नहीं है, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी बेशक बीसीसीआई ने 51 करोड़ रूपए टीम को दिए हैं, लेकिन 2024 के टी 20 में पुरुष टीम ने विश्व कप जीता था तो उसे 125 करोड़ दिए गए थे। 125 और 51 के बीच जितना बड़ा फासला है, पूर्ण समानता का लक्ष्य हासिल करना भी उतना ही दूर लग रहा है। हालांकि महिला खिलाड़ियों को सौ मुबारक और उनके जज्बे को सलाम जो इस बात पर भी खुश हैं कि उनके लिए मैच में समान फीस का फैसला लिया गया है।

क्रिकेट से पहले हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, तैराकी, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, भारोत्तोलन, दौड़, जिमनास्टिक्स, पर्वतारोहण जैसे तमाम खेलों में महिला खिलाड़ियों ने अपनी धाक जमाई है। लेकिन कई खिलाड़ियों को राजनैतिक शोषण, नाइंसाफी का शिकार बनाया गया, कईयों को संसाधनों की कमी के कारण आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। विश्वकप उठाती महिलाओं की सुंदर तस्वीर देश देखकर गदगद है, तो क्या जंतर-मंतर पर इंसाफ के लिए संघर्ष करती महिलाओं की तस्वीर देखकर शर्मिंदगी आई, यह सवाल अब खुद से पूछने का वक्त आ गया है।

# पटना रोड शो: एनडीए के लिए तीन बुरी खबरें

राजधानी पटना में प्रधानमंत्री के बहुप्रचारित रोड शो को अगर, बिहार के विधानसभाई चुनाव के रुझान का संकेतक माना जा सकता है, तो यह दर्ज किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रोड शो की चर्चा सबसे ज्यादा तीन ऐसी चीजों के लिए हो रही है, जो इस रोड शो के आयोजकों के लिए अच्छी खबर नहीं देती हैं। इनमें पहली है, इस रोड शो के लिए जिस तरह से पटना के करीब-करीब सभी मुख्य मार्गों को घंटे बंद रखा गया था और इसकी वजह से इस रोड शो से दूर-दूर तक के इलाकों में भी लोगों को घंटों सड़कों पर जाम में फंसे रहना पड़ा था, उस पर खुलकर सामने आयी आम लोगों की बड़ी संख्या की मुखर नाराजगी। बेशक, चूंकि रोड शो करने को प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार का एक प्रमुख तरीका ही बना लिया गया है, हैरानी की बात नहीं है कि इससे पहले अन्य राज्यों के दूसरे प्रमुख शहरों में भी प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के इस तरीके से हुई व्यापक असुविधा पर लोगों के बीच नाराजगी पैदा हुई हो और यह नाराजगी जाहिर भी हुई हो। फिर भी मुख्यधारा के मीडिया पर सत्ताधारी संघ-भाजपा के लगभग पूर्ण नियंत्रण के चलते, इससे पहले शायद ही कभी यह नाराजगी उस तरह दर्ज हुई होगी, जिस तरह पटना रोड शो के मामले में, खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए सामने आयी है। इस नाराजगी को, दूसरी ओर इस रोड शो के रास्ते पर लोगों की उत्साहहीन तथा मामूली उपस्थिति के साथ जोड़कर देखा जाए, तो इसका कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है कि बिहार की जनता का मूड क्या है? जाहिर है कि सब कुछ के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी, इस चुनाव में भी भाजपा का ही नहीं एनडीए का भी सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता हैं। इस पत्ते का चुनावी बाजी में वजन घटता जाना, जिसकी पुष्टि चुनाव क्षेत्र से आ रही दूसरी अनेक रिपोर्टों से भी होती है, सत्ताधारी गठजोड़ के लिए अच्छी खबर नहीं है।

सत्ताधारी गठजोड़ के लिए इससे भी बड़ी बुरी खबर है, इस रोड के संबंध में बहुत व्यापक रूप से दर्ज हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नामौजूदगी। बेशक, नीतीश कुमार की नामौजूदगी को ढांपने के लिए, रोड शो में प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए ललन सिंह को लाया गया, जिन्हें जदयू के शीर्ष नेताओं में माना जाता है। लेकिन, ललन सिंह को नीतीश कुमार का काफी सस्ता स्थानापन्न ही माना जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सचाई यह है कि इस रोड शो में ललन सिंह की मौजूदगी ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री के रोड शो की भी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, जितनी चर्चा इस रोड शो से नीतीश कुमार की नामौजूदगी की है। नीतीश कुमार अपनी अनुपस्थिति के जरिए, गठजोड़ की संचालक बनने की कोशिश कर रही भाजपा को, अपनी नाखुशी का स्पष्ट संदेश देना चाहते थे और वह संदेश उन्होंने जोरदार तरीके से दिया है।

और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने का मंत्रजाप करने के बावजूद, नीतीश कुमार की पार्टी के ठीक बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, व्यवहार में सत्ताधारी गठजोड़ की संचालक बनने की कोशिश कर रही भाजपा को, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के रोड शो से दूर रहने के जरिए क्या संदेश दिया है? संदेश यही है कि चुनाव के बाद एनडीए सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मुद्दे पर भाजपा जिस तरह की अस्पष्टता जान-बूझकर पैदा कर रही है, वह जाहिर है कि नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है।

और ऐसा सबसे बढ़कर इसलिए है कि मोदी के बाद, उनकी भाजपा में दो नंबर माने जाने वाले अमित शाह खुद अपने इस प्रकार के बयानों से कि मुख्यमंत्री का चुनाव, चुनकर आए विधायकों द्वारा किया जाता है, भाजपा की नीयत और

राजेंद्र शर्मा

> सत्ताधारी गठजोड़ के पहले ही काफी भौंथरे नजर आ रहे वृहत्तर चुनाव नैरेटिव के लिए, इतनी ही बुरी खबर इस रोड शो में एक और चर्चित नामौजूदगी में छिपी थी। यह नौजूदगी थी, मोकामा से जदयू के उम्मीदवार, बाहुबली/ माफिया अनंत सिंह की। और यह नामौजूदगी सुनिश्चित की गयी थी, रोड शो से ठीक पहले की रात में अनंत सिंह की, चुनाव प्रचार के ही दौरान अपने राजनीतिक विरोधी, दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी के जरिए।

इरादों के संबंध में नीतीश कुमार के संदेहों को हवा देते रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह अपने मुंह से, भाजपायी उप-मुख्यमंत्री, साम्राट चौधुरी को मोदी जी द्वारा 'बहुत बड़ा आदमी' बनाए जाने की घोषणा ही नहीं कर चुके हैं, एनडीए का चुनाव घोषणापत्र जारी करने के लिए आयोजित हास्यास्पद प्रैस कान्फ्रेंस में चंद सैकेंड में नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं के चलता कर दिए जाने के बाद, अकेले साम्राट चौधरी द्वारा घोषणापत्र के संबंध में पत्रकारों को संबोधित कराए जाने के जरिए, उनके भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की पुष्टि भी कीर जा चुकी है।

दूसरी ओर, कहने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में, कथित रूप से पिछली गठजोड़ सरकार के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणाओं के बाद, जिस तरह भाजपा ने बिना किसी बहाने के अपने नेता फडनवीस को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया और शिंदे को दो उप-मुख्यमंत्रियों में से एक के स्टूल पर बैठा दिया, नीतीश कुमार के समर्थक उसे भूले नहीं हैं। इसमें इतना और जोड़ लीजिए कि नीतीश कुमार के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा खराब, नीतीश कुमार की पार्टी का सांगठनिक स्वास्थ्य है। व्यापक रूप से यह माना जाना निराधार ही नहीं है कि जदयू में शीर्ष नेतृत्व तक, भाजपा ने गहरी सुरंगें बना ली हैं, जिसने भाजपा के पैंतरों के सामने नीतीश कुमार को और वेध्य बना दिया है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद के फैसले तक अगर वह अगर इंतजार करते हैं, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि सत्ताधारी गठजोड़ में जारी इस रस्साकशी की खबरों के नुकसान की भरपाई, प्रधानमंत्री के इसके दावों से शायद ही हो सकती है कि प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन में 'राजद और कांग्रेस एक-दूसरे के बाद नोंच रहे हैं' या 'कनपट्टी पर कट्टा रखकर राजद ने कांग्रेस से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा लिया है। नीतीश कुमार के समर्थक आधार के सक्रिय समर्थन के बिना, भाजपा चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं टिक पाएगी।

सत्ताधारी गठजोड़ के पहले ही काफी भौंथरे नजर आ रहे वृहत्तर चुनाव नैरेटिव के लिए, इतनी ही बुरी खबर इस रोड शो में एक और चर्चित नामौजूदगी में छिपी थी। यह नौजूदगी थी, मोकामा से जदयू के उम्मीदवार, बाहुबली/ माफिया अनंत सिंह की। और यह नामौजूदगी सुनिश्चित की गयी थी, रोड शो से ठीक पहले की रात में अनंत सिंह की, चुनाव प्रचार के ही दौरान अपने राजनीतिक विरोधी, दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी के जरिए। बेशक, यह गिरफ्तारी सबसे बढ़कर, सत्ताधारी गठजोड़ के ''जंगलराज बनाम सुशासन'' की लड़ाई के नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाने के लिए और सबसे बढ़कर प्रधानमंत्री के दामन को इस कथित सुशासन के दामन पर लगे खून के छींटों से सुरक्षित रखने के लिए, बहुत सोच-विचार कर की गयी थी। लेकिन, चुनाव के बीचों-बीच हत्या कर सकने वाले माफिया से दूरी बनाने के इस नाटक के पीछे की यह सचाई किसी से छुपी नहीं रही है कि बिहार में शासन-प्रशासन ने अनंत सिंह का चुनाव प्रचार तक तब तक जारी रहने दिया था, जब तक सत्ताधारी गठजोड़ के पटना के गिर्द के विधानसभा उम्मीदवारों के हिस्से के तौर पर, उसके प्रधानमंत्री के रोड शो के काफिले में शामिल होने का ही खतरा पैदा नहीं हो गया। इसके बावजूद, बाकायदा अनंत सिंह को वार्ताओं के जरिए सरेंडर करने के लिए तैयार किया गया और सरेंडर करने के बाद सीधे जेल भेज दिया गया क्योंकि पुलिस ने रिमांड की मांग तक नहीं की थी। इससे पहले नीतीश कुमार के सुशासन की पुलिस और प्रशासन ने मृतक को ही अपराधी घोषित कर, इसका साफ तौर पर एलान कर दिया था कि उनका सुशासन किस के साथ खड़ा है।

लेकिन, मरहम-पट्टी की इस तमाम कोशिश के बाद भी, अनंत सिंह प्रकरण और उस पर सत्ताधारी गठजोड़ की प्रतिक्रिया ने, लालू राज को जंगलराज बताकर, नीतीश-भाजपा राज को सुशासन बनाने के उस पूरे नैरेटिव को तार-तार कर दिया है, जो मुख्यधारा के मीडिया के सहारे, अति-प्रचार के बल पर और जातिवादी-सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के सहारे, वर्षों में खड़ा किया गया था और जिसका बिहार के हरेक चुनाव में पिछले दो दशक से ज्यादा में लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा था। यह पूर्वाग्रहों का सहारा लेकर, अति-प्रचार के जरिए, मीडिया के बल पर किसी भी झूठ को, सच मनवाने की संघ-भाजपा के गोयबल्सीय कार्यनीति का, प्रगति के गुजरात मॉडल से भी पुराना उदाहरण है। इस नैरेटिव का यथार्थ से कुछ लेना-देना नहीं है। वर्ना सचाई यह है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, बलात्कार आदि गंभीर अपराधों के मामले में, नीतीश कुमार के सुशासन में 2023 में, जिसके लिए आखिरी आंकड़े उपलब्ध हैं, बिहार देश के सबसे अपराधग्रस्त राज्यों में चौथे नंबर पर था। और उसका चौथा स्थान, अपराधों की कुल संख्या के लिहाज से नहीं, प्रति एक लाख आबादी के आंकड़े के हिसाब से है। सुशासन बाबू के बिहार के लिए यह आंकड़ा, 41 है जो कि 30 से 35 तक के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। और बिहार के अपराधों में अपहरण तथा अगवा करने की वारदातों का हिस्सा कुछ गंभीर अपराधों में 40 से 50 फीसद तक है। 2023 में बिहार में इस श्रेणी के 13,392 अपराध दर्ज हुए थे, जो 2022 के 11,822 के आंकड़े से पूरे 13 फीसद की बढ़ोतरी को दिखाता था।

इतना ही नहीं, लालू-राबड़ी राज (1990-2005) और नीतीश राज के बीच, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार ही अपराध दर में कमी नहीं, बढ़ोतरी ही हुई है। लालू-राबड़ी राज के आखिरी वर्ष, 2004 में कुल अपराध दर हर एक लाख की आबादी पर 122.4 थी, जबकि नितीश राज में (2005-23) यह दर 2014 में 150 हो गयी, जो 2019 में और बढ़कर 164.8 और 2023 तक बढ़कर, 200 हो गयी। कुल संख्या में 2004 के 115,216 से दोगुने होकर अपराध 2019 में 269,096 पर पहुंच गए। महिलाओं और दलितों पर अपराधों के मामले में तो वास्तव में नीतीश राज ही असली जंगल राज है। मोदी के पटना रोड शो ने नीतीश कुमार के सुशासन को भी बेपर्दा करने काम किया है।

**(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)**

# भाजपा ने चुनावों से पहले सांस्कृतिक अंधभक्ति की नींव रखी

■ **आशीष विश्वास**

जाहिर है, अगर राजनीतिक नेता ज़िद करें, तो 'कविगुरु' रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ गीत विशेष अवसरों को छोड़कर नहीं गाए जा सकते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने राज्य पुलिस को एक कांग्रेस नेता के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसने कुछ दिन पहले राज्य के श्रीभूमि (करीमगंज) ज़िले में एक पार्टी समारोह में 'आमार सोनार बांग्ला' गाने का 'पाप' किया था।

अपने फ़ैसले की व्याख्या करते हुए, श्री सरमा ने कहा कि गायक को पता होना चाहिए था कि वह असल में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहा था! भारतीय धरती पर एक सभा में इसे गाना राज्य और देश दोनों का अपमान था।

श्री सरमा के इस ऐलान से पहले ही इस तरह के मुद्दों पर विवाद खड़ा हो गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तल्ख रिश्तों के अलावा, ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश में सक्रिय इस्लामी चरमपंथी एक स्वतंत्र मुस्लिम गणराज्य बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री शर्मा ने कहा कि चूंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक - पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसे बांग्लादेशी 'मियां' मुसलमानों - के समर्थन के लिए जानी जाती है, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता असम में बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति नहीं करेगा।

> बांग्लादेश की बात करें तो यह बहुत बाद में आया। समस्या यह थी कि श्री सरमा और उनके जैसे लोग स्वतंत्रता आंदोलन या बंगाल या अन्य जगहों पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश-विरोधी संघर्षों से वाकिफ नहीं थे, यही उनके निरर्थक तर्कों की व्याख्या करता है। हालांकि, बंगाल कांग्रेस के हलकों का मानना है कि सरमा श्री गोगोई के तर्कों के आगे खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की खुफिया एजेंसियां इस्लामी चरमपंथियों की एक बड़े 'स्वतंत्र' इस्लामी बंगाल बनाने की दीर्घकालिक योजनाओं से आम तौर पर वाकिफ थीं। उन्हें वर्तमान में तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। भारत सरकार के हलकों में ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन पिछले साल 8 अगस्त को अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश पर अप्रत्याशित कब्ज़ा करने से पूर्वोत्तर की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया।

अस्थायी मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए, डॉ. यूनुस ने पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका के साथ सांठगांठ करके भारत सरकार की सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। उन्होंने बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की और चीन और पाकिस्तान से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने भारत के साथ व्यापार और व्यवसाय की मात्रा कम कर दी, जबकि इस्लामी देशों के साथ संपर्क बढ़ाए। स्वाभाविक रूप से, भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नए रुझानों पर ध्यान देना पड़ा। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि इसी संदर्भ में श्री सरमा ने यह बात कही थी।

भाजपा विरोधी दल मुख्यमंत्री के तर्क से कतई सहमत नहीं थे। सही हो या गलत, सरमा ने एक कट्टर मुस्लिम विरोधी और कट्टर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है। राज्य कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, टैगोर ने यह गीत लिखा था, जो बंगालियों और यहां तक कि दुनिया भर के कई भारतीयों के बीच एक शक्तिशाली भावनात्मक एकीकरण का सूत्रधार बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गीत को न गाने का कोई ठोस कारण नहीं हो सकता।

बांग्लादेश की बात करें तो यह बहुत बाद में आया। समस्या यह थी कि श्री सरमा और उनके जैसे लोग स्वतंत्रता आंदोलन या बंगाल या अन्य जगहों पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश-विरोधी संघर्षों से वाकिफ नहीं थे, यही उनके निरर्थक तर्कों की व्याख्या करता है।

हालांकि, बंगाल कांग्रेस के हलकों का मानना है कि सरमा श्री गोगोई के तर्कों के आगे खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी 'आमार सोनार बांग्ला' गीत को लेकर एक ग़लती में शामिल रही थी। इसके अलावा, एक टीएमसी मंत्री का हाल असम के मुख्यमंत्री से भी कहीं ज़्यादा बुरा हुआ, जब उन्होंने बांग्लादेश में ही एक आधिकारिक समारोह में 'आमार सोनार बांग्ला' गाने की कोशिश की।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बांग्लादेश यात्रा पर संस्कृति मंत्री और एक गायक, श्री इंद्रनील सेन को भी साथ ले गई थीं। कुछ हद तक भावुक होकर, श्री सेन, जिनका परिवार बांग्लादेश से आया था, अपने दर्शकों से कभी-कभार बातचीत करते हुए भी, अचानक 'आमार सोनार बांग्ला' की कुछ पंक्तियां गाने लगे थे।

इसके तुरंत बाद दर्शकों ने विरोध जताया। लोग खड़े हो गए और सेन के गीत को बीच में ही रोक दिया और बताया कि 'आमार सोनार बांग्ला' उनका राष्ट्रगान है। वे किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना किसी गंभीरता के, उस गीत को यूं ही गाने की इजाज़त नहीं दे सकते। धिक्कार पाकर, निराश सेन ने गाना बंद कर दिया और बैठ गए। पश्चिम बंगाल से आए गणमान्य लोगों के साथ-साथ उन्होंने भी सबक सीख लिया था।

जहां तक श्री सरमा की बात है, उन पर टैगोर विरोधी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने और यह साबित करने के एक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश की कि राज्य में उनकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेता 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय मियों को खुश करने के लिए पड़ोसी मुस्लिम देश का राष्ट्रगान गा रहे हैं। इस प्रक्रिया में, मुख्यमंत्री ने एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है।

# ललित सुरजन की कलम से

## वंशवाद चिरजीवी हो!

*महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके बेटे नितेश को विजयी बनाने में मतदाताओं ने संकोच नहीं किया। सुशील कुमार शिंदे की बेटी भी दुबारा विधायक चुन ली गई हैं। भले ही इसके पूर्व उनके माता-पिता दोनों चुनाव हार चुके हैं। विलासराव देशमुख के बेटे भी जीत गए हैं, जबकि छगन भुजबल एवं उनके पुत्र दोनों एक साथ विधानसभा में होंगे। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी पंकजा न सिर्फ चुनाव जीत गई हैं बल्कि वे पिछले दो माह से लगातार दावा कर रही हैं कि महाराष्ट्र के युवा मतदाता उनको ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन देखना चाहते हैं। यह कुछ वैसी ही बात हुई जैसे मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण को उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रखा है।*

**(देशबन्धु में 23 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित)**

https://lalitsurjan.blogspot.com/2014/10/blog-post_24.html

### पावन प्रसंग

## कार्तिक पूर्णिमा जैन चातुर्मास का समाप्ति दिवस

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सनातन धर्म में कार्तिक माह और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में गंगा स्नान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया है।

वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जब भगवान विष्णु और चंद्र देवता की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है और इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है।

हिंदू सनातन परंपरा में प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पूजनीय माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की विशेष आराधना करने का विधान है। पूर्णिमा का दिन वैसे तो हर महीने शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन जब यह तिथि श्रीहरि विष्णु को समर्पित पवित्र कार्तिक मास में आती है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में जैन समाज में चातुर्मास की समाप्ति का दिवस है।

भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के उपलक्ष्य में, जिसे 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में, जिसे 'गुरु पर्व' भी कहा जाता है। देवी तुलसी के पृथ्वी पर जन्म के सम्मान में इस दिन को 'देव दीपावली' भी कहा जाता है, जब देवता पृथ्वी पर आते हैं और उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं।

हिंदू पौराणिक कथाओं में कार्तिक पूर्णिमा कई किंवदंतियों से जुड़ी है। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव और देवी पार्वती एक संतान चाहते थे, और भगवान शिव ने देवताओं से एक पुत्र उत्पन्न करने में मदद करने का अनुरोध किया। देवताओं ने कार्तिकेय की रचना की, जिनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इसलिए, कार्तिक पूर्णिमा को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की है। पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था, जिन्हें एक राक्षस ने चुरा लिया था। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत, जो बाद में मनु कहलाए, के सामने प्रकट हुए और उन्हें आने वाली बाढ़ से खुद को और वेदों को बचाने के लिए एक नाव बनाने को कहा। मछली रूपी भगवान विष्णु ने नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इसे सिखों के लिए 'गुरु पर्व' या 'गुरु पूरब' के रूप में मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा भगवान कार्तिकेय के जन्म का भी दिन है। कुछ पौराणिक मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का अवतरण हुआ था।

धर्मप्राण क्रान्तिकारी वीर लौंकाशाह जैसी महान आत्मा आज के ही दिन अवतरित हुईं। उस युग में धार्मिक क्षेत्र में गहन अंधकार परिव्यास था। धर्म के नाम पर कई तरह के पाखण्ड और आडंबरों को पुष्ट किया जा रहा था। लौंकाशाह ने जब यह सब कुछ देखा तो उनका अंतर उद्वेलित हुए बिना नहीं रहा।

**- कांतिलाल मांडोत**

### आपके पत्र

## ऐतिहासिक विजयः भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा विश्व कप का नया इतिहास

आज का दिन भारतीय खेल इतिहास के स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित रहेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस अदम्य जज़्बे, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है जिसने वर्षों से भारतीय बेटियों को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व, उत्साह और प्रेरणा का है— क्योंकि यह सिर्फ़ मैदान की जीत नहीं, बल्कि मानसिकता की भी जीत है।

भारतीय महिला क्रिकेट का यह गौरवशाली अध्याय उस लंबे सफर का परिणाम है, जो संघर्ष, सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बीच शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब महिला क्रिकेट को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, न दर्शक होते थे, न प्रायोजक। लेकिन समय बदला, और इन बेटियों ने अपने खेल, समर्पण और प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खेल का मैदान किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। आज जब भारत विश्व कप जीतकर विश्व का सिरमौर बना है, तो यह जीत हर उस बेटी की आवाज़ है जिसने अपने सपनों को समाज की बंदिशों से ऊपर रखा। विश्व कप के इस रोमांचक फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 298 रन बनाए। पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। स्मृति ने संयमित लेकिन महत्वपूर्ण 45 रन बनाकर टीम को मजबूत आधार दिया, जबकि शेफाली वर्मा ने आक्रामक शैली में खेलते हुए 78 गेंदों में 87 रन ठोके। उनकी पारी में चौके-छक्कों की झड़ी लगी रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर इस बार जल्दी आउट हो गईं, लेकिन युवा बल्लेबाज़ ऋचा घोष ने 34 रनों की अहम पारी खेली और टीम को एक बार फिर स्थिरता दी। मिडिल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को लगभग 300 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

दक्षिण अफ्रीका की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो शुरुआती ओवरों में उसने तेज़ शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपनी पकड़ बना ली। रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को बांधे रखा। शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 7 ओवर में मात्र 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनका हरफनमौला प्रदर्शन भारतीय जीत की रीढ़ साबित हुआ। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ता गया और अंततः भारतीय टीम ने जीत के साथ इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान मिला।

2025 का यह वर्ष भारतीय खेलों के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज होगा। भारत की बेटियां अब सिर्फ़ इतिहास नहीं, भविष्य लिख रही हैं। उनकी यह विजय हर भारतीय के दिल में गर्व, प्रेरणा और उम्मीद की लौ जगा रही है।

**— डॉ. प्रियंका सौरभ**

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

## चिंतन

# जीत के पीछे तपस्या, कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता

यह कहावत पूरी तरह से सच है कि कामयाबी के पीछे तपस्या, यानी कड़ी मेहनत, समर्पण व दृढ़ता होती है। सफलता आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना, लगातार प्रयास और असफलताओं से सीखने की जरूरत होती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से जुट जाना जरूरी है। यही किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से टीम ने 52 साल बाद विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है। रविवार को मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत की लड़कियों ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। ये वो टीम है, जिसके हर खिलाड़ी की कहानी प्रेरणा देती है। किसी के माता-पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को क्रिकेटर बनाया है तो किसी के पैरेंट्स सरकारी जॉब में रहे हैं। किसी के पिता ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं तो किसी के घरवाले सब्जी बेचते रहे हैं, लेकिन इन बेटियों ने अपने खुद के हौसले के दम पर नई उड़ान भरी है। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा रोहतक की रहने वाली हैं। इनके पिता ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं और मां गृहणी हैं। रेणुका सिंह की मां दर्जा चार की कर्मचारी हैं। राधा यादव के पिता सब्जी बेचते हैं। उमा छेदी के माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब इनकी लाड़लियों ने अपने जज्बे से नया इतिहास लिख दिया है। विश्व चैंपियन बनने के पीछे केवल खिलाड़ियों का ही नहीं, बल्कि माहौल और सुविधाओं का भी अहम योगदान रहा है, जो बीसीसीआई ने उन्हें उपलब्ध करवाईं। वो समय था जब भारत का महिला क्रिकेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से बहुत पीछे था, लेकिन विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत के बाद हालात बदल गए। जय शाह से पहले सभी बीसीसीआई अध्यक्ष इसे शुरू करने का प्लान ही बनाते रह गए, शाह ने इसकी शुरुआत 2023 में कर दी। ऐसे प्लेटफॉर्म पर युवा और घरेलू प्लेयर्स को विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, प्लेयर्स एक महीने तक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग, बेहतर कोच और प्रेशर सिचुएशन का सामना करने लगीं, जिसका फायदा इंडिया विमेंस टीम को भी मिला। इन्हीं मुकाबलों से टीम इंडिया को यास्तिका भाटिया, श्रेयांका पाटील, अमनजोत कौर, श्री चरणी, क्रांति गौड़ जैसी युवा और आक्रामक प्लेयर्स मिलीं। यास्तिका और श्रेयांका इंजरी के कारण वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सकीं, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने भारत को फाइनल में पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इस जीत के पीछे टीम के कोच का भी अहम रोल रहा। विश्व कप जीत के बाद जैसे ही हेड कोच अमोल मजूमदार सामने आए, वैसे ही हरमनप्रीत ने दोनों हाथों से उनके पैर छुए। जो बताता है कि टीम को इस मुकाम तक पहुचाने में उनका कितना योगदान रहा है। वैसे भी अनेक खिलाड़ियों ने भी इस विश्व कप को अमोल मजूमदार द्वारा बनाई गई रणनीति की ही जीत बताया है। हालात जो भी हों भारत की बेटियों ने 2 नवंबर 2025 के दिन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। भारतीय महिला टीम ने वो कारनामा किया जो 1983 में कपिल देव की टीम ने किया था। किसी ने भी मुकाबले की शुरूआत में नहीं सोचा था कि टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनेगी, लेकिन हमारी बेटियों ने आखिरकार वह कर दिखाया। जिससे पूरा देश गौरवान्वित और सम्मानित मसूस कर रहा है।

# स्त्री क्रिकेट का अविस्मरणीय समय

विजेता
विकेश कुमार बडोला

भारत को स्त्री विश्व क्रिकेट की निर्णायक प्रतियोगिता में विजय प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि पूरे 52 वर्ष मिली है। यह भारतीय स्त्री क्रिकेट के लिए एक अविस्मरणीय समय है। किंतु इस उपलब्धि की अतिप्रसन्नता एवं आत्ममुग्धता खिलाड़ियों पर हावी नहीं होनी चाहिए। संभवत: यही कारण रहा था अथवा निर्णायक प्रतियोगिता का दबाव-तनाव जो हरमनप्रीत एवं स्मृति ने अति सुरक्षात्मक होकर दब्बू बनकर बल्लेबाजी की तथा परिणामस्वरूप दोनों देर तक भी नहीं खेलीं एवं अधिक गेंदें खर्च करके कम रन बनाकर बाहर हो गईं। भविष्य में ऐस दबाव से बचा जाना चाहिए।

यह पहली बार है जब भारतीय स्त्रियों ने क्रिकेट की विश्व-प्रतियोगिता में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में 2 नवंबर को खेली गई वन डे क्रिकेट प्रतियोगिता स्त्री-क्रिकेट के दृष्टिकोण से एक विहंगम प्रतियोगिता थी। विश्व में जब से स्त्री-क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर रविवार तक कभी भी महिलाओं की क्रिकेट प्रतिस्पर्द्धा देखने स्टेडियम में इतनी अधिक संख्या में दर्शक एकत्रित नहीं हुए। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इतना ही नहीं, जियो हॉटस्टार पर उक्त प्रतियोगिता का सजीव प्रसारण विजयी क्षण तक विश्वभर के 30 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। रविवार को ही स्त्री-क्रिकेट की इस निर्णायक प्रतियोगिता के आरंभ होने से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के होबॉर्ट में भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य टी-20 की एक पुरुष-क्रिकेट प्रतियोगिता भी खेली गई थी। हालांकि इस प्रतिस्पर्द्धा में भी भारत की विजय हुई, किंतु जियो हॉटस्टार पर इसकी प्रसारणावधि में इसे देखने वाले मात्र 16 करोड़ दर्शक ही थे। अब जब स्त्री-क्रिकेट में भारत विश्वविजेता बन चुका है तथा स्त्रियों की क्रिकेट क्रीड़ा देखने प्रत्यक्ष रूप में स्टेडियम पर व अप्रत्यक्ष रूप में सजीव प्रसारण मंचों पर देशी-विदेशी दर्शकों की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है, तो विश्वविजयी प्रतियोगिता में भारतीय स्त्रियों के सामूहिक एवं व्यक्तिगत योगदान पर विचार-विमर्श अनिवार्य हो जाता है।

चिरप्रतीक्षित स्त्री विश्व क्रिकेट की अंतिम व निर्णायक प्रतिस्पर्द्धा निर्धारित समय पर आरंभ नहीं हो सकी थी। दक्षिण भारत में परिव्याप्त मोंथा चक्रवात के प्रभाव में महाराष्ट्र भी था और प्रतियोगिता आरंभ होने से ठीक पूर्व नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम पर भी वर्षा होने लगी थी। इस कारणवश प्रतियोगिता विलंब से आरंभ हुई। यह आनंद का समाचार था कि प्रतियोगिता में दोनों प्रतियोगी दल निर्धारित पचास-पचास ओवर की ही क्रीड़ा करेंगे। टॉस दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित भारतीय टीम ने हालांकि संतुलित और धैर्यपूर्ण ढंग से बल्लेबाजी आरंभ की और भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने क्रमशः 87 व 45 रन बनाए। जैसे-जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती रही भारतीयों द्वारा छोटी-छोटी साझेदारियां बनती रही और नियमित अंतराल में बल्लेबाज आउट भी होती रहीं। इस निर्णायक प्रतिस्पर्द्धा से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई स्पर्द्धा में अग्र बल्ला प्रदर्शनकारी शतकधारी जेमिमा रोड्रिग्स और दल नायिका हरमनप्रीत कौर क्रमशः 24 व 20 रन बनाकर बाहर हो गईं। इसके बाद दीप्ति शर्मा (58 गेंद पर 58 रन) ने पहले अमनजौत कौर (12) और फिर ऋचा घोष (26 गेंद पर 34 रन) के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करके भारत के रन 298 तक पहुंचाए। जहां भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा एवं ऋचा घोष ने कम गेंद खेलकर उपयोगी रन बनाए, वहीं हरमनप्रीत कौर एवं स्मृति मंधाना ने क्रमशः कप्तान व उप कप्तान के रूप में अधिक गेंदें व्यर्थ करके कम रन बनाए। इस कारण भारत की रन गति में होती रही एक नियमित वृद्धि बार-बार रुकती रही। यदि हरमनप्रीत एवं

स्मृति ने अपनी खेली हुई गेंदों के बराबर भी रन बनाए होते तो भारत के कुल रन अंक सवा तीन सौ के निकट होते। यदि भारत इस प्रतिस्पर्द्धा में पराजित होता तो पराजय के दो अग्रणी दोषियों के रूप में हरमनप्रीत एवं स्मृति तथा द्वितीयक दोषी के रूप में राधा यादव की गणना अवश्य होती।

भारतीय रन 298 को पार करने मैदान में उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम ने भी मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अफ्रीकी दल नायिका लौरा वोल्वार्ड एवं ताजमिन ब्रिट्स ने उल्लेखनीय पारी खेली। लौरा ने प्रतिस्पर्द्धा के लगभग अंत तक संघर्ष किया कप्तान के रूप में अपेक्षित प्रदर्शन करते हुए 101 रन बनाए। शतक बनाने में उन्होंने सौ से कम गेंदें खेलीं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ब्रिट्स (23), सुने लुस (25) एवं एनेरी डर्कसन (35) ही दहाई के अंक में रन बना सकीं। गेंदबाजी में सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए। उन्होंने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके बाद शेफाल वर्मा ने 7 ओवर में 36 रन देकर 2 महत्त्वपूर्ण विकेट लिए। भारत की ओर से तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने हालांकि कोई विकेट नहीं लिया, किंतु उनकी गेंदबाजी ने सबसे कम रन दिए। उन्होंने 8 ओवर में मात्र 28 रन दिए। इसके बाद श्री चरणी भी अपने सातवें ओवर तक अति मितव्ययी गेंदें फेंक रही थीं। यदि उनके अंतिम दो ओवरों में एनेरी डर्कसन चौके-छक्के नहीं लगाती तो वे भी अपने कुल 9 ओवरों में 48 रन न देकर रेणुका के बराबर ही मितव्ययी होतीं। चरणी ने एक विकेट भी लिया। गेंदबाजी में अमनजोत कौर एवं राधा यादव का प्रदर्शन निराशाजनक था। क्रांति गौड मात्र 3 ओवर फेंक पाई, जिसमें उन्होंने 16 रन दिए। पहले 87 रन बनाने और बाद में कम रन देकर 2 विकेट प्राप्त करनेवाली शेफाली वर्मा को निर्णायक प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ध्यान रहे कि भारतीय प्रथम बल्लाधारकों में से एक प्रतिका रावल के पैर में गंभीर चोट लगने के कारण उप-निर्णायक एवं निर्णायक प्रतियोगिता में ही शेफाली वर्मा को आपातिक स्थिति में भारतीय स्त्री क्रिकेट दल में सम्मिलित किया गया था। स्त्री क्रिकेट की इस विश्व प्रतियोगिता में पूरी शृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दीप्ति शर्मा का चयन किया गया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फिर क्षेत्ररक्षण तीनों ही स्तर पर उनके परिणामोन्मुखी प्रदर्शन ने उन्हें शृंखला की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव प्रदान किया। यदि विश्व प्रतियोगिता के निर्णायक संघर्ष में प्राप्त सफलता के सबसे बड़े कारण को देखें तो यह भारतीय दल का सामूहिक चहुंदिश प्रदर्शन था, इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा क्षेत्ररक्षण। बल्लेबाजी में हरमनप्रीत, स्मृति, अमनज्योत, जेमिमा एवं राधा ने यद्यपि अच्दा प्रदर्शन नहीं किया, किंतु क्षेत्ररक्षण में सभी का योगदान उल्लेखनीय रहा। इसी प्रकार गेंदबाजी में जहां अमनज्योत एवं राधा का प्रदर्शन विफलता का कारक हो सकता था, वहीं क्षेत्ररक्षण में दोनों का प्रदर्शन अति परिश्रमपूर्ण रहा। इसी दल भावना की शक्ति द्वारा अंततः भारत को स्त्री विश्व क्रिकेट की निर्णायक प्रतियोगिता में विजय प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि पूरे 52 वर्ष बाद प्राप्त हुई है। यह भारतीय स्त्री क्रिकेट के लिए एक अविस्मरणीय समय है। किंतु इस उपलब्धि की अतिप्रसन्नता एवं आत्ममुग्धता खिलाड़ियों पर हावी नहीं होनी चाहिए। संभवतः यही कारण रहा था अथवा निर्णायक प्रतियोगिता का दबाव-तनाव जो हरमनप्रीत एवं स्मृति ने अति सुरक्षात्मक होकर दब्बू बनकर बल्लाकारिता की तथा परिणामस्वरूप दोनों देर तक भी नहीं खेलीं एवं अधिक गेंदें व्यय करके कम रन बनाकर बाहर हो गईं। भविष्य में इससे बचा जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

वायु प्रदूषण
डॉ. नीलू तिवारी

# भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी हरित ऊर्जा

हाल ही में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 14 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विकास की कीमत प्रदूषण होनी चाहिए? क्या आधुनिक भारत प्रदूषण की छाया में ही आगे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों का उत्तर खोजते हुए भारत ने एक नई दिशा अपनाई हरित ऊर्जा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवम्बर 2021 को ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–सीओपी26 के दौरान जब पंचामृत संकल्प की घोषणा के तहत वर्ष 2070 तक "नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन" लक्ष्य रखा, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि भारत विकास करेगा पर प्रकृति के साथ। इसी दृष्टिकोण ने भारत को जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) पर निर्भरता से मुक्त कर हरित ऊर्जा की राह पर आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार की प्रमुख पहल प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना ने आम जनता को इस परिवर्तन का सहभागी बनाया है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाए हैं। नतीजा यह है कि अब वे हर महीने 200-300 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गृहिणी बताती हैं कि पहले हर महीने बिजली का बिल देना पड़ता था। अब सौर पैनल से घर चल रहा है और 1500 रुपये की बचत भी हो रही है। यह उदाहरण बताता है कि हरित ऊर्जा केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी वरदान है। सौर ऊर्जा केवल घरों तक सीमित नहीं रही। अब गांवों में स्कूल, पंचायत भवन और छोटे उद्योग भी सौर बिजली से चल रहे हैं। राजस्थान का भड़ला सौर पार्क, जो 14,000 एकड़ में फैला है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है।

हरित ऊर्जा का दूसरा मजबूत स्तंभ है पवन ऊर्जा। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य अब देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा हवा से पैदा कर रहे हैं। 2025 में शुरू हुई ऑफशोर विंड एनर्जी योजना के तहत समुद्र तटों पर विशाल टरबाइन लगाए गए हैं, जिनसे 15 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है, बल्कि इससे तटीय इलाकों में रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं, भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिए विश्व को चौंका दिया है। 2030 तक भारत पांच मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में बड़े संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। इसका उपयोग भविष्य में रेलवे, उद्योग और जहाजरानी में किया जाएगा। यह पहल न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगी, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बनाएगी।

हरित ऊर्जा का एक और बड़ा अध्याय है इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ताकि प्रदूषण घटे और विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो। पहले जहां पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा केवल 1.5 प्रतिशत थी, वहीं अब यह 12 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गन्ना किसान अब अपनी फसलों से ईंधन तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महिला किसान बताती हैं कि इथेनॉल उत्पादन के लिए उनका गन्ना अब बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है और उन्हें पहले से अधिक आमदनी हो रही है। यह उदाहरण दर्शाता है कि हरित ऊर्जा ग्रामीण भारत में भी आर्थिक क्रांति ला रही है। अगर किसानों की बात करें तो मोदी सरकार की कुसुम योजना ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है। अब तक देशभर में 35 लाख से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं। पहले जो किसान बिजली कटौती और डीजल खर्च से परेशान थे, अब वे सौर ऊर्जा से दिन-रात खेती कर पा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में किसान बताते हैं कि पहले महीने में 2000 रुपये का डीजल खर्च होता था, अब वही पैसा बच रहा है और सौर पंप से बिना रुकावट सिंचाई हो रही है। यह योजना सीधे किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर यह सिद्ध किया है कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं। भारत की यह पहल इस दृष्टि से भी प्रासंगिक है कि यह देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर कर रही है। इन उपायों से भारत स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टिकाऊ ऊर्जा के भविष्य की ओर और तेजी से बढ़ सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

## जानिए कैसे चेतना को विस्तृत करता है योग?

संकलित
दर्शन

योग के आठ अंग हैं और उनमें से मात्र एक अंग है शारीरिक मुद्राएं या आसन। योग मात्र व्यायाम नहीं है, इसमें मुख्य बात मन की समरसता को बनाए रखना है। जब आप कोई भी कार्य सजगता से करते हैं, तब आप इस बात के प्रति सजग होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यही आपको योगी बनाता है। योग के प्रतिपादक पतंजलि ने बताया है कि योग का उद्देश्य दुख को आने से पहले ही दूर कर देना है। लालच, क्रोध, जलन, घृणा, निराशा आदि नकारात्मक भावनाओं को योग से मिटाया जा सकता है। जब आप खुश होते हैं, तब आप अपने भीतर एक विस्तार की भावना का अनुभव करते हैं। विफलता या अपमान की स्थिति में लगता है कि हमारे भीतर कुछ सिकुड़ गया है। इस पर ध्यान देना ही योग है, जिसका हमारे खुश हो जाने पर विस्तार होता है और जो हमारे दुखी हो जाने पर सिकुड़ जाता है। मन की इस स्थिति को परिवर्तित करने का रहस्य योग में है। यह आपको स्वतंत्र बनाता है। अपनी ही भावनाओं के द्वारा पीड़ित होने के बजाय आप जिस समय जैसा महसूस करना चाहते हैं, योग उसके लिए आपको शक्ति प्रदान करता है। योग निश्चित रूप से आपको अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि योग से आपके भीतर ऊर्जा एवं उत्साह उत्पन्न होता है। आप तब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जब आप थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं। यदि आपने अपनी थकान और तनाव को संभाल लिया, तब आप निश्चित रूप से अधिक जिम्मेदारी उठाएंगे और आपके भीतर हल्कापन भी बना रहेगा।

## धैर्य से काम लेने में ही समझदारी

संकलित
प्रेरणा

एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफी देर हो गई थी। बुद्ध जी को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होनें अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरु जी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा, ये सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी इसीलिए उन्होनें फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए। शिष्य बोला की प्रभु वहां नदी का पानी वास्तव में गंदा था लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया। और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी उपर आ गया। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आते हैं जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देख कर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते।

## गुलदाउदी की बहार

श्रीनगर में गुलदाउदी गार्डन में घूमते हुए लोग, जिसे बाग-ए-गुल-ए-दाऊद के नाम से भी जाना जाता है।

## आज की पाती

### धन और अन्न शादियों में बर्बाद न करें

त्योहारों के साथ-साथ अब शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। हमारे देश में शादी समारोह में भी फिजूलखर्ची लोक दिखावे के लिए होने लगी है। लोक दिखावे के लिए लोग अपने पैर चादर से बाहर भी पसार देते हैं। कुछ समय पहले शादियों में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी कृष्णा तीरथ ने सुझाव दिया था कि उनके अनुसार चाय और नमकीन में भी फेरे लेकर विवाह की रस्म निभाई जा सकती है। इसके लिए लाखों रुपए फूंकने की क्या जरूरत है। जो कि बहुत ही सराहनीय है। अमीर लोगों को तो लाखों रुपए खर्च करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब अगर विवाह समारोहों में लाखों खर्चा करने लग पड़ेगा तो वो सारी जिंदगी गरीबी की दलदल में धंस जाएगा। *- विशेष अग्रवाल, रायगढ़*

## ट्रेंड

### हार्दिक बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को विश्व कप जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। वे अच्छा खेल रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है।
-द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

### तीन बंदर

आज इंडिया गठबंधन के तीन और बंदर आ गए हैं- पप्पू, टप्पू और अप्पू... पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। इसके बावजूद ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इन पर भरोसा करेगी।
-योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी

### ऐतिहासिक जीत

यह एक जीत ऐतिहासिक है, भारत के लिए और भारत की औरतों के लिए। आज हमने अपनी महिला क्रिकेट टीम के लिए वही जोश, वही आंसू और वही जश्न मनाया, जो हम अपनी पुरुष टीम के लिए मनाते आए हैं। 60 मिलियन से ज्यादा लोगों ने मैच देखा, एक देश, एक इमोशन, एक जज्बा।
-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

### अदम्य इच्छाशक्ति

भारतपुत्रियों ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, अविचल धैर्य और अविराम पुरुषार्थ से वह विजयगाथा अंकित की है, जो लंबे समय तक भारत की स्मृति में अक्षय कीर्तिलेख रूप में प्रतिष्ठित रहेगी।
-कुमार विश्वास, हिन्दी कवि

## करंट अफेयर

### हेगसेथ ने दक्षिण व उत्तर कोरिया का किया दौरा

अमेरिक के रक्षामंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को उत्तर और दक्षिण कोरिया के सीमा पर स्थित असैन्यीकृत क्षेत्र का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा वार्ता के लिए अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया की दो दिवसीय यात्रा की भी शुरुआत की। हेगसेथ और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक को निगरानी चौकी में सैन्य अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी दी। यह चौकी सैन्य सीमांकन रेखा के पास है, जहां का दौरा अमेरिका के कई राष्ट्रपति कर चुके हैं जिनमें 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। हेगसेथ और बैक ने पनमुनजोम सीमावर्ती गांव का भी दौरा किया, जहां 1950-53 के कोरियाई युद्ध को रोकने के लिए एक युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैक के मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे ने मित्र देशों के बीच 'मज़बूत संयुक्त रक्षा रुख और घनिष्ठ समन्वय की पुष्टि की'। दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को बताया कि देश के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल जिन योंग-सुंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जनरल डैन केन ने प्योंगटेक में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे के ऊपर दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी एफ-16 लड़ाकू विमानों के 'फ्लाईपास्ट' का निरीक्षण किया।

## ऑफ बीट

### महिलाएं घर में 427 अरब डॉलर का अवैतनिक श्रम करती है

ऑस्ट्रेलिया में लोग खाना पकाने, घर की साफ-सफाई और परिवार के सदस्यों की देखभाल जैसे अवैतनिक कार्यों में हर साल हजारों घंटे बिता देते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बांधे रखने वाला एक अहम सूत्र है। लेकिन उन्हें आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों में कोई मान्यता नहीं दी जाती। नया अध्ययन अर्थव्यवस्था में इस अवैतनिक श्रम के योगदान पर प्रकाश डालता है, जिसे 688 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास आंका गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है और इसमें अधिकांश योगदान महिलाओं का है। रोजाना औसतन 3 घंटे 56 मिनट घरेलू कामों में बीतते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाएं रोजाना औसतन 3 घंटे और 56 मिनट का समय अवैतनिक काम एवं देखभाल में बिता देती हैं, जो प्रति सप्ताह 771 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं, पुरुष अवैतनिक काम एवं देखभाल पर रोजाना औसतन 2 घंटे और 28 मिनट का समय खर्च करते हैं, जो प्रति सप्ताह 493 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। आबादी के हिसाब से देखें तो महिलाएं हर साल औसतन 427.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर अवैतनिक श्रम करती हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 261 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

## अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दैनिक जागरण
सौंदर्य दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं

# लड़कियों ने किया कमाल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीत कर केवल इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के साथ देश की लाखों लड़कियों के लिए खेलों और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खोलने का भी काम किया। इस जीत ने फिर यह सिद्ध किया कि लड़कियां लड़कों की ही तरह हर क्षेत्र में चुनौतियों से पार पा सकती हैं और अपने हौसले से देश-दुनिया को चमत्कृत कर सकती हैं। यह जीत लड़कियों के प्रति हमारे पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सिद्ध होनी चाहिए। यह बदलाव उन्हें आगे बढ़ने और खुद को साबित करने के मौके तो देगा ही, भारतीय समाज में खेलों की महत्ता भी बढ़ाएगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज के युग में खेल के मैदान में अर्जित की जाने वाली सफलताएं देश विशेष की प्रगति का सूचक हैं। महिला विश्व कप की जीत इसलिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पहले किसी अंतरराष्ट्रीय खेल में भारतीय लड़कियों की टीम ने कोई खिताब नहीं जीता था। यह जीत इसलिए भी विशेष है, क्योंकि महिला विश्व कप क्रिकेट में आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का दबदबा था। इसके पहले के सभी महिला विश्व कप क्रिकेट आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के नाम रहे। एक तरह से भारतीय टीम ने अपनी जीत से विकासशील देशों की महिला क्रिकेट टीमों को भी प्रेरणा प्रदान करने का काम किया।

महिला वनडे विश्व कप जीत की प्रतीक्षा किस बेसब्री से की जा रही थी, इसका पता फाइनल मुकाबले को लेकर बने माहौल से भी चलता है और स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भीड़ से भी। यह माहौल और भीड़ इस कारण थी कि खेल प्रेमियों को कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी उत्साही टोली पर भरोसा था। इस भरोसे का आधार उनके खेल में आए सुधार के साथ यह भी था कि भारतीय महिला टीम दो बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। यह स्वाभाविक है कि इस जीत को 1983 के वनडे विश्व कप में कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम की ओर से हासिल की गई खिताबी जीत के समकक्ष बताया जा रहा है। उस जीत ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया था। महिला क्रिकेट के साथ ऐसा होना और आसान है, क्योंकि तब के मुकाबले आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम है। वास्तव में क्रिकेट बोर्ड की इस आर्थिक सक्षमता ने ही महिला क्रिकेटरों के विश्व विजयी अभियान को सुगम बनाया। बीसीसीआइ ने 2006 में महिला क्रिकेट की कमान अपने हाथ में ली थी। यदि उसने दो दशक के अंदर ही महिला क्रिकेटरों को शिखर पर पहुंचा दिया तो इसका कारण है उनके प्रोत्साहन के लिए उनकी पुरस्कार राशि पुरुषों के समान करना, उन्हें उनके जैसे संसाधन उपलब्ध कराना और महिला प्रीमियर लीग शुरू करना।

# नए भर्ती नियम

मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर वर्ष 2047 का विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्ष 2047 तक एक करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले भी सरकारी क्षेत्र में आगामी तीन साल में दो लाख पदों पर भर्ती की बात कही जा चुकी है। पद हैं और नए भी सृजित किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या हर विभाग के लिए अलग परीक्षा और अलग नियम हैं। परीक्षाओं की संख्या सीमित करने के साथ ही शासकीय सेवा में भर्ती संबंधी नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अगले वर्ष से परीक्षा संशोधित नियमों के तहत होगी। दरअसल, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और उसी अनुरूप सभी चीजें संचालित होनी चाहिए। बीते कई वर्षों में महिला एवं ओबीसी आरक्षण की वजह से भर्ती नियमों में सामने आई विसंगति की वजह से कई परीक्षार्थियों ने कोर्ट में याचिकाएं लगा दीं और परीक्षाओं में विलंब शुरू हो गया। इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मामला उलझ गया इसलिए नए नियमों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। राज्य सरकार ने सभी विभागों में भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा का निर्णय ले लिया है इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी नए नियम आवश्यक हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनमें सभी विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा।

> नए नियमों की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही थी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मामला उलझ गया था

# फिर संघ के पीछे पड़ी कांग्रेस

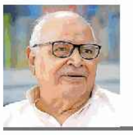

हृदयनारायण दीक्षित

**सेक्युलर दल हिंदुत्व और संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, पर उनके पास न तो अल्पसंख्यक की परिभाषा है और न ही सांप्रदायिकता की**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस फिर आमने-सामने हैं। ताजा विवाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि निजी संगठन, व्यक्तियों के समूह और संघ के लिए सरकारी परिसर के उपयोग हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने सनातन परंपरा पर हमला बोलते हुए यह भी कहा था, 'अपनी संगति सही रखें। सनातनियों और संघियों से दूर रहें।' उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने पर वे संघ को प्रतिबंधित कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी संघ पर प्रतिबंध की जरूरत जताई है। उनके बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने भी संघ पर हमला बोला। नियम अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन से संबंध नहीं रख सकता और उसकी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट (1964) के अधीन कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध था। बाद में इसे संशोधित किया गया। अब इस सूची में संघ का नाम नहीं है। कांग्रेस द्वारा संघ की गतिविधियों को बाधित करने के प्रयास पहले भी हुए हैं। ऐसा प्रयास भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14) के अधीन विचार अभिव्यक्ति की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भारतीय संस्कृति आधारित राष्ट्रवादी समाज बनाना उसकी प्राथमिकता है। हिंदुत्व संघ का अधिष्ठान है। संघ ने इस देश की राजनीति, संस्कृति में आधारभूत सकारात्मक हस्तक्षेप किया है। 1925 में जन्मा संघ सौ बरस का हो गया है। उससे ईर्ष्या स्वाभाविक है। संघ विरोधी राजनीतिक विचारधारा सेक्युलरवाद के नाम पर अल्पसंख्यकवाद चलाती रहती है। सेक्युलरवाद ने विचारधाराविहीन समाज बनाने का काम किया है, पर सेक्युलरिज्म तो आयातित और एक विजातीय विचार है। संघ का मूल आधार हिंदू राष्ट्रवाद है। सेक्युलर दल हिंदुत्व और संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, पर उनके पास न तो अल्पसंख्यक की परिभाषा है और न ही सांप्रदायिकता की। अल्पसंख्यकवाद ऐसी राजनीति का भयानक प्रेत है। देश में लगभग 14.2 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इसके बावजूद सेक्युलर राजनीति उन्हें अल्पसंख्यक बताती है। अल्पसंख्यक की भी कोई परिभाषा नहीं है। राजनीति का मजहबीकरण देश के लिए घातक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के समय कहा था कि पहले सांप्रदायिकता की परिभाषा कीजिए। उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया।

अवधेश राजपूत

सेक्युलरवाद की दृष्टि में संघ सांप्रदायिक है और इस्लामी एवं ईसाई विश्वास सेक्युलर हैं। यह दोहरापन है। कांग्रेस को संघ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे इंडियन मुस्लिम लीग से कोई समस्या नहीं। संघ से खार खाए कथित सेक्युलर नेता अक्सर कोप में आ जाते हैं और उसके खात्मे का एलान करते रहते हैं। कुछ समय पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने संघ के पथ संचलन कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। तर्क दिए गए कि पथ संचलन के कार्यक्रम के रास्ते में मस्जिद और चर्च पड़ते हैं। इसलिए अनुमति देना संभव नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि संघ को अनुमति देने से मना करने का फैसला संविधान के विरुद्ध है और लोकतंत्र के लिए असंगत भी। सरकार का निर्णय मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। संघ ने गांधी जयंती और स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम आयोजन की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनुमति नहीं दी। संघ ने तब न्यायालय की शरण ली। संघ के कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश बंगाल में भी होती रही है।

संघ पर पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी, 1948 को लगाया। आरोप लगाया गया कि संघ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है। कहीं कोई साक्ष्य नहीं थे, फिर भी यह प्रतिबंध एक वर्ष तक रहा और 11 जुलाई, 1949 को हटा दिया गया। संघ आगे बढ़ता रहा। वह सेक्युलरपंथियों की आंख की किरकिरी रहा। आपातकाल (1975-1977) में हिंसक गतिविधियों के आरोप के साथ संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। आपातकाल में सभी दलों के नेता जेलों में थे। तकलीफ सभी दलों को थी, पर अकेले संघ ने ही विरोध स्वरूप भूमिगत आंदोलन चलाया। सरकार ने संघ को लोकतंत्र विरोधी और विघटनकारी कह प्रतिबंधित कर दिया। 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई तो प्रतिबंध हटाया गया। अयोध्या आंदोलन से तमतमाए केंद्र ने 6 दिसंबर, 1992 को संघ पर प्रतिबंध लगाया। आरोप सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पहुंचाने और हिंसा फैलाने का लगाया गया। संघ की भूमिका सिद्ध नहीं हुई। 1993 में प्रतिबंध हटाया गया। संघ ने विचार निष्ठा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन की हैसियत पाई है। यह तथ्य छद्म सेक्युलरवादियों को हजम नहीं होता।

हिंदुत्व सर्व समावेशी विचार है। सुदीर्घ काल से चली आ रही संस्कृति और उस पर आधारित जीवन पद्धति का नाम है हिंदुत्व। संघ पर पाबंदी लगाने को आतुर सेक्युलरपंथी हिंदुत्व की बढ़त से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी संगठन की गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोका। संघ बनाम केके धवन मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1970 में फैसला दिया था कि आरएसएस की गतिविधियां राजनीतिक नहीं हैं। केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि कर्मचारी संघ से जुड़ सकता है। यह सब जानते हुए भी सेक्युलरपंथी संघ से निपटने की बातें करते हैं। कर्मचारी, अधिकारी भी नागरिक हैं। नागरिक होने के कारण उन्हें किसी संगठन के आयोजन में शामिल होने, उत्सव मनाने और सांस्कृतिक जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। संघ के समर्थकों को इससे वंचित करना राजनीतिक असहिष्णुता ही है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं)

response@jagran.com

# प्रदर्शन का जरिया बनी राजनीति

ब्रजेश कुमार तिवारी

**बड़े काफिले, भव्य मंच, चौबीसों घंटे ब्रांडिंग और डिजिटल विज्ञापनबाजी अब राजनीति का केंद्रीय आधार बन चुके हैं**

महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण आदि ने भारतीय राजनीति में सरल जीवन, सादगी, संयम और उच्च विचार की भावना को बढ़ावा दिया, लेकिन बीते दो-तीन दशकों में भारतीय लोकतंत्र का मूल उद्देश्य प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और लोकसेवा की जगह बाहरी आडंबर, चमक-दमक और महंगे प्रचार तंत्र की ओर झुका हुआ दिखता है। पहले नेता साधारण कारों से यात्रा करते थे, आज उनके काफिले में 40-50 महंगी गाड़ियां होना सामान्य है। नेताओं के साथ दौड़ते वाहनों की कतारें, हूटर, कमांडो स्टाइल सुरक्षा और समर्थकों के बीच शक्ति-प्रदर्शन का माहौल अपने आप में नई तरह की राजनीति का संदेश देता है। राजनीति अब विचार, नीति और काम की जगह दिखावे की भाषा बोल रही है। यह दृश्य अब आम हो गया है, पर क्या यह लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है या एक नई राजनीति की पहचान है, जहां सत्ता प्रदर्शन का माध्यम बन गई है?

इन दिनों बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार के नाम पर पैसे और प्रभाव का प्रदर्शन हो रहा है। इसे बाहुबली छवि वाले प्रत्याशी खास तौर पर कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए खड़े हुए कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 (32 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 354 उम्मीदवारों (27 प्रतिशत) ने बताया है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 241 विजेता सदस्यों में से 163 (68 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी। यह आंकड़ा 2015 में 58 प्रतिशत था। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के अनुसार लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 सदस्य ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 170 (31 प्रतिशत) के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विधानसभाओं का परिदृश्य भी अलग नहीं है। 28 राज्यों एवं तीन केंद्रशासित प्रदेशों के 4092 विधायकों में से 1861 (45 प्रतिशत) ने अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले

गाड़ियों से पटा पटना का गांधी मैदान। प्रेट्र

घोषित किए हैं। राजनीति का अपराधीकरण चुनाव दर चुनाव संस्थागत होता जा रहा है। वर्तमान लोकसभा में 93 प्रतिशत सदस्य करोड़पति हैं। 2009 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत, 2014 में 82 प्रतिशत और 2019 में 88 प्रतिशत था।

2024 में पुनः चुनाव लड़ रहे सांसदों की औसत परिसंपत्तियां पांच वर्षों में 43 प्रतिशत बढ़ीं। यह आंकड़ा बताता है कि सत्ता तक पहुंच आर्थिक पूंजी को तेजी प्रदान करती है। कारों के काफिले की लंबाई और 'शो-आफ' का बजट यहीं से आता है। यह बदलाव नई राजनीति की पहचान है, जहां नेता राजा जैसे दिखते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में भीड़ और जुलूस का परंपरागत स्थान रहा है, परंतु आज यह केवल समर्थन नहीं दर्शाता, बल्कि प्रभुत्व का संकेत देता है। गाड़ियों का लंबा काफिला यह 'आश्वस्ति' देता है कि नेता 'ताकतवर' है और 'अपने लोगों' की 'रक्षा' कर सकता है। यही मनोविज्ञान चुनाव-पूर्व डर और समर्पण पैदा करता है। इंटरनेट मीडिया के ड्रोन शाट्स और रील्स ने इसे और बढ़ाया है। काफिला जितना बड़ा और सिनेमाई दिखे, नेता को उतना ज्यादा बड़ा माना जाता है। बड़े काफिले, भव्य मंच, चौबीसों घंटे ब्रांडिंग, एआइ संचालित वीडियो और डिजिटल विज्ञापनबाजी अब राजनीति का केंद्रीय आधार बन चुके हैं। यह टिकट वितरण, उम्मीदवारी, नीति-निर्माण और मतदाता को भी प्रभावित करते हैं। इसी खिड़की से अपराध और धनशक्ति का गठजोड़ लोकतंत्र के भीतर न्यू नार्मल बनता दिख रहा है।

सेंटर फार मीडिया स्टडीज ने 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल अनुमानित खर्च एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक आंका। तब 9,000 करोड़ के आसपास की नकदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातुएं और 'फ्रीबीज' की जब्तियां हुई थीं। यह आंकड़ा प्रचार-युद्ध के शीर्ष-स्तर को परिभाषित करता है और यह भी इंगित करता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया भारत में विश्व की सबसे महंगी लोकतांत्रिक कवायदों में से एक बन चुकी है। सही मायने में यह चुनावी वित्त और आपराधिक नेटवर्क के गठजोड़ की गवाही है। जब चुनावी दान नीति-निर्माण को प्रभावित करे तो जनहित का स्थान 'रिटर्न-आन-इन्वेस्टमेंट' ले ही लेगा। नियमों को सख्ती से लागू करके इस संरचना को बदलना होगा। हमें राजनीति में गांधी, शास्त्री और पटेल जैसे आदर्शों की पुनर्स्थापना करनी होगी। दलों को टिकट बांटने में योग्यता, चरित्र और सेवा को तरजीह देनी चाहिए, न कि चमक-धमक को। जब अपराधी-नेटवर्क और धनशक्ति टिकट-वितरण का आधार बनेंगे तो ईमानदार कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर जांच-पड़ताल और तथ्यपरक पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा। यदि लोकतंत्र के आत्मा को बचाना चाहते हैं तो जनता को भी रवैया बदलना होगा। भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी नागरिक-भागीदारी का मंच है। यह मंच तभी सार्थक है जब नीति, प्रतिस्पर्धा, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, स्थानीय बुनियादी ढांचा केंद्र में हों। सादगी कोई सजावट की वस्तु नहीं, भारतीय राजनीति का आत्मा है। इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पार्टियों, संस्थाओं और सबसे बढ़कर मतदाताओं की है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### सच को स्वीकारें

जो मनोनुकूल नहीं है, जिसकी आशा नहीं थी, उससे सामना होने पर मनुष्य या तो दुखी हो जाता है अथवा उसे बदलने की ठान लेता है। इसे अहंकार वश पुरुषत्व या संघर्षशीलता का नाम दे दिया जाता है। ऐसे कई संघर्ष जीवन में चलते रहते हैं। कभी वह सफल हो जाता है तो हर्ष से भर जाता है। जब सफल नहीं होता तो कुंठा पैदा होती है। यह निश्चित है कि जीवन में सभी कुछ वैसा नहीं होता, जैसा मनुष्य चाहता है। कुछ न कुछ ऐसा आवश्य होता है, जो उसे अप्रिय है। इस तरह सारा जीवन अनुकूल और प्रतिकूल के मध्य डोलते रहने में बीत जाता है। कई बार तनिक भी प्रतिकूलता अधिक अनुकूलता के आनंद को नष्ट कर देती है।

अगला जीवन कैसा होगा? किसी को भी ज्ञात नहीं है। वर्तमान को ही स्वर्ग या नर्क बनाना है। यह स्वयं मनुष्य के हाथ में है। परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार रचा है जिसे देखने और अनुभव करने हेतु एक जीवन कम है। सुंदर प्रकृति, मनमोहक पशु-पक्षी जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। सुंदर फूल, फल, वनस्पतियां तृप्त कर देने वाली हैं। ऋतुओं का बदलना सदा उत्सुकता बनाए रखता है। निद्रा जैसा सुख काल कोई नहीं है, जो मनुष्य के तन की संरचना में ही परमात्मा ने निहित कर दिया है। इनके आगे मनुष्य की रुचियां, अरुचि अत्यंत लघु हैं। मनुष्य व्यापकता के स्थान पर लघुता से जुड़ कर अपने लिए दुख आमंत्रित करता है। जैसा सामने आ रहा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना एक साहसिक कार्य है। दुख को सुख में बदलना सीखें। दुखों का पोषण कायरता है। दुखों को नकार देना, प्रिय-अप्रिय के सोच का चक्रव्यूह, जो जीवन के सुख पर ग्रहण बना हुआ है, उसे भेद कर बाहर निकल आना वीरता है। युद्ध में लगे घाव नहीं देखे जाते, विजय का उत्सव मनाया जाता है। जो सुख हैं, उनकी तीव्र अनुभूति दुखों को नकार देती है। मनुष्य जीवन मिला है, जो सारे जीवों से श्रेष्ठ है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

# महिला क्रिकेट को मिली नई ऊर्जा

डा. मोनिका शर्मा

> पहले क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता था, पर अब बेटियों की बल्लेबाजी-गेंदबाजी भी घर-घर में चर्चा का विषय बनने लगी है

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आइसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह केवल एक खेल की जीत नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, समर्पण और समानता की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों की परिणति है। आज भारतीय महिला क्रिकेट जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसके पीछे न केवल खिलाड़ियों की मेहनत है, बल्कि वे नीतिगत फैसले भी हैं, जिन्होंने महिला खिलाड़ियों को सम्मान, आत्मविश्वास और समान अवसर प्रदान किए। बीते कुछ वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट ने अपनी पहचान विश्व स्तर पर मजबूत की है। 2017 के आइसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के बाद देश ने पहली बार महिला क्रिकेट की असली ताकत को महसूस किया। इसके बाद 2020 में टी-20 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय महिला टीम अब किसी भी सूरत में कमतर नहीं है। इस दौरान महिला खिलाड़ियों के प्रति जनमानस का नजरिया भी बदला- जहां पहले क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता था, वहीं अब बेटियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी घर-घर में चर्चा का विषय बनने लगी है।

महिला क्रिकेट की इस प्रगति के पीछे समान वेतन नीति का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लंबे समय तक एक ही खेल में महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में असमानता बनी रही, लेकिन वर्ष 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय अनुबंधित महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस लागू की। यह निर्णय न केवल आर्थिक समानता का प्रतीक था, बल्कि इसने महिला खिलाड़ियों के मनोबल को भी नई ऊंचाई दी। अब महिला खिलाड़ियों को यह अहसास हुआ कि उनकी मेहनत और प्रदर्शन को पुरुषों के समान मान्यता मिल रही है। इसी तरह, आइसीसी द्वारा 2023 में महिला और पुरुष विश्व कप विजेताओं के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा भी खेल जगत में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। इन निर्णयों का प्रभाव सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे महिला खिलाड़ियों के प्रति समर्थन का माहौल तैयार हुआ। युवा पीढ़ी में भी यह संदेश गया कि क्रिकेट केवल पुरुषों का नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर वाला खेल है। इन नीतिगत बदलावों का परिणाम आज विश्व के सामने है। यह इस बात का प्रमाण है कि समान अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती हैं।

विश्व कप की यह जीत केवल एक ट्राफी की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच के विजयगान की कहानी है जो समानता, सम्मान और आत्मविश्वास पर आधारित है। बीसीसीआइ और आइसीसी द्वारा लिए गए समान वेतन के निर्णयों ने महिला क्रिकेट को नया जीवन दिया है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

### मुस्लिम मतदाताओं के हित की बात

रामिश सिद्दीकी द्वारा लिखित आलेख 'वोट बैंक के दायरे से बाहर निकलें मुस्लिम' में जिन मुद्दों की चर्चा की गई है वे बेहद प्रासंगिक हैं। ये हरेक जाति, धर्म के मतदाताओं के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मुस्लिम मतदाताओं के लिए। दरअसल मतदाता होना नागरिकता का पर्याय है। नतीजतन सच्चा नागरिक कर्तव्य का निर्वहन तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखकर मतदान करे, जिसमें सभी देशवासियों का सम्यक हित निहित होता है। आजादी के बाद मुसलमानों में पृथकता, अलगाव का बीजारोपण उनको अल्पसंख्यक संबोधित करके किया गया। उनका इस तरह भयादोहन किया जाता रहा कि आम मुस्लिम मतदाता कभी स्वतंत्र नागरिक की हैसियत रखकर मतदान कर ही नहीं पाया। अगर ऐसा हुआ होता तो मुस्लिम मतदाता पंथनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता महसूस करता। वे यह देख पाने में सक्षम होते कि जिन नेताओं ने हमें बरगलाया, बहकाया वे ही अपने बच्चों के मामले में अलग रीति-नीति अपना रहे हैं। उनके बच्चे रोजी-रोजगार के लिए विदेश गए। मगर उनके इलाकों को आधुनिक अस्पताल, शिक्षण संस्थान से वंचित रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने विकास के लिए वोट करने के बजाय किसी को हराने के लिए किया। उनका यही दृष्टिकोण उन्हें वोटबैंक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हम सब 21वीं सदी के तकनीकी युग में जी रहे हैं। इस दौर में भी मुस्लिमों का किसी खास दल का वोटबैंक बना रहना समझ में नहीं आता। बदलते समय के अनुसार उन्हें अपने सोच भी बदलने चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, पटना

## मेलबाक्स

### हास्यास्पद निर्णय

संपादकीय 'मार्ग दुर्घटनाओं पर रोक' पढ़ा। देश में बढ़ते सड़क हादसे राष्ट्रीय चिंता का विषय है। भारत की सड़कों पर दुनिया के एक फीसद वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत का प्रथम स्थान पर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी एक हिस्से पर एक वर्ष में एक से अधिक दुर्घटनाओं के लिए ठेकेदारों को दंडित करने का निर्णय लेना हास्यास्पद प्रतीत होता है। मंत्रालय ने देश भर में 3500 से अधिक दुर्घटना बहुल क्षेत्र की पहचान की है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि निर्माण कार्य के दौरान इस तरह के दोषपूर्ण डिजाइनिंग और खराब इंजीनियरिंग की पहचान क्यों नहीं की गई एवं उनमें समय रहते सुधार क्यों नहीं किया गया? निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन के अधिकारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधे रखते हैं, और जब स्थिति चिंताजनक हो जाती है, तब विभाग की कुंभकर्णी निद्रा टूटती है। हमारे देश में निर्माण कार्यों में बढ़ती कमीशन खोरी की वजह से गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है, एवं निर्माण कार्य के दौरान संबंधित अधिकारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिसकी कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सड़कों के दोषपूर्ण डिजाइनिंग के लिए ठेकेदार के बजाय संबंधित अधिकारी को दंडित करने का प्रविधान होना चाहिए। आम जनता को खराब सड़कों के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी चाहिए।

himanshushekhar.mca@gmail.com

### नारी शक्ति की गाथा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। यह महज खिताब नहीं, नारी शक्ति की अमर गाथा है। अब गांव की गलियों में बैट नहीं, सपने लहराते हैं। लड़कियां कहती हैं-'हम विश्व चैंपियन बनेंगी।'' स्कूल की छतें गूंजती हैं-'हरमन बनना है, कोई और नहीं।'' बीसीसीआइ ने राशि बराबर की, कारपोरेट ने रोशनी दी, मीडिया ने आवाज बनाई, पर असली जादू मैदान पर हुआ, जहां बेटियों ने साबित किया कि जब नारी आगे बढ़ती है, राष्ट्र पीछे नहीं रहता। यह क्रांति है। यह घोषणा है- अब कोई क्षेत्र पुरुषों का नहीं, हर मैदान बेटियों का है। भारत की बेटियां अब सिर्फ खेलती नहीं, युग लिखती हैं। स्वर्ण अक्षरों में। हमेशा के लिए।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी (मप्र)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
********

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 221

# नीतिगत पारदर्शिता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अगस्त में मौद्रिक नीति ढांचे पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किए जाने के बाद इस विषय पर व्यापक बहस शुरू हो गई है। इस समाचार पत्र में भी उस पर चर्चा हुई। गत सप्ताह आयोजित बिज़नेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में भी इस पर बातचीत हुई जिसमें मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के दो पूर्व बाहरी तथा दो पूर्व आंतरिक सदस्य शामिल थे। पैनल ने इस बात पर सहमति जताई कि यह ढांचा भारत के लिए प्रभावी रहा है और फिलहाल इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य की समीक्षा मार्च 2026 तक होनी तय है। यद्यपि इस ढांचे के कुछ तकनीकी पहलुओं पर मामूली मतभेद हैं लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि 4 फीसदी का मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य (दो फीसदी कम या ज्यादा) को फिलहाल बरकरार रखा जाना चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि इस ढांचे का एक पहलू जिस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है वह भी इस पैनल परिचर्चा में सामने आया। आरबीआई अधिनियम कहता है कि जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहता है तो उसे केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है जिसमें उसे इस विफलता के कारण, उसके द्वारा उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय और वह समय सीमा बतानी होती है जिसके भीतर केंद्रीय बैंक प्रस्तावित नीतिगत कदमों के साथ उक्त लक्ष्य को हासिल करेगा। अगर लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति की दर तय सहनशील दायरे से बाहर बनी रहती है तो यह माना जाएगा कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने में नाकाम रहा है। बैंक ने 2022 में ऐसी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। उस समय लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति की दर दायरे के ऊपरी स्तर से ऊपर बनी रही थी। हालांकि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। कहा यह गया है कि कानून के मुताबिक ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कानूनन ऐसा कहना सही हो सकता है लेकिन देश के मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले लचीले ढांचे की भावना के मुताबिक यह सही नहीं है।

यह ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि मौद्रिक नीति में पारदर्शिता रहे। उदाहरण के लिए कानून कहता है कि एमपीसी की बैठक के कैलेंडर का प्रकाशन भी समय रहते किया जाए। एमपीसी का प्रस्ताव सार्वजनिक किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य ने कैसे मतदान किया, इसकी जानकारी भी शामिल होती है और बैठक की कार्यवाही का विवरण भी जारी किया जाता है। कानून के अनुसार, रिजर्व बैंक को हर छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, जिसमें मुद्रास्फीति के स्रोतों का विवरण और आने वाले तिमाहियों में इसकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान दिया जाता है। इसके अलावा, हर एमपीसी बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नरों और अन्य अधिकारियों के साथ मीडिया के सवालों का विस्तार से जवाब देते हैं, जो केवल एमपीसी के निर्णयों तक सीमित नहीं होते।

ऐसे में व्यापक तौर पर देखें तो यह उम्मीद करना उचित है कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने में नाकामी से संबंधित रिपोर्ट को रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कानून के मुताबिक रिजर्व बैंक को रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होती है। ऐसे में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। बीएफएसआई इनसाइट समिट के पैनल का भी यही मानना था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक जरूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक आशंका यह हो सकती है कि शायद इसमें ऐसी सूचनाएं हों जो वित्तीय बाजारों को प्रभावित करें। इसका जवाब यह हो सकता है कि रिजर्व बैंक का ढांचा वित्तीय बाजारों को समायोजन में मदद कर सकता है। अगर नीति-निर्माता इस नजरिये से सहमत नहीं हैं तो रिपोर्ट को एक अंतराल के बाद जारी किया जा सकता है। इससे नीतिगत चर्चाओं में मदद मिलेगी और मौद्रिक नीति को पारदर्शी बनाने का विचार मजबूत होगा।

अजय मोहंती

# ‘मेड इन इंडिया’ को नया रूप दे सकते हैं हस्तशिल्प

**भारत की विविधताओं से भरी और मजबूत हस्तशिल्प परंपरा ‘मेड इन इंडिया’ के विचार को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं अजित बालकृष्णन**

सन 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में जब मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कलकत्ता का विद्यार्थी था तब उस दौर के सभी कॉलेज जाने वाले बच्चों की तरह मैं भी सामाजिक रुझानों में गहरी रुचि रखता था। उस समय की बौद्धिक बहसों का सबसे बड़ा विषय जानते हैं क्या था? अपनी सांसें थाम कर सुनिए। वह विषय था- ‘परिवार नियोजन भारत की आर्थिक प्रगति की कुंजी है।’ उस दौर में लोक नीति की बहस में यह विषय उतना ही प्रमुख था जितना कि आज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का विषय है।

सन 1960 के दशक में भारत के परिवार नियोजन के नारे कुछ इस प्रकार थेः ‘हम दो, हमारे दो’ और ‘अगला बच्चा अभी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं।’ सड़कों के किनारे होर्डिंग पर, सिनेमा घरों में और अखबारों में भी ऐसे विज्ञापन आया करते थे। भारतीय डाक एवं तार विभाग ने परिवार नियोजन सप्ताह को लेकर 25 लाख डाक टिकट भी जारी किए थे।

संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यहां तक कि फोर्ड फाउंडेशन जैसे निजी परोपकारी संगठनों ने भारत में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में मदद की। रोज इस बारे में नई-नई खबरें आती थीं कि सरकार जन्म नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपना रही है। इसमें गर्भनिरोधक यंत्रों से लेकर देश में बनाया गया पहला कॉन्डोम निरोध तक शामिल थे। इनके केंद्र में प्रायः गरीब और वंचित वर्ग के लोग थे। उस समय कहा यह जाता था कि दुनिया की 14 फीसदी आबादी भारत में रहती है जबकि दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4 फीसदी हिस्सा भारत में है।

अब जब कभी मैं समकालीन सुर्खियों पर नजर डालता हूं तो मुस्कुरा उठता हूं। उदाहरण के लिए गत सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स की यह सुर्खी- ‘भारत का सबसे कीमती निर्यातः करोड़ो कामगार जो वैश्विक व्यापार के अवसरों को बढ़ा रहे हैं।’ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इससे कई पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल रहा है। और भी उल्लेखनीय बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक अब ‘जनसंख्या विस्फोट’ जैसे शब्द की जगह ‘जनांकिकीय लाभांश’ का इस्तेमाल करने लगे हैं।

जब मैंने अधिक सोच-विचार करने वाले मित्रों से इस अवधारणा के बारे में पूछा तो एक स्पष्टीकरण यह मिला कि इस समय भारत की अत्यधिक विविधता मसलन 22 आधिकारिक भाषाओं, हजारों बोलियों, संस्कृतियों और उपभोक्ता आदतों को अक्सर एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह व्यापार के लिए कोई एक बाजार प्रदान नहीं करता है बल्कि देश में कई छोटे-छोटे बाजार हैं। इसे समझना और इसे संचालित करना अत्यधिक जटिल और अक्षम माना जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और अत्यधिक व्यक्तिकरण पर आधारित होगी, वह इस विखंडन को लाभ के रूप में देखे क्योंकि जो कंपनी भारत में सामान बेचना सीख जाती है वह दुनिया के किसी भी बाजार में कामयाबी के लिए प्रशिक्षित हो जाती है। भारत की यह विविधता एआई मॉडल्स के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण मैदान है। ऐसा एआई जो भारत की समग्र संकृति में अनुवाद, ग्राहक सेवा और मार्केटिंग को कुशलता से संचालित कर सकता है, वह दुनिया का सबसे सबसे मजबूत और बेहतर एआई हो सकता है।

उसके बाद एक अन्य समकालीन चिंता है विदेशी पर्यवेक्षकों और भारत के अभिजात वर्ग के बीच यह चिंता कि एक ‘पिछड़ी’ हस्तशिल्प-आधारित अर्थव्यवस्था कहीं देश की प्रगति में बाधा न बन जाए। भारत का विशाल, खंडित और मुख्यतः असंगठित हस्तशिल्प क्षेत्र (जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है) अक्सर आर्थिक अक्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे औद्योगिकीकरण और स्वचालन में विफलता माना जाता है, जो लोगों को कम उत्पादकता वाली नौकरियों में फंसा देता है।

लेकिन एक ऐसे भविष्य में, जहां एआई और रोबोटिक्स लगभग शून्य लागत पर ‘संपूर्ण’ (खामी रहित) वस्तुएं बड़े पैमाने पर बना सकते हैं, क्या प्रामाणिकता, मूल स्रोत और मानवीय कौशल नई विलासिता बन सकते हैं? भारत, जो इस विशाल और अबाध हस्तशिल्प परंपरा को संरक्षित किए हुए है, संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी और विविध मानवीय कौशल संपदा का स्वामी बन सकता है।

इस विचार के मूल में वह है जिसे हम ‘स्वचालन का विरोधाभास’ कह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई एक बेहतरीन कुर्सी बना सकता है और एक रोबोट उसे 1,000 कुर्सी प्रति मिनट की दर से तैयार कर सकता है तो ‘बेहतरीन’ कुर्सी के दाम गिर जाते हैं क्योंकि सभी कुर्सियां एक जैसी नजर आने लगती हैं। इस नई दुनिया में दुर्लभ और सबसे मूल्यवान चीजें शायद किफायती नहीं रहेंगी। उनमें मानवीय स्पर्श का अभाव हो सकता है और उसके पीछे का सांस्कृतिक कथानक भी नदारद हो सकता है। किसी उत्पाद का मूल्य अब इस बात पर कम निर्भर करेगा कि वह क्या करता है और अधिक इस पर कि वह कैसे बना। उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी और किसी वास्तविक व्यक्ति व स्थान से जुड़ाव के लिए अतिरिक्त मूल्य चुकाएंगे। हम यह प्रवृत्ति पहले से ही लक्जरी बाजारों में देख रहे हैं (जैसे स्विस घड़ियां और महंगे बैग), लेकिन स्वचालन इसे एक सामान्य उपभोक्ता इच्छा बना सकता है।

इटली या जापान जैसे देशों में हस्तशिल्प की परंपरा है। वहीं भारत की खासियत है इतने बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प कलाओं की व्यापक जीवंतता। हमारे देश में लाखों कारीगर हजारों समुदायों में फैले हुए हैं। उनमें से हर एक की बुनाई, धातु-कला, नक्काशी, कढ़ाई आदि में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। ये कोई नए शौक नहीं हैं। नागालैंड के हाथ से बुने कपड़े हों या कश्मीर का पश्मीना। ये केवल एक उत्पाद भर नहीं हैं। यह एक सतत प्राचीन सांस्कृतिक कथा का हिस्सा हैं। यह प्रामाणिकता न तो नकली बनाई जा सकती है और न ही किसी कृत्रिम बुद्धिमता से इसे तैयार किया जा सकता है।

सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले ही वितरण की समस्या को हल कर रहे हैं। भविष्य में राजस्थान के किसी गांव में बैठा कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट और उच्च मूल्य वाले सामान को सीधे न्यूयॉर्क या टोक्यो के ऐसे ग्राहक को बेच सकेगा जो ऐसी चीजों का कद्रदान हो।

ऐसे में इस समय जिसे एक व्यापक कम तकनीक वाले बोझ के रूप में देखा जा रहा है वही चीज आगे चलकर उच्च मूल्य वाली निर्यातोन्मुखी वस्तु बन सकती है जो आर्थिक इंजन को गति प्रदान करे। देश में भविष्य का मेड इन इंडिया का टैग कम लागत वाले निर्माण से उच्च मूल्य वाली विशिष्ट वस्तुओं में बदल सकता है जो इंसानों द्वारा तैयार की जाती हों।

*(लेखक तकनीक और समाज के बीच के संपर्कों को समझने के लिए समर्पित हैं)*

# शहरों को नियंत्रित करने वाले निकाय कमजोर

**देश** भर में शहरी बुनियादी ढांचा लगातार दबाव में है। शहरों को कभी उत्पादकता का वाहक और बेहतर जीवन स्तर सुलभ कराने वाला माना जाता था लेकिन अब वे जलभराव, लंबे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से जूझ रहे हैं जिससे निवासियों के जीवन स्तर और समग्र उत्पादकता, दोनों को खतरा है। ये अंतर्निहित कमियां शहरी नियोजन की कमी की ओर इशारा करती हैं, जिसका दोष हमारे शहरों को संचालित करने वाले स्थानीय निकायों पर मढ़ा जाता है। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), जिन्हें शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, प्राथमिक शासी संस्थाएं हैं जो नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इनकी विफलता शहरी आबादी के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति को खराब कर सकती है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों का ऑडिट किया जिससे एक अधिक मौलिक प्रश्न उठा हैः क्या इन निकायों के पास प्रभावी ढंग से योजना बनाने की शक्ति है?

1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संशोधन की 12वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान ने इन निकायों को कुल 18 कार्य सौंपे, जिनमें शहरी नियोजन और भूमि उपयोग विनियमन से लेकर स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलिन बस्तियों में सुधार और गरीबी उन्मूलन जैसी सामाजिक एवं बुनियादी ढांचागत सेवाओं का रखरखाव शामिल है। हालांकि यह संशोधन 30 साल से भी पहले पेश किया गया था, लेकिन 2024 में 18 राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों में सीएजी द्वारा किए गए कामकाज के ऑडिट से यह एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि 74वें संशोधन के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

ऑडिट के अनुसार, औसतन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 में से केवल 4 शक्तियां ही शहरी स्थानीय निकायों के पूर्ण स्वायत्त नियंत्रण में हैं तथा अधिकांश कार्य राज्य सरकारों या अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के नियमित हस्तक्षेप से किए जाते हैं, जिसमें अक्सर स्थानीय निकायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

अमित कपूर

इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को अपने लिए भर्ती करने के निर्णय लेने से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों की जरूरत का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कर्मियों की आवश्यकताओं का कम आकलन होता है। उदाहरण के लिए शिमला नगर निगम जिसे 720 कर्मियों की आवश्यकता थी, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा केवल 20 नए पद स्वीकृत किए गए। स्वायत्तता की इस कमी के कारण न केवल स्वीकृत पदों की संख्या कम हो गई है, बल्कि 18 राज्यों में हर तीन में से एक पद रिक्त रह गया है, जिससे शहरी स्थानीय निकाय अपने कार्यों को ठीक से करने के लिए आवश्यक मानव संसाधनों से वंचित हो रहे हैं।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नए संस्थागत ढांचों के गठन का प्रावधान है, जैसे कि नियमित नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), और एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय नियोजन को सुगम बनाने के लिए जिला नियोजन समितियां (डीपीसी) और महानगर नियोजन समितियां (एमपीसी)। हालांकि, सीएजी ऑडिट से इन प्रावधानों की पूरी तरह उपेक्षा का पता चलता है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन 17 राज्यों के 2,625 शहरी स्थानीय निकायों का ऑडिट किया गया उनमें से 61 फीसदी या 1,600 में कोई निर्वाचित परिषद नहीं थी, और केवल पांच राज्यों में ही प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से महापौर की नियुक्ति हुई।

इस कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि वार्ड परिसीमन का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जिससे अक्सर नियमित नगर निगम चुनाव कराने में देरी होती है। निर्वाचित परिषद के अभाव में जनता शहरी स्थानीय निकायों को जवाबदेह नहीं बना पाती। रणनीतिक योजना का अभाव इन नगर निकायों को और कमजोर बनाता है। ऑडिट में शामिल केवल 10 राज्यों ने ही जिला स्थानीय निकायों (डीपीसी) का गठन किया था, और केवल तीन ने ही वार्षिक जिला योजनाएं तैयार की थीं। एमपीसी में भी यही रुझान देखने को मिलता है। एमपीसी बनाने के लिए अधिकृत नौ राज्यों में से केवल तीन ने ही ऐसा किया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल सात महानगरीय स्थानीय निकाय बन गए और केवल तीन ने ही योजनाएं विकसित की थीं।

वित्तीय पक्ष की बात करें तो राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) (राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय के बीच राजकोषीय हस्तांतरण के समन्वय के लिए जिम्मेदार) के गठन और एसएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन, दोनों में ही काफी देरी देखी गई। कई मामलों में, राज्य सरकारों ने एसएफसी द्वारा अनुशंसित पूरी राशि शहरी स्थानीय निकायों को जारी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप 15 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में औसतन 1,606 करोड़ रुपये की कमी आई।

अनुदानों के अलावा, संपत्ति कर जैसे कर इन निकायों के लिए धन के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। शहरी स्थानीय निकायों को ऐसे कर वसूलने का अधिकार है, लेकिन उनके पास संपत्ति कर की दर तय करने, मूल्यांकन करने या कर दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसकी वजह से कई संपत्ति कर अभी भी पहले से मौजूद दरों पर ही लगाए जा रहे हैं।

ये सभी कारक स्थानीय निकायों की वित्तीय तंगी की अहम वजह हैं। 11 राज्यों ने व्यय-राजस्व अंतर को 42 फीसदी के चौंका देने वाले स्तर पर पहुंचा दिया है। उपलब्ध धनराशि के बावजूद, स्थानीय निकाय विकास गतिविधियों को पर्याप्त रूप से सहयोग देने में असमर्थ हैं, क्योंकि केवल 29 फीसदी धनराशि ही विकास गतिविधियों के लिए आवंटित की जा रही है। ये सभी कारक शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को काफी हद तक कमजोर कर देते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जरूरतों का वित्तपोषण नहीं हो पा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों के वास्तविक सशक्तीकरण के बिना शहरी संकट को टाला नहीं जा सकता। राज्यों को इन निकायों को उनके कार्यों पर वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करना होगा और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त कर, 74वें संशोधन का दृढ़ता से पालन करना होगा। इसके लिए नियमित चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के वास्ते राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) को मजबूत करना होगा। इसके अलावा, डीपीसी और एमपीसी को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए, साथ ही राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन किया जाना चाहिए, और शहरी स्थानीय निकायों को कार्यबल भर्ती में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विकास योजनाएं नियमित रूप से बनाई जाएं, समय पर वित्त उपलब्ध हो, और स्थानीय निकायों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन हो। इन सुधारों के बिना, भारत के शहरी केंद्रों का क्षरण जारी रहेगा, और वे उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण जीवन के केंद्र बनने के अपने वादे से चूक जाएंगे।

*(लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के अध्यक्ष हैं। लेख में कार्तिक का भी योगदान है)*

## आपका पक्ष

### देश के सेवा क्षेत्र में भारी वृद्धि अच्छा संकेत

इस समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय ‘सेवा क्षेत्र का विरोधाभास’ निश्चित रूप से सेवा क्षेत्र के विकास के परिप्रेक्ष्य में सुधारवादी एवं सकारात्मक चर्चा करता है। विरोधाभास आंकड़ों में दिखाई दे सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार असंगठित हो सकता है। जब तक सेवा क्षेत्र अपने घर पर दस्तक नहीं देता, तब तक इसका वास्तविक रूप समझ नहीं आता और आंकड़ों में उलझकर रह जाता है। उदाहरण के लिए अर्बन क्लैप, ई-कॉमर्स की डिलिवरी व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन। पोर्टर जैसे बहुत से स्टार्टअप घर-घर सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे-जैसे सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, वैसे ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। बहुत-सी सेवाएं केवल महिलाओं के लिए हैं। अभी इस प्रकार की सेवाएं महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित हैं, धीरे-धीरे यह छोटे-छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचने की स्थिति में हैं। यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग मध्यम और कम आय वाले वर्ग से आते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से कम आय वर्ग को वंचित वर्ग या गरीब तबके से जोड़ना बंद करना चाहिए बल्कि सम्मानजनक दृष्टि से उनका ‘कौशल वर्ग’ जैसा वर्गीकरण करना श्रेयस्कर है। रोजगार सृजन का सबसे सशक्त साधन सेवा क्षेत्र है और रोजगार से उद्यमिता का मार्ग भी सेवा क्षेत्र से तय होता है।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

**देश में सेवा क्षेत्र को विस्तार देने के लिए इसका प्रसार महानगरों से इतर छोटे शहरों तथा कस्बों तक करना होगा**

### कृत्रिम बदलाव की पहचान वाले टूल विकसित किए जाएं

भारत में आईटी एक्ट और डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत डीपफेक एवं एआई के दुरुपयोग से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान और कठोर दंड की व्यवस्था होना चाहिए। एआई और डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूदा कानून इनका दुरुपयोग को रोकने के लिए अपर्याप्त है। एक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नैतिक एआई के विकास को बढ़ावा देने और एक सुरक्षित व भरोसेमंद डिजिटल वातावरण बनाया जाए। इसके लिए जागरूक नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। एक ऐसा डिटेक्शन टूल्स विकसित किया जाए, जिससे आम नागरिक वीडियो, ऑडियो या फोटो में मौजूद कृत्रिम बदलावों की पहचान कर सकें।

*विमलेश पगारिया, बदनावर*

### डीपफेक दुरुपयोग रोकने को डिजिटल साक्षरता बढ़ाएं

डीपफेक तकनीक का उपयोग मनोरंजन या शिक्षा में लाभकारी हो सकता है किंतु उसका दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग, अफवाह फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। जरूरी है कि तकनीकी कंपनिया ऐसी पहचान प्रणाली विकसित करें जो फर्जी सामग्री को स्वयं चिह्नित करें। नागरिकों को भी डिजिटल साक्षरता सिखाई जाना चाहिए ताकि सत्य और असत्य का वास्तविक मूल्यांकन हो सके। डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग सरकार के लिए एक जबरदस्त चुनौती है इसके विरुद्ध सरकार को कठोरतम दंड का प्रावधान करना चाहिए ।

*हार्दिक जैन, इंदौर*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

**अफगानिस्तान में आए 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को और अधिक आपूर्ति का आश्वासन भी दिया। उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 20 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए।**

https://t.me/AllNewsPaperPaid